Drishti IAS Presents...

PT SPRINT 2023

अर्थव्यवस्था

(मार्च 2022 – मार्च 2023)

Detailed Explanation

Drishti IAS, 641, Mukherjee Nagar, Opp. Signature View Apartment, New Delhi

Drishti IAS, 21 Pusa Road, Karol Bagh New Delhi - 05

Drishti IAS, Tashkent Marg, Civil Lines, Prayagraj, Uttar Pradesh

Drishti IAS, Tonk Road, Vasundhra Colony, Jaipur, Rajasthan

e-mail: englishsupport@groupdrishti.com, Website: www.drishtiias.com
Contact: 011430665089, 7669806814, 8010440440

उत्तर

1.

उत्तर: D

व्याख्या:

- परिचय:
  - NPCI भारत में सभी खुदरा भुगतान प्रणालियों के लिये एक एकीकृत संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में सुरक्षित और कुशल खुदरा भुगतान प्रणाली प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य देश में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है।
- स्थापना:
  - NPCI की स्थापना वर्ष 2008 में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) और भारतीय बैंक संघ (Indian Banks' Association- IBA) के मार्गदर्शन तथा समर्थन के तहत की गई थी।
- स्वामित्व:
  - NPCI एक गैर-लाभकारी कंपनी है और इसका स्वामित्व भारत में प्रमुख बैंकों के एक संघ द्वारा साझा किया जाता है।
- वस्तु एवं सेवाएँ:
  - यह एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT), तत्काल भुगतान सेवा (IMPS), भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS), रुपे कार्ड और अन्य सहित उत्पादों एवं सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है।
  - अत: विकल्प D उत्तर सही है।

2.

उत्तर: D

व्याख्या:

- स्टार्टअप के लिये फंड ऑफ फंड्स (FFS) योजना:
  - सरकार ने स्टार्टअप्स की फंडिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिये 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ FFS की स्थापना की है।
  - उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) इसकी निगरानी एजेंसी है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) FFS के लिये संचालन एजेंसी है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - यह न केवल शुरुआती चरण, विकास चरण में स्टार्टअप के लिये पूंजी उपलब्ध कराता है, बल्कि घरेलू पूंजी को बढ़ाने, विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी तथा नए उद्यम पूंजी कोष को प्रोत्साहित करने में भी उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

3.

उत्तर: B

व्याख्या:

- विश्व बैंक द्वारा "फॉलिंग लॉन्ग-टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स: ट्रेंड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड पॉलिसीज" (2020-2030) रिपोर्ट जारी की गई है।
- रिपोर्ट संभावित विकास के कई उपायों के व्यापक डेटाबेस का उपयोग करती है। यह संभावित विकास और उसके चालकों, 2020 के दशक में संभावित विकास और निवेश के लिये वैश्विक और क्षेत्रीय संभावनाओं और संभावित विकास को बढ़ाने के लिये नीतिगत विकल्पों की एक श्रृंखला की जाँच करता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- रिपोर्ट के अनुसार हालाँकि भारत में भी पिछले दो दशकों में अपनी विकास गति धीमी हुई है, लेकिन जब विकास दर की बात आती है तो यह वैश्विक नेता बने रहने की संभावना है। अत: कथन 2 सही है।

4.

उत्तर: A

व्याख्या:

- सरकार ने दिवाला और दिवालियापन से संबंधित सभी कानूनों को समेकित करने और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets- NPA), जो वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक गंभीर समस्या रही है, से निपटने के लिये IBC, 2016 को लागू किया।
- IBC में सभी व्यक्ति, कंपनियाँ, सीमित देयता भागीदारी (Limited Liability Partnerships- LLP) और साझेदारी फर्म शामिल हैं। अत: कथन 1 सही है।
- न्यायिक प्राधिकरण:
  - कंपनियों और LLP हेतु राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal- NCLT)।
  - व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों हेतु ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunal- DRT)। अत: कथन 2 सही नहीं है।

5.

उत्तर: D

व्याख्या:

- IMF बेलआउट्स: देशों की अर्थव्यवस्था को जब व्यापक आर्थिक ज़ोखिम होता है, अधिकांशत: मुद्रा संकट (जैसे कि श्रीलंका का सामना करना पड़ रहा है) का सामना करना पड़ता है तो वे आमतौर पर IMF से मदद मांगते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- देश अपने बाह्य ऋण और अन्य दायित्वों को पूरा करने, आवश्यक आयात करने और अपनी मुद्राओं के विनिमय मूल्य को बढ़ाने के लिये IMF से ऐसी सहायता मांगते हैं।
- IMF खराब अर्थव्यवस्थाओं को अक्सर विशेष आहरण अधिकार (SDR) के रूप में धन उधार देता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- SDR केवल पाँच मुद्राओं की एक बास्केट का प्रतिनिधित्त्व करते हैं, अर्थात् अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड।
- यह उधार कई ऋण कार्यक्रमों जैसे- विस्तारित ऋण सुविधा, लचीली क्रेडिट लाइन, स्टैंड-बाय समझौतों आदि द्वारा किया जाता है।
- बेलआउट प्राप्त करने वाले देश अपनी परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रयोजनों के लिये SDR का उपयोग कर सकते हैं।

6.

उत्तर: C

व्याख्या:

- 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय व्यवस्था को विनियमित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (IBRD) की स्थापना की। IMF का मुख्य उद्देश्य वैश्विक मौद्रिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। अत: कथन 1 सही है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) 190 देशों (सार्वभौमिक सदस्यता नहीं) का एक संगठन है, जो वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, सुरक्षित वित्तीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने, उच्च रोज़गार और सतत् आर्थिक विकास को बढ़ावा देने तथा विश्व भर में गरीबी उन्मूलन के लिये काम कर रहा है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- IMF के सदस्य: कोई अन्य राष्ट्र, चाहे संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो या नहीं, IMF के समझौते के अनुच्छेदों और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार IMF का सदस्य बन सकता है।
  - IMF में सदस्यता IBRD में सदस्यता के लिये एक शर्त है। अत: कथन 3 सही है।
  - कोटा सदस्यता का भुगतान: IMF में शामिल होने पर प्रत्येक सदस्य देश एक निश्चित राशि का योगदान करता है, जिसे कोटा सदस्यता कहा जाता है, जो देश की पूंजी और आर्थिक प्रदर्शन (कोटा सूत्र) पर आधारित होता है।

7.

उत्तर: C

व्याख्या:

- परिचय:
  - भारत विश्व स्तर पर 1.2 बिलियन डिजिटल ग्राहकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाज़ार है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पिछले नौ वर्षों में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में 2.5 गुना तेज़ी से बढ़ी है, यह एक असाधारण डिजिटल बढ़त है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - इस अवधि में ब्रॉडबैंड उपयोगकर्त्ताओं की संख्या 60 मिलियन से बढ़कर 800 मिलियन हो गई और इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर 850 मिलियन हो गई। इसके अलावा सरकार और निजी क्षेत्र ने मिलकर 25 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है।
  - प्रतिदिन 70 मिलियन ई-प्रमाणीकरण और मासिक 8 बिलियन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) लेन-देन के साथ भारत विश्व में सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ लोकतंत्र है। अत: कथन 3 सही है।
  - भारत ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से अपने नागरिकों को सीधे 28 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी है।

8.

उत्तर: D

व्याख्या:

- निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना:
  - TIES योजना केंद्र/राज्य सरकार के स्वामित्त्व वाली एजेंसियों या उनके संयुक्त उद्यमों को महत्त्वपूर्ण निर्यात संबंधी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं हेतु सहायता अनुदान प्रदान करती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - इस बुनियादी ढाँचे में बॉर्डर हाट, भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाएँ, कोल्ड चेन, व्यापार संवर्द्धन केंद्र, निर्यात भंडारण एवं पैकेजिंग, विशेष आर्थिक क्षेत्र व बंदरगाह/हवाई अड्डे कार्गो टर्मिनस शामिल हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।

9.

उत्तर: d

व्याख्या:

- "बैंक रन" शब्द एक ऐसी परिस्थिति को संदर्भित करता है जब ग्राहक या निवेशक घबरा जाते हैं एवं अपनी जमा राशि निकालना शुरू कर देते हैं। बैंक रन को रोकने या कम करने के लिये आमतौर पर उपयोग किये जाने वाले तरीके निम्नलिखित हैं:
  - नकदी की उपलब्धता बढ़ाने के लिये बैंक परिसंपत्तियों को बेच सकते हैं।
  - बैंक निकासी को सिमित कर सकते हैं या निकासी को पूरी तरह प्रतिबंधित कर सकते हैं।
  - दिवालियापन को रोकने के लिये बैंक अन्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों या केंद्रीय बैंक से ऋण ले सकते हैं। अत: 3 सही है।
  - यदि किसी बैंक के बैंक रन होने की संभावना है, तो बैंक आगे की निकासी को रोकने के लिये अस्थायी रूप से बंद हो सकते हैं। अत: 2 सही है।
  - डिपॉज़िट इंश्योरेंस बैंक की विफलता के मामले में जमाकर्त्ताओं को एक सुरक्षा तंत्र प्रदान करता है और बैंक रन के विनाशकारी प्रभाव को सीमित कर सकता है। अत: 1 सही है।

10.

उत्तर: C

व्याख्या:

भारत-अमेरिका वाणिज्यिक संवाद:

- हाल ही में भारत और अमेरिका ने अपनी 5वीं मंत्रिस्तरीय वाणिज्यिक वार्ता पर संयुक्त वक्तव्य जारी किया है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और अर्द्धचालक साझेदारी पहल पर सहमति व्यक्त की गई है।
- जनवरी 2023 में भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा अमेरिका के व्यापारिक प्रतिनिधि राजदूत ने वाशिंगटन डीसी में भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम (TPF) की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता की।
- व्यापार नीति फोरम (TPF) संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच आयोजित की गई थी। फोरम ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को 'अगले उच्च स्तर' पर ले जाने का संकल्प लिया और 'संभावित लक्षित टैरिफ कटौती' पर विचारों का आदान-प्रदान किया। अत: कथन 1 सही है।
- दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार वर्ष 2014 के बाद से लगभग दोगुना हुआ है, जो वर्ष 2022 में 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- अमेरिका, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक और व्यापार साझेदार है, जबकि भारत, अमेरिका का 9वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अत: कथन 2 सही है।
- दोनों देशों का उद्देश्य वर्ष 2025 तक 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य हासिल करना है।
- अप्रैल 2000 से सितंबर 2022 तक 56,753 मिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के साथ अमेरिका भारत में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक भी है।

11.

उत्तर: C

व्याख्या:

- आभासी डिजिटल परिसंपत्ति सेवा प्रदाता/व्यवसाय अब PMLA अधिनियम 2002 के तहत 'रिपोर्टिंग संस्थाएँ' बन गई हैं और उन्हें अन्य विनियमित संस्थाओं जैसे- बैंकों, प्रतिभूति मध्यस्थों, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों आदि के समान रिपोर्टिंग मानकों एवं KYC मानदंडों का पालन करना चाहिये। अत: कथन 1 सही है।
- PMLA में शामिल गतिविधियों के उदाहरण हैं: आभासी डिजिटल परिसंपत्ति (Virtual digital assets- VDA) और फिएट मनी में ट्रेडिंग, विभिन्न VDA प्रकारों के बीच स्विच करना आदि। अत: कथन 2 सही है।

12.

उत्तर: D

व्याख्या:

- स्वामी निवेश कोष (Special Window for Affordable and Mid-Income Housing- SWAMIH): यह भारत का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव कोष है जिसे विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिये बनाया गया है।
- यह सरकार द्वारा समर्थित कोष है, जिसे वर्ष 2019 में लॉन्च किये गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) के साथ पंजीकृत श्रेणी- II वैकल्पिक निवेश कोष ((Alternate Investment Fund- AIF) के तहत ऋण कोष के रूप में स्थापित किया गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह कोष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इसका प्रबंधन स्टेट बैंक समूह की एक कंपनी SBICAP वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है।
- योग्यता मानदंड:
- रियल एस्टेट परियोजनाएँ, जो धन की कमी के कारण रुकी हुई हैं, को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम (RERA) के तहत अवश्य पंजीकृत होना चाहिये।

i. इनमें से प्रत्येक परियोजना लगभग पूरी होने के करीब होनी चाहिये।

- इन्हें 'किफायती और मध्यम-आय परियोजना' श्रेणी के अंतर्गत भी आना चाहिये (कोई भी आवास परियोजना जिसमें आवास इकाइयाँ 200 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक में न हों)। अत: कथन 2 सही नहीं है।

13.

उत्तर: B

व्याख्या:

- QR-कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन:
  - कैशलेस कॉइन डिस्पेंसर जिसे QR-कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन (QCVM) कहा जाता है, एकीकृत भुगतान इंटरफेस का उपयोग कर ग्राहक के बैंक खाते के माध्यम से सिक्का प्रदान करेगी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- ग्राहकों के लिये आवश्यक मात्रा और मूल्य वर्ग में सिक्के निकालने का विकल्प उपलब्ध होगा।
- यह सिक्कों तक पहुँच' को आसान बनाएगी।
  - QCVM एक नकद-आधारित मानक कॉइन वेंडिंग मशीन के विपरीत बैंक नोट प्रदान करने और उनके प्रमाणीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। अत: कथन 2 सही है।

14.

उत्तर: C

व्याख्या:

- IPEF (हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा) एक संयुक्त राज्य-नेतृत्त्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करना है ताकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुनम्यता, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- IPEF को वर्ष 2021 में 12 साझीदार देशों के साथ लॉन्च किया गया था, जो एक साथ विश्व GDP के 40% का प्रतिनिधित्त्व करते हैं।
- IPEF एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) नहीं है, किंतु यह इसके सदस्यों को कुछ मुद्दों पर बातचीत करने की अनुमति भी प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है। इस वार्ता के चार मुख्य "स्तंभ" निम्नलिखित हैं:
  - आपूर्ति-शृंखला सुनम्यता
  - स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइज़ेशन और बुनियादी ढाँचा
  - कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी
  - निष्पक्ष और सुनम्य व्यापार।

15.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हॉलमार्क:
- कीमती धातु के सामानों में कीमती धातु की आनुपातिक सामग्री का सटीक निर्धारण और आधिकारिक रिकॉर्डिंग को हॉलमार्किंग के रूप में जाना जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- आभूषणों के संदर्भ में हॉलमार्किंग योजना BIS द्वारा वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। भारत में वर्तमान में हॉलमार्किंग के दायरे में सोने और चाँदी जैसी दो कीमती धातुओं को शामिल किया गया है।
- हालाँकि 23 जून, 2021 से गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स ऑर्डर, 2022 के अनुसार, देश के 288 ज़िलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।
- वर्ष 2021 में 6-अंकीय HUID की शुरुआत के बाद हॉलमार्क में 3 प्रतीक अर्थात् BIS लोगो, आभूषणों की शुद्धता और 6-अंकीय अल्फान्यूमेरिक HUID शामिल थे। प्रत्येक हॉलमार्क किये गए आभूषण में अद्वितीय HUID संख्या होती है, जिससे आभूषणों के बारे में पता लगाया जा सकता है। अत: कथन 2 सही है।

16.

उत्तर: A

व्याख्या:

- GeM एक ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म है जिसे वर्ष 2016 में सरकारी मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (Public Sector Undertakings- PSU) आदि द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा हेतु स्थापित किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- इसकी परिकल्पना भारत के राष्ट्रीय खरीद पोर्टल के रूप में की गई है।
- इसे राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न (इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तकनीकी समर्थन के साथ आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (Directorate General of Supplies and Disposals-DGS&D), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
- GeM पूरी तरह से पेपरलेस, कैशलेस और सिस्टम संचालित ई-मार्केटप्लेस है जो न्यूनतम मानव इंटरफेस के साथ सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद को सक्षम बनाता है। अत: कथन 2 सही है।

17.

उत्तर: A

व्याख्या:

- सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE):
  - SSE मौजूदा स्टॉक एक्सचेंज के भीतर एक अलग खंड के रूप में कार्य करेगा और सामाजिक उद्यमों को अपने तंत्र के माध्यम से जनता फंड एकत्रित करने में मदद करेगा।
  - यह उद्यमों द्वारा अपनी सामाजिक पहलों के लिये वित्त की व्यवस्था करने, दृश्यता हासिल करने और फंड एकत्रित करने एवं इसके उपयोग के बारे में पारदर्शिता प्रदान करने हेतु एक माध्यम के रूप में काम करेगा।
  - खुदरा निवेशक केवल मुख्य बोर्ड के तहत लाभकारी सामाजिक उद्यमों (Social Enterprises- SE) द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।
  - अन्य सभी मामलों में केवल संस्थागत निवेशक और गैर-संस्थागत निवेशक सामाजिक उद्यमों द्वारा जारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं।
  - अर्हता:
  - कोई भी गैर-लाभकारी संगठन (Non-Profit Organisation- NPO) या लाभकारी सामाजिक उद्यम (FPSEs) जो सामाजिक प्रधानता का इरादा रखता है, को सामाजिक उद्यम के रूप में मान्यता दी जाएगी, जो इसे SSE में पंजीकृत या सूचीबद्ध होने के योग्य बनाएगा।
  - सेबी के ICDR विनियम, 2018 के तहत 17 प्रशंसनीय मानदंड भूख, गरीबी और कुपोषण को खत्म करने के साथ-साथ शिक्षा, रोज़गार, समानता एवं पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने हेतु कार्य कर रहे हैं।
  - अनर्हता:
  - कॉर्पोरेट क्षेत्र, राजनीतिक या धार्मिक संगठन, पेशेवर या व्यापार संघ, बुनियादी निर्माण एवं आवास कंपनियों (किफायती आवास को छोड़कर) को सामाजिक उद्यम हेतु गैर-लाभकारी संगठन के रूप में पहचाना नहीं जाएगा।अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - जो गैर-लाभकारी संगठन अपनी फंडिंग के 50% से अधिक के लिये कॉर्पोरेट पर निर्भर हैं, उन्हें अयोग्य माना जाएगा।

18.

उत्तर: C

व्याख्या:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, भारत की 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 47% आबादी की आजीविका का मुख्य आधार कृषि है। अत: कथन 2 सही है।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि के प्रभुत्त्व के बारे में आम धारणा के विपरीत लगभग दो-तिहाई ग्रामीण आय अब गैर-कृषि गतिविधियों से उत्पन्न होती है। अत: कथन 1 सही है।
- आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, पिछले छह वर्षों में कृषि क्षेत्र की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.6% रही है। हालाँकि ऐसे अन्य कई कारण हैं जिनसे कृषि क्षेत्र और ग्रामीण आय काफी प्रभावित हो रही है।

19.

उत्तर: B

व्याख्या:

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):

- यह यह भारत में ई-कॉमर्स उद्योग के लिये एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department of Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा स्थापित एक ओपन ई-कॉमर्स प्रोटोकॉल है।
- ONDC के तहत यह परिकल्पना की गई है कि एक भागीदार ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये अमेज़न) पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये फ्लिपकार्ट) पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है।
- इसका लक्ष्य एक सामान्य प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो ई-कॉमर्स मूल्य श्रृंखला में खरीदारों, विक्रेताओं, रसद प्रदाताओं और अन्य हितधारकों के बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह को सक्षम बनाता है।
- अत: विकल्प B सही है।

20.

उत्तर: B

व्याख्या:

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):

- यह यह भारत में ई-कॉमर्स उद्योग के लिये एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department of Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा स्थापित एक ओपन ई-कॉमर्स प्रोटोकॉल है।
- ONDC के तहत यह परिकल्पना की गई है कि एक भागीदार ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये अमेज़न) पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये फ्लिपकार्ट) पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है।

- इसका लक्ष्य एक सामान्य प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो ई-कॉमर्स मूल्य श्रृंखला में खरीदारों, विक्रेताओं, रसद प्रदाताओं और अन्य हितधारकों के बीच सूचना के निर्बाध प्रवाह को सक्षम बनाता है।
- अत: विकल्प B सही है।

21.

उत्तर: B

व्याख्या:

- वोस्ट्रो खाता वह खाता है जिसमें घरेलू बैंक विदेशी बैंकों के लिये घरेलू मुद्रा रखते हैं। घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु करते हैं जिनकी वैश्विक बैंकिंग जरूरतें हैं।
  - नोस्ट्रो खाता एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक में रखा गया खाता है। यह ग्राहकों को बैंक के खाते में दूसरे बैंक में पैसा जमा करने की अनुमति देता है। इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं होती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- जब भागीदार देशों के बैंक वोस्ट्रो खाता खोलने हेतु संपर्क करेंगे तो प्राधिकृत घरेलू बैंक व्यवस्था का विवरण प्रदान करते हुए शीर्ष बैंकिंग नियामक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
  - घरेलू बैंक यह सुनिश्चित करने हेतु ज़िम्मेदार हैं कि संपर्की बैंक वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force- FATF) की उच्च जोखिम और गैर-सहकारी क्षेत्राधिकारों की सूची में उल्लिखित देश से नहीं है।
  - अधिकृत बैंक एक ही देश के विभिन्न बैंकों में कई वोस्ट्रो खाते खोल सकते हैं। अत: कथन 2 सही है।

22.

उत्तर: D

व्याख्या:

- शेयर बाज़ार सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों में इक्विटी शेयरों के व्यापार हेतु खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ लाते हैं।
- शेयर बाज़ार एक मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था के घटक हैं क्योंकि वे निवेशक व्यापार और पूंजी के आदान-प्रदान हेतु लोकतांत्रिक पहुँच को सक्षम करते हैं।
- नियमन हेतु कानून:
  - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम)
  - प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (SCRA)
  - कंपनी अधिनियम, 2013
  - निक्षेपागार अधिनियम, 1996
  - आतंरिक व्यापार विनियम, 2015

अत: विकल्प D सही है।

23.

उत्तर: A

व्याख्या:

- सरकारी प्रतिभूतियों/जी-सेक केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा जारी एक व्यापार योग्य साधन है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- जी-सेक एक प्रकार का ऋण साधन है जो सरकार द्वारा अपने राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने हेतु जनता से धन उधार लेने के लिये जारी किया जाता है।
- एक ऋण साधन एक वित्तीय साधन है जो जारीकर्त्ता द्वारा एक निर्दिष्ट तिथि पर धारक को एक निश्चित राशि, जिसे मूलधन या अंकित मूल्य के रूप में जाना जाता है, का भुगतान करने के लिये एक संविदात्मक दायित्त्व का प्रतिनिधित्त्व करता है।
- यह सरकार के ऋण दायित्त्व को स्वीकार करता है। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्पकालिक (आमतौर पर ट्रेज़री बिल कहा जाता है, एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ- वर्तमान में तीन अवधियों में जारी किये जाते हैं, अर्थात् 9 -दिन, 182 दिन और 364 दिन) या दीर्घकालिक (आमतौर पर सरकारी बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है, एक वर्ष अथवा उससे अधिक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ) होती हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- भारत में केंद्र सरकार ट्रेज़री बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों जारी करती है, जबकि राज्य सरकारें केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी करती हैं, जिन्हें राज्य विकास ऋण (SDLs) कहा जाता है।
- G-Secs में व्यावहारिक रूप से डिफॉल्ट का कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिये जोखिम मुक्त गिल्ट-एज इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अत: कथन 3 सही है।
- गिल्ट-एज सिक्योरिटीज़ उच्च-श्रेणी के निवेश बॉण्ड हैं जो सरकारों और बड़े निगमों द्वारा धन उधार लेने के साधन के रूप में पेश किये जाते हैं।

24.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भुगतान गेटवे एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एक ऑनलाइन स्टोर अथवा व्यापारियों को भुगतान प्रोसेसर से जोड़ता है, जिससे व्यापारी को ग्राहक से भुगतान स्वीकार करने की अनुमति प्राप्त होती है। अत: कथन 2 सही है।

- दूसरी ओर, भुगतान एग्रीगेटर, मध्यस्थ हैं जो कई व्यापारियों को अलग-अलग भुगतान प्रोसेसर से जोड़ने के लिये एक मंच प्रदान करते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे के बीच मुख्य अंतर यह है कि भुगतान एग्रीगेटर वित्त/निधि का प्रबंधन करता है जबकि भुगतान गेटवे प्रौद्योगिकी प्रदान करता है।
- हालाँकि भुगतान एग्रीगेटर द्वारा भुगतान गेटवे प्रदान किया जा सकता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

25.

उत्तर: D

व्याख्या:

- परिचय:
  - राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है।
  - CAD और राजकोषीय घाटा संयुक्त रूप से दोहरा घाटा है जो शेयर बाज़ार और निवेशकों को प्रभावित कर सकता है।
- चालू खाता घाटा को कम करने के तरीके:
  - निर्यात प्रोत्साहन: CAD को कम करने के लिये निर्यात प्रोत्साहन सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है।
  - आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देना: वर्तमान में आयात की जा रही वस्तुओं के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने से व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार: घरेलू अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में सुधार से निर्यात बढ़ाने तथा व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है।

अत: विकल्प D सही है।

26.

उत्तर: C

व्याख्या:

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999:

- यह अधिनियम भारत में विदेशी मुद्रा लेन-देन के प्रशासन के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- FEMA जो कि 1 जून, 2000 से प्रभावी हुआ, के तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े सभी लेन-देन को पूंजी या चालू खाता लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अत: कथन 1 सही है।
- निवासी भारतीय:
- FEMA, 1999 की धारा 2(v) में 'भारत में रहने वाले व्यक्ति' को FEMA, 1999 की धारा 2 (V) में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत
- कुछ अपवादों को छोड़कर, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिनों से अधिक समय तक भारत में रहने वाला व्यक्ति। अत: कथन 2 सही है।
- भारत में पंजीकृत या निगमित कोई भी व्यक्ति या कॉर्पोरेट निकाय ।
- भारत में कार्यालय, शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्त्व या नियंत्रण भारत से बाहर के किसी व्यक्ति के पास हो।
- भारत के बाहर का कोई कार्यालय, शाखा या एजेंसी जिसका स्वामित्व या नियंत्रण भारत के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किया जाता हो।

27.

उत्तर: A

व्याख्या:

- क्रोनी कैपिटलिज़्म के बारे में:
  - क्रोनी कैपिटलिज़्म एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करने के लिये किया जाता है जिसमें राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ करीबी संबंध रखने वाले व्यक्ति या व्यवसाय बाज़ार में अनुचित लाभ हासिल करने के लिये अपने राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते हैं।
  - द इकोनॉमिस्ट इंडिया द्वारा प्रकाशित क्रोनी कैपिटलिज़्म इंडेक्स 2021 में 7वें स्थान पर था, जहाँ देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में क्रोनी सेक्टर की संपत्ति 8% थी।
- क्रोनी कैपिटलिज़्म से संबंधित मुद्दे:
  - मार्केटप्लेस में अनुचित लाभ: क्रोनी कैपिटलिज़्म भ्रष्टाचार को जन्म दे सकता है क्योंकि व्यवसाय अक्सर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर बाज़ार में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये अपने राजनीतिक संबंधों का उपयोग करते हैं।
  - यह कानून के शासन को कमज़ोर करने की साथ ही सरकारी संस्थानों में जनता के विश्वास को खत्म कर सकता है।
  - विकृत बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा: जब कुछ व्यवसायों को उनके राजनीतिक संबंधों के माध्यम से अनुचित लाभ दिया जाता है, तो यह बाज़ार की प्रतिस्पर्द्धा को विकृत कर देता है और छोटे व्यवसायों एवं उद्यमियों के लिये सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
  - इससे कुछ व्यक्तियों या निगमों के हाथों में धन और शक्ति का संकेद्रण हो सकता है।
  - नवाचार में गिरावट: बड़े व्यवसायों की प्रमुख स्थिति अक्सर प्रतिस्पर्द्धा को खत्म कर देती है और उन्हें अपने उत्पादों/सेवाओं को आगे बढ़ाने या सुधारने के लिये हतोत्साहित करती है।
  - यह समग्र अर्थव्यवस्था में नवाचार को खत्म सकता है और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में गिरावट ला सकता है।

- सरकार और अर्थव्यवस्था के प्रति जनता में अविश्वास: व्यापक रूप से क्रोनी कैपिटलिज़्म सरकारी संस्थानों और आर्थिक व्यवस्था में जनता के विश्वास को कम कर सकता है।
- इससे नीति निर्माताओं के लिये सुधारों को लागू करना और व्यवसायों को प्रभावी ढंग से संचालित करना मुश्किल हो सकता है। अत: विकल्प A सही है।

28.

उत्तर: C

व्याख्या:

- इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक निजी स्वामित्त्व की कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक रूप से कारोबार करती है। अत: कथन 1 सही है।
- IPO को आमतौर पर एक या एक से अधिक निवेश बैंकों द्वारा अंडरराइट (बीमा पॉलिसी के माध्यम से क्षति अथवा हानि की पूर्ति का आर्थिक दायित्त्व लेना) किया जाता है, जो शेयरों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने और IPO की सफलता सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार होते हैं।
- IPO में शेयरों की कीमत आपूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है। कंपनी और उसके अंडरराइटर शेयरों के लिये एक प्रारंभिक मूल्य निर्धारित करते हैं, लेकिन बाज़ार की स्थितियों तथा कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर IPO के बाद भी कीमत में उतार-चढ़ाव हो सकता है। अत: कथन 2 सही है।
- IPO में निवेश करना एक उच्च ज़ोखिम वाला निवेश माना जाता है, क्योंकि कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन और शेयर की कीमत अल्पावधि में अस्थिर हो सकती है।

29.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (RBI अधिनियम, 1934) (2016 में संशोधित) के तहत RBI को विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उपकरण हैं जिनका उपयोग मौद्रिक नीति को लागू करने के लिये किया जाता है।
  - रेपो दर: वह ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों को रातों-रात चलनिधि प्रदान करता है।
- रेपो दर सीधे विक्रेताओं द्वारा दी जाने वाली ऋण दरों से जुड़ी हुई है, रेपो में वृद्धि से उधार लेने की लागत में वृद्धि होगी।
  - मौद्रिक नीति समिति रेपो दर तय करती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) ने चालू वित्त वर्ष (2022-23) में अपनी सबसे हालिया बैठक में 6.4% वास्तविक GDP वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये) का अनुमान लगाया है।
- रेपो रेट वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है। अत: कथन 2 सही है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 की धारा 42(2) के तहत सांविधिक रिटर्न फॉर्म A रिटर्न (CRR के लिये) और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24 के तहत फॉर्म VIII रिटर्न (SLR के लिये) निर्धारित किया है। SLR और CRR दोनों संसद और RBI द्वारा तय किये जाते हैं, न कि MPC द्वारा।

30.

उत्तर: D

व्याख्या:

- राजकोषीय घाटा:
  - राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व (उधार को छोड़कर) के बीच का अंतर है।
  - यह एक संकेतक है जो दर्शाता है कि सरकार को अपने कार्यों को वित्तपोषित करने के लिये किस सीमा तक उधार लेना चाहिये और इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।
  - ऋण स्तर में वृद्धि, मुद्रा का मूल्यह्रास और मुद्रास्फीति कर्ज़ के बोझ में वृद्धि का कारण बन सकते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - जबकि कम राजकोषीय घाटा राजकोषीय प्रबंधन और सुचारू अर्थव्यवस्था के सकारात्मक संकेत हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।

31.

उत्तर: C

व्याख्या:

- सीड फंड एक निवेश फंड है जो स्टार्टअप्स को आमतौर पर सीड कैपिटल के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अत: कथन 1 सही है।
- सीड कैपिटल किसी स्टार्टअप में निवेश का शुरुआती चरण है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर कंपनी के शुरुआती समय में संचालन, उत्पाद विकास और बाज़ार अनुसंधान के वित्तपोषण के लिये किया जाता है।

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के कार्यान्वयन की देखरेख और निगरानी के लिये विशेषज्ञ सलाहकार समिति (EAC) की स्थापना की है। अत: कथन 2 सही है।

32.

उत्तर: C

व्याख्या:

- परिचय:
  - पेरिस क्लब ज़्यादातर पश्चिमी कर्जदाता देशों का एक समूह है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1956 में आयोजित बैठक से हुई है जिसमें अर्जेंटीना पेरिस में अपने सार्वजनिक कर्जदाताओं से मिलने हेतु सहमत हुआ था।
  - यह खुद को एक मंच के रूप में वर्णित करता है जहाँ लेनदार देशों द्वारा सामना की जाने वाली भुगतान कठिनाइयों को हल करने हेतु आधिकारिक कर्जदाता बैठक करते हैं।
  - इसका उद्देश्य उन देशों हेतु स्थायी ऋण-राहत समाधान खोजना है जो देश अपने द्विपक्षीय ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। अत: कथन 1 सही है।
- सदस्य:
  - सदस्यों में शामिल हैं: ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, आयरलैंड, इज़रायल, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य।
  - ये सभी 22 सदस्यीय आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) नामक समूह के सदस्य हैं।
  - हालिया गतिविधि:
  - पिछली सदी में पेरिस समूह के देशों का द्विपक्षीय ऋण पर प्रभुत्त्व था, लेकिन पिछले दो दशकों में चीन के दुनिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में उभरने के साथ उनका महत्त्व कम हो गया है। अत: कथन 2 सही है।
  - उदाहरण के लिये श्रीलंका के मामले में भारत, चीन और जापान सबसे बड़े द्विपक्षीय लेनदार हैं।
  - श्रीलंका के द्विपक्षीय ऋणों में चीन का 52%, जापान का 19.5% तथा भारत का 12% हिस्सा है।

33.

उत्तर: C

व्याख्या:

- सिकल सेल रोग में सिकल सेल के आकार की लाल रक्त कोशिकाएँ सामान्य लाल रक्त कोशिकाओं की तुलना में अधिक संवेदनशील होती हैं और समय से पहले ही विभाजित और मर जाती हैं। अत: कथन 1 सही है।
- इसमें हीमोग्लोबिन के अणु असामान्य होते हैं जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएँ सिकल सेल का आकार धारण करती हैं। यह कम ऑक्सीजन प्रवाह और दर्द सहित कई जटिलताओं को जन्म दे सकता है।
- लाल रक्त कोशिकाएँ जो कठोर और सिकल सेल के आकार की होती हैं, वे छोटी रक्त वाहिकाओं में फँस सकती हैं, रक्त के प्रवाह को बाधित कर सकती हैं एवं शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन के प्रवाह को सीमित कर सकती हैं। अत: कथन 2 सही है।

34.

उत्तर: D

व्याख्या:

केंद्रीय बजट 2023-24:

- केंद्रीय बजट 2023-24 का मुख्य विषय समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना है जो विशेष रूप से सबका साथ, सबका विकास की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है, जिसमें शामिल हैं:
- किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Classes- OBC), दिव्यांगजन (PwD) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Sections- EWS)।
- वंचितों को समग्र प्राथमिकता (वंचितों को वरीयता)।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र (Northeast Region- NER) के केंद्रशासित प्रदेशों पर भी निरंतर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- यह बजट 2019 में पहली बार अनावरण की गई द्वि-आयामी विकास रणनीति की तर्ज पर है:
- निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देकर रोज़गार सृजित करना और विकास को आगे बढ़ाना।
- 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन'; पूंजीगत परिव्यय (Capex) बढ़ाना और विनिवेश के माध्यम से अधिक राजस्व जुटाना। अत: कथन 1 सही है।
- बजट की मुख्य उपलब्धियाँ:
- नई आयकर व्यवस्था में बदलाव (छूट की सीमा में और टैक्स स्लैब में)।
- पूंजी निवेश परिव्यय में 33% की वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है, इसे बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए (पिछले एक दशक में सबसे अधिक वृद्धि) किया गया है। अत: कथन 3 सही है।

- सीमा शुल्क में परिवर्तन; मोबाइल फोन निर्माण, झींगा हेतु खाद्य आदि के लिये कुछ निविष्टियों के आयात में कमी और सिगरेट, सोने की वस्तुओं, यौगिक रबड़ आदि के आयात में वृद्धि की गई है।
- रेलवे के लिये पूंजी परिव्यय को बढ़ाकर अब तक का सर्वाधिक 2.40 लाख करोड़ रुपए किया गया है। अत: कथन 2 सही है।

35.

उत्तर : B

व्याख्या:

खाद्य और कृषि संगठन:

- परिचय:
- FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भुखमरी को समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्त्व करती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्तूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। वर्ष 1945 में FAO की स्थापना की वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में यह दिन मनाया जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- यह रोम (इटली) में स्थित संयुक्त राष्ट्र खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसकी सिस्टर निकाय विश्व खाद्य कार्यक्रम और कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (IFAD) हैं।
- प्रमुख प्रकाशन:
- द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर (SOFIA)
- स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स (SOFO) अत: कथन 3 सही है।
- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI)
- खाद्य और कृषि राज्य (SOFA)
- द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स (SOCO)

36.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार, एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है।
- वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने के लिये उत्तरदायी नोडल निकाय है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह बजट केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा की स्वीकृति के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है और इसीलिये इस विधेयक को पारित होने के लिये लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिये। अत: कथन 2 सही है।

37.

उत्तर: A

व्याख्या:

- जुलाई 2021 से, क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) दोनों दोनों में ही सुधार हुआ है। अत: कथन 1 सही है।
- यह अनुमान लगाया गया है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2023 में 6.8 प्रतिशत होगी, जो कि RBI द्वारा निर्धारित लक्ष्य सीमा से बाहर है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

38.

उत्तर: B

व्याख्या:

- उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन' योजना (PLI Scheme):
  - भारत सरकार द्वारा 14 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में PLI योजना की शुरुआत विनिर्माण उद्योग के लिये अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - 1.97 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ यह योजना विभिन्न प्रोत्साहनों और सहयोग उपायों के माध्यम से लक्षित उद्योग के विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिये अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई है।
  - मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना ने प्रारंभ में तीन उद्योगों को लक्षित किया:
  - मोबाइल और संबद्ध घटक विनिर्माण
  - विद्युत घटक विनिर्माण
  - चिकित्सीय उपकरण
- लक्षित क्षेत्र:
  - इसके तहत लक्षित 14 क्षेत्र इस प्रकार हैं- मोबाइल विनिर्माण, चिकित्सा उपकरणों का निर्माण, ऑटोमोबाइल और ऑटो घटक (Auto Components), फार्मास्यूटिकल्स, दवाएँ, विशेष इस्पात, दूरसंचार और नेटवर्किंग/संजाल उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, एसी और एलईडी, खाद्य उत्पाद, वस्त्र उत्पाद, सौर पीवी मॉड्यूल, उन्नत रसायन विज्ञान सेल (Advanced Chemistry Cell-ACC) बैटरी और ड्रोन एवं ड्रोन संबंधित घटक।
- योजना के तहत प्रोत्साहन:
  - दिये जाने वाले प्रोत्साहनों की गणना बढ़ी हुई बिक्री के आधार पर की जाती है।

- उन्नत रसायनिक सेल बैटरी, वस्त्र उत्पाद और ड्रोन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों में दिये जाने वाले प्रोत्साहनों की गणना पाँच वर्ष की अवधि में की गई बिक्री, प्रदर्शन तथा स्थानीय मूल्यवर्द्धन के आधार पर की जाएगी। अत: कथन 2 सही है।
- अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश पर ज़ोर दिये जाने से किसी भी उद्योग को वैश्विक रुझानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने में मदद मिलेगी।

39.

उत्तर: B

व्याख्या:

- परिचय:
  - भारत में ग्रामीण पर्यटन, ग्रामीण जीवन-शैली और संस्कृति की खोज तथा अनुभव पर केंद्रित है। अत: कथन 1 सही है।
  - इसमें स्थानीय संस्कृति और जीवन के प्रति गहरी समझ विकसित करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों की यात्रा करना तथा खेती, हस्तशिल्प एवं गाँव की सैर जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना शामिल है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - उदाहरण के लिये तमिलनाडु का कोलुक्कुमलाई विश्व का सबसे ऊँचा चाय बागान; केरल में देवलोकम नदी के किनारे एक योग केंद्र; नगालैंड का कोन्याक टी रिट्रीट आदि आगंतुकों/पर्यटकों को आदिवासी संस्कृति को समझने-जानने में मदद करते हैं।
- विस्तार:
  - भारत की ग्रामीण पर्यटन क्षमता इसकी विविध और जीवंत संस्कृति, हस्तशिल्प, लोक कलाओं, त्योहारों और मेलों में निहित है।
  - एक अमेरिकी मार्केट रिसर्च कंपनी, ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार, कृषि-पर्यटन उद्योग के वर्ष 2022 से 2030 तक 11.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की संभावना है। अत: कथन 3 सही है।
- महत्त्व:
  - ग्रामीण पर्यटन न केवल स्थानीय कला और शिल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने के साथ व्यवहार्य पारंपरिक व्यवसायों को विस्थापित होने से रोक सकता है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के पुनर्विकास एवं ग्रामीण जीवन को पुन: जीवंत करने, रोज़गार तथा नए व्यावसायिक अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा। अत: कथन 4 सही नहीं है।

40.

उत्तर: D

व्याख्या:

- GST परिषद:
  - यह केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है।
  - यह संविधान के अनुच्छेद 279A(1) के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा प्रवर्तित किया गया था।
- सदस्य:
  - परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - प्रत्येक राज्य, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।
- कार्य:
  - संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार, परिषद GST से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें कर सकती है, जैसे कि GST मॉडल कानून के तहत किन वस्तुओं एवं सेवाओं को GST के अधीन छूट दी जा सकती है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 के साथ-साथ अनुच्छेद 279A देश के वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है।
- वे विशेष रूप से संघ शुल्कों और वस्तुओं पर करों से "शुद्ध आय" की गणना तथा क्रमश: माल एवं सेवा कर परिषद के गठन से संबंधित हैं।
  - यह GST के विभिन्न स्लैब दर पर भी निर्णय लेता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- उदाहरण के लिये मंत्रियों के पैनल की एक अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% GST लगाने का सुझाव दिया गया है।

41.

उत्तर: C

व्याख्या:

आर्थिक सर्वेक्षण:

- भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज़ है। यह आमतौर पर केंद्रीय बजट से एक दिन पूर्व संसद में पेश किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के अर्थशास्त्र प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है।
  - यह विगत 12 माह की भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की समीक्षा करता है और चालू वित्त वर्ष के लिये आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

- यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP), मुद्रास्फीति, रोज़गार और व्यापार पर डेटा सहित भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को भी प्रस्तुत करता है। अत: कथन 2 सही है।
- भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था।
  - वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था। वर्ष 1964 के बाद से इसे बजट से अलग कर दिया गया है।

42.

उत्तर: C

व्याख्या:

विशेष आहरण अधिकार (SDRs):

- विशेष आहरण अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिये अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- SDR न तो एक मुद्रा है और न ही IMF पर इसका दावा किया जा सकता है। बल्कि यह IMF के सदस्यों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिये SDR का आदान-प्रदान किया जा सकता है। अत: कथन 2 सही है।
- SDR के मूल्य की गणना 'बास्केट ऑफ करेंसी' में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर की जाती है। इस बास्केट में पाँच देशों की मुद्राएँ शामिल हैं- अमेरिकी डॉलर, यूरोप का यूरो, चीन की मुद्रा रॅन्मिन्बी, जापानी येन और ब्रिटेन का पाउंड।
- SDRs या SDRi पर ब्याज दर सदस्यों को उनके SDR होल्डिंग्स पर दिया जाने वाला ब्याज है।

43.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में भारत सरकार ने लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये समन्वित और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के निष्पादन हेतु महत्त्वाकांक्षी गति शक्ति योजना या 'नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्लान' लॉन्च किया है।
- योजना के विषय में:
- उद्देश्य: ज़मीनी स्तर पर काम में तेज़ी लाना, लागत में कमी करना और रोज़गार पैदा करने पर ध्यान देने के साथ-साथ आगामी चार वर्षों में बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं की एकीकृत योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। अत: कथन 1 सही है।
- लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती के अलावा इस योजना का उद्देश्य कार्गो हैंडलिंग क्षमता को बढ़ाना और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु बंदरगाहों पर टर्नअराउंड समय को कम करना है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- इसमें एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी मौजूदा व नियोजित पहलें शामिल होंगी। प्रत्येक विभाग अब व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना एवं निष्पादन करते समय महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करते हुए एक-दूसरे की गतिविधियों की दृश्यता में रहेगा। अत: कथन 3 सही नहीं है।

44.

उत्तर: D

व्याख्या:

- निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या कंपनी के संचालन से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- यह कर किसी निगम के शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है, जिसकी गणना उक्त निगम के कुल राजस्व से बेचे गए उत्पादों की लागत, परिचालन व्यय और मूल्यह्रास जैसे स्वीकार्य खर्चों को घटाकर की जाती है।
- निगम कर कंपनी अधिनियम 1956 के तहत भारत में पंजीकृत सार्वजनिक और निजी दोनों कंपनियों द्वारा देय है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

45.

उत्तर: C

व्याख्या:

- जब वस्तुओं या सेवाओं की मांग उन वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में तेज़ी से बढ़ती है, तो मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति तब होती है जब कुल मांग में वृद्धि होती है और आपूर्ति पूर्व स्थिति में पहुँच जाती है अथवा घट जाती है। अत: कथन 1 सही है।
- स्टैगफ्लेशन कम आर्थिक विकास और उच्च मुद्रास्फीति का एक संयोजन है। कुल मांग में गिरावट आर्थिक विकास को कम करके और बेरोज़गारी को बढ़ाकर गतिरोध पैदा कर सकती है, जबकि एक ही समय में उच्च मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को कम कर सकती है और खर्च करने की उनकी क्षमता को और कम कर सकती है। अत: कथन 2 सही है।

46.

उत्तर: D

व्याख्या:

- गिग कर्मी आमतौर पर स्व-नियोजित होते हैं और परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर काम करते हैं, जिसका अर्थ है कि गिग

अर्थव्यवस्था में अस्थायी, लचीली नौकरियाँ आम बात है। कंपनियाँ पूर्णकालिक कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों को नियुक्त करती हैं।

- गिग कार्य उन लोगों द्वारा किये गए कार्य से जुड़ा है, जिन्हें परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर भुगतान किया जाता है, और स्वतंत्र ठेकेदार वे स्व-नियोजित कर्मचारी होते हैं जो व्यवसायों को सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- सारांशत:, गिग कर्मी स्व-नियोजित हैं, परियोजना-दर-परियोजना के आधार पर काम करते हैं, और लाभ या नौकरी की सुरक्षा के लिये पात्र नहीं होते हैं। वे वेतनभोगी कर्मचारी नहीं हैं क्योंकि वे एक पारंपरिक रोज़गार संरचना का हिस्सा नहीं हैं और उन्हें नियमित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। अत: विकल्प D सही है।

47.

उत्तर: B

व्याख्या:

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम 2003, भारत सरकार द्वारा राजकोषीय अनुशासन एवं ज़िम्मेदार बजट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ पारित कानून है। अधिनियम सरकार के राजकोषीय घाटे को कम करने के लिये लक्ष्य निर्धारित करता है, जो कि इसके राजस्व तथा व्यय के बीच का अंतर है।
- अधिनियम सरकार के वार्षिक बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिये एक रूपरेखा भी स्थापित करता है तथा सरकार को अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन पर नियमित रिपोर्ट प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है।
- FRBM अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार का वित्तीय प्रबंधन पारदर्शी, अनुमानित और जवाबदेह हो।
- अत: विकल्प B सही है।

48.

उत्तर: C

व्याख्या:

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) भारत सरकार में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है।
- यह बड़े पैमाने पर आर्थिक जनगणना और सर्वेक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर सांख्यिकीय डेटा एकत्र करने, संकलित करने तथा इस डेटा को जनता तक पहुँचाने के लिये ज़िम्मेदार है।
- NSO सांख्यिकीय डेटा के संग्रह और विश्लेषण में अन्य सरकारी एजेंसियों को तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है।
- मौद्रिक नीति तैयार करना और कार्यान्वित करना NSO का कार्य नहीं है, यह भारतीय रिज़र्व बैंक की ज़िम्मेदारी है।
- अत: विकल्प C सही है।

49.

उत्तर: B

व्याख्या:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 का उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- पात्रता:
  - राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवार। अत: कथन 1 सही है।
  - अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए परिवार।
- प्रावधान:
  - प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो प्रदान किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - हालाँकि अंत्योदय अन्न योजना के तहत मौजूदा प्रतिमाह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान करना जारी रहेगा।
  - गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है।
  - 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।
  - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
  - ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

50.

उत्तर: D

व्याख्या:

मुद्रा आपूर्ति:

- किसी विशेष समय में जनता के बीच चलन में मुद्रा का कुल भंडार मुद्रा आपूर्ति कहलाता है।
  - यह ध्यान देने योग्य है कि मुद्रा का कुल भंडार मुद्रा की कुल आपूर्ति से भिन्न होता है। अत: कथन 1 सही है।
  - मुद्रा की आपूर्ति मुद्रा के कुल भंडार का केवल वह भाग है जो किसी समय विशेष पर जनता के पास होती है।

- चलन में जो धन शामिल होता है उसमें मुद्रित नोट, जमा खातों में धन और अन्य तरल संपत्तियाँ होती हैं।
- आरबीआई मुद्रा आपूर्ति के चार वैकल्पिक उपायों के लिये आँकड़े प्रकाशित करता है, अर्थात् M1, M2, M3 और M4।
  - M1 = CU + DD
  - M2 = M1 + डाकघर बचत बैंकों में बचत जमा
  - M3 = M1 + वाणिज्यिक बैंकों में शुद्ध सावधि जमा
  - M4 = M3 + डाकघर में कुल जमा (सावधि जमा+आवर्ती जमा) (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों को छोड़कर)
- CU जनता द्वारा धारित मुद्रा (नोट+सिक्के) है और DD वाणिज्यिक बैंकों द्वारा धारित शुद्ध मांग जमा है।
- 'नेट' शब्द का तात्पर्य है कि बैंकों द्वारा रखी गई जनता की जमा राशि को ही मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया जाना है।
  - जब एक वाणिज्यिक बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों में इंटरबैंक डिपॉज़िट रखता है, तो इसे मुद्रा की आपूर्ति का हिस्सा नहीं माना जाता है। अत: कथन 3 सही है।
- M1 और M2 को संकुचित मुद्रा (नैरो मनी) कहा जाता है। M3 और M4 को विस्तृत मनी (ब्रॉड मनी) के रूप में जाना जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- ये श्रेणियाँ तरलता के घटते क्रम में हैं।
  - M1 लेन-देन के लिये सबसे अधिक तरल और आसान है, जबकि M4 सबसे कम तरल है।
  - M3 पैसे की आपूर्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपाय है। इसे कुल मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है।

51.

उत्तर: D

व्याख्या:

आठ कोर सेक्टर:

- आठ प्रमुख उद्योगों में शामिल हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली का उत्पादन।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में इन उद्योगों का भारांश 40.27 प्रतिशत है।
- घटते क्रम में इन उद्योगों का भारांश: रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

52.

उत्तर: C

व्याख्या:

- उद्यम पूंजी एक प्रकार का वित्तपोषण है जो धनी व्यक्तियों या फर्मों द्वारा कंपनी में स्वामित्व हिस्सेदारी के बदले छोटे स्टार्टअप को उनके प्रारंभिक चरण में प्रदान की जाती है।

53.

उत्तर: C

व्याख्या:

- GNPA अनुपात की गणना बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा रखी गई सभी संपत्तियों के कुल मूल्य से गैर-निष्पादित संपत्तियों के कुल मूल्य को विभाजित करके की जाती है। अत: कथन 1 सही है।
- यदि बैंक या वित्तीय संस्थान का उच्च GNPA अनुपात है, तो उसे इन गैर-निष्पादित संपत्तियों से होने वाले संभावित नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के लिये अतिरिक्त धनराशि निर्धारित करने की आवश्यकता हो सकती है।
- उच्च GNPA अनुपात संस्थान की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुँचा सकता है और पूंजी जुटाने या निवेशकों को आकर्षित करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अत: कथन 2 सही है।

54.

उत्तर C

व्याख्या:

- वैधानिक तरलता अनुपात (Statutory Liquidity Ratio- SLR) जमा का न्यूनतम प्रतिशत है (अर्थात् शुद्ध मांग और समय देयता (Net Demand and Time Liabilities- NDTL) जो एक वाणिज्यिक बैंक को अपने पास रखना होता है। अत: कथन 1 सही है।
- यह संपत्ति निम्नलिखित के रूप में हो सकती है:
- नकद
- सोने की कीमत वर्तमान कीमत से अधिक नहीं है
- सरकारी प्रतिभूतियाँ और ट्रेज़री बिल
- नकद आरक्षित अनुपात (Cash Reserve Ratio- CRR) कुल जमा राशि का न्यूनतम प्रतिशत है जिसे एक वाणिज्यिक बैंक को RBI के पास नकद भंडार के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता होती है। अत: कथन 2 सही है।

55.

उत्तर A

व्याख्या:

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। किसानों की ऋण आवश्यकताओं (कृषि संबंधी खर्चों) की पूर्ति के लिये पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करने, साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक कार्यकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तुत की गई थी। यह ऋण

सुविधा आवश्यकता के आधार पर एक सरल कार्यविधि के माध्यम से प्रदान की जाती है। अत: कथन 1 सही है।

- बजट 2018-19 में सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालक किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद के लिये किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सुविधा के विस्तार की घोषणा की।
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ:
- वाणिज्यिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)
- लघु वित्त बैंक
- सहकारी समितियाँ

अत: कथन 2 सही नहीं है।

56.

उत्तर A

व्याख्या:

- वैश्विक न्यूनतम कर (GMT) विश्व भर में कॉर्पोरेट आय आधार को परिभाषित करने के लिये मानक न्यूनतम कर दर को लागू करता है। अत: कथन 1 सही है।
- OECD ने बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों के विदेशी मुनाफे पर 15% कॉर्पोरेट न्यूनतम कर का प्रस्ताव किया है, जो देशों को 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नया वार्षिक कर राजस्व प्रदान करेगा।
- GMT का उद्देश्य कम कर दरों के माध्यम से राष्ट्रों की कर प्रतिस्पर्द्धा से हतोत्साहित करना है, क्योंकि इसकी वजह से कॉर्पोरेट लाभ में बदलाव और कर आधार का क्षरण होता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक परिचालन वाले बड़े व्यवसायों को टैक्स बचाने के लिये टैक्स हेवन में रहने से लाभ की प्राप्ति न हो।
  - न्यूनतम कर और अन्य प्रावधानों का उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये सरकारों के बीच दशकों से चली आ रही कर प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करना है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

57.

उत्तर: C

व्याख्या:

- यह नीति रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (RSC) के नए मॉडल पर आधारित है, इसे पहले के प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट (PSC) के बदले लाया गया है। अत: कथन 1 सही है।
- इंडियन सेडिमेंट्रीबेसिन में तेल और गैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति (HELP) शुरू की गई थी।
- HELP नीति के तहत ओपन एकरेज लाइसेंसिंग (OAL) मैकेनिज़्म लॉन्च किया गया है। अत: कथन 2 सही है।

58.

उत्तर A

व्याख्या:

- भारत में चमड़ा उद्योग की हिस्सेदारी वैश्विक चमड़ा उत्पादन का लगभग 13% है और यहाँ लगभग 3 बिलियन वर्ग फीट चमड़े का वार्षिक उत्पादन होता है।
- चमड़ा उद्योग एक रोज़गार सघन उद्योग है जो 4 मिलियन से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश समाज के कमज़ोर वर्गों से हैं।
- भारत में चमड़े और जूते के उत्पादों के प्रमुख उत्पादन केंद्र तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में स्थित हैं। अत: कथन 1 सही है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से चमड़ा और चमड़े के उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक है तथा अप्रैल-अगस्त 2022 के दौरान देश के कुल चमड़े के निर्यात का 25.19% का निर्यात किया गया। अत: कथन 2 सही नहीं है।

59.

उत्तर D

व्याख्या:

- रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक के खिलाफ भारतीय रिज़र्व बैंक से रातोंरात तरलता उधार ले सकते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- बैंक दर वह दर है जिस पर RBI खरीद के लिये पात्र विनिमय या अन्य वाणिज्यिक पत्र के बिलों को खरीदने या फिर से भुनाने के लिये तैयार होता है। बैंक दर RBI अधिनियम, 1934 की धारा 49 के तहत प्रकाशित की जाती है। अत: कथन 2 सही है।
- दैनिक औसत शेष राशि जिसे बैंक को अपनी शुद्ध मांग और समय पर देनदारियों के प्रतिशत के रूप में रिज़र्व बैंक के साथ बनाए रखने के लिये आवश्यक है, इसे रिज़र्व बैंक समय-समय पर भारत के राजपत्र में सूचित कर सकता है, यह कैश रिज़र्व अनुपात (CRR) के रूप में जाना जाता है। अत: कथन 3 सही है।

60.

उत्तर C

व्याख्या:

- यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने टी-सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया (T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia: T-ALL) से पीड़ित मरीज़ में कैंसर थेरेपी के एक नए रूप 'बेस एडिटिंग' का सफल परीक्षण किया है। अत: कथन 1 सही है।
- टी-सेल संक्रमित कोशिकाओं को मारकर, अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करके और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को विनियमित कर व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं।
- टी-सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जो अस्थि मज़्जा की रक्त बनाने वाली स्टेम कोशिकाओं में बनता है। अत: कथन 2 सही है।

61.

उत्तर: A

व्याख्या:

- सरकारें 1 महीने से 30 वर्ष तक की अवधि के लिये उधार लेती हैं।
- आमतौर पर लंबी अवधि के लिये यील्ड अधिक होता है क्योंकि इसमें धन लंबे समय तक के लिये उधार दिया जाता है।
- यदि बॉण्ड के अलग-अलग कार्यकाल के लिये यील्ड को मापा जाता है, तो यह ऊपर की ओर ढाल वाला वक्र प्रदान करेगा। अत: कथन 1 सही है।
- बाज़ार में उपलब्ध धन और अपेक्षित समग्र आर्थिक गतिविधियों के आधार पर वक्र सपाट या सीधा हो सकता है। जब निवेशक अर्थव्यवस्था के बारे में उत्साहित महसूस करते हैं, तो वे दीर्घकालिक बॉण्ड से पैसा निकालते हैं और इसे शेयर बाज़ारों जैसे अल्पकालिक ज़ोखिम वाली परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। जैसे-जैसे दीर्घकालिक बॉण्ड की कीमतें गिरती हैं, उनका यील्ड बढ़ता है और यील्ड वक्र बढ़ता जाता है।
- यील्ड व्युत्क्रम तब होता है जब कम अवधि के बॉण्ड के लिये यील्ड लंबी अवधि के बॉण्ड पर यील्ड की तुलना में अधिक होता है। यदि निवेशकों को संदेह है कि अर्थव्यवस्था संकट की ओर बढ़ रही है, तो वे अल्पकालिक ज़ोखिम वाली परिसंपत्तियों (जैसे शेयर बाज़ार) से पैसा निकालेंगे और इसे दीर्घकालिक बॉण्ड में निवेश करेंगे। इससे दीर्घकालिक बॉण्ड की कीमतें बढ़ जाती हैं एवं उनका यील्ड घट जाता है। यह प्रक्रिया पहले सपाट और अंतत: यील्ड व्युत्क्रमण की स्थिति होती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

62.

उत्तर: A

व्याख्या:

- MSF ऐसी स्थिति में अनुसूचित बैंकों के लिये आपातकालीन स्थिति में RBI से ओवरनाइट (रातों-रात) ऋण लेने की सुविधा है जब अंतर-बैंक तरलता पूरी तरह से कम हो जाती है। अत: कथन 1 सही है।
- MSF के तहत, बैंकों को RBI से ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया में वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के तहत आने वाली प्रतिभूतियों का उपयोग करने की भी अनुमति है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- SLR के तहत, वाणिज्यिक बैंकों को RBI द्वारा नकदी, सोना और अभारग्रस्त (ऋण से मुक्त) प्रतिभूतियों जैसी तरल संपत्तियों के रूप में अपनी जमा राशि का एक निर्धारित अनुपात बनाए रखने के लिये अनिवार्य किया जाता है।

63.

उत्तर: C

व्याख्या:

- पूँजीगत बजट - इसमें पूँजीगत प्राप्तियाँ और पूँजीगत व्यय शामिल हैं।
  - पूंजी प्राप्तियाँ सरकार की वे प्राप्तियाँ होती हैं, जो या तो देनदारियों (Liabilities) का सृजन करती हैं या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं, इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) संपत्ति (या विनिवेश) जैसे कि सार्वजनिक उद्यमों के शेयरों को बेचकर अर्जित धन, और (ii) राज्यों द्वारा उधार लेने या ऋण चुकाने के रूप में प्राप्त धन। अत: कथन 1 सही है।
  - पूंजीगत व्यय सरकार का वह व्यय होता है जो या तो संपत्ति का निर्माण करता है या देयता को कम करता है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) सड़कों और अस्पतालों जैसी संपत्तियों के निर्माण पर सरकार द्वारा दीर्घकालिक निवेश, और (ii) राज्यों को ऋण के रूप में सरकार द्वारा दिया गया धन या उसकी उधारियों का पुनर्भुगतान। अत: कथन 2 सही है।

64.

उत्तर B

व्याख्या:

- रेपो दर वह दर है जिस पर RBI सभी वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है जिसमें अनुसूचित बैंक के साथ-साथ अन्य संबंधित बैंक भी शामिल हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- रेपो रेट पर उन बैंकों को ऋण दिया जाता है जो अपनी अल्पकालिक वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं। जबकि, MSF बैंकों को रातोंरात उधार देने के लिये है। अत: कथन 2 सही है।

65.

उत्तर A

व्याख्या:

मौद्रिक नीति समिति (MPC):

- संशोधित (2016 में) आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन करने का अधिकार है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत RBI को विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अत: कथन 2 सही है।
- इसके अलावा धारा 45ZB में कहा गया है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीतिगत दर का निर्धारण करेगी।
- मौद्रिक नीति समिति का निर्णय बैंक के लिये बाध्यकारी होता है।
- धारा 45ZB के अनुसार MPC में 6 सदस्य होंगे:

a. RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में।

b. मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर।

c. केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी।

d. केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन व्यक्ति।

i. इस प्रक्रिया के तहत "अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्त या मौद्रिक नीति के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों" की नियुक्ति की जाएगी।

66.

उत्तर D

व्याख्या:

- विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा में एक केंद्रीय बैंक द्वारा आरक्षित संपत्ति है, जिसमें बॉण्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल हो सकती हैं।
  - यह ध्यान दिया जाना चाहिये कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किये जाते हैं।
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल हैं:
  - विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति
  - सोने का भंडार
  - विशेष अहरण अधिकार
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ आरक्षित स्थिति।
- अत: विकल्प D सही है।

67.

उत्तर D

व्याख्या:

- PDS उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत स्थापित एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कम कीमत पर अनाज के वितरण और आपातकालीन स्थितियों में प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये लाई गई एक प्रणाली है।
  - PDS केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत संचालित होता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - पहचान किये गए लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये केंद्र और राज्य सरकारें ज़िम्मेदारी साझा करती हैं।
  - केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर किसानों से अनाज खरीदता है और केंद्रीय निर्गम मूल्य पर राज्यों को बेचता है। यह प्रत्येक राज्य में अनाज को गोदामों तक पहुँचाने हेतु ज़िम्मेदार है।
  - राज्य इन गोदामों से खुदरा दुकान (राशन की दुकान) तक खाद्यान्न की ढुलाई की व्यवस्था और प्रबंधन करते हैं, जहाँ लाभार्थी निम्न केंद्रीय निर्गम मूल्य पर खाद्यान्न खरीदता है। कई राज्य खाद्यान्न को लाभार्थियों को बेचने से पहले उसकी कीमतों में और सब्सिडी देते हैं।

PDS प्रणाली का महत्त्व:

- यह राष्ट्र की खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है।
- इसने खाद्य कीमतों को स्थिर करने और गरीबों को सस्ती कीमतों पर अनाज/भोजन उपलब्ध कराने में सहायता की है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- यह गोदामों में खाद्यान्नों के बफर स्टॉक को बनाए रखता है ताकि कम कृषि खाद्य उत्पादन की अवधि के दौरान भी भोजन/अनाज का प्रवाह सक्रिय रूप से बना रहे।
- इसने देश के अधिशेष क्षेत्रों से अभावग्रस्त क्षेत्रों में भोजन की आपूर्ति करके अनाज के पुनर्वितरण में मदद की है।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य और खरीद की व्यवस्था ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि में योगदान दिया है।

68.

उत्तर C

व्याख्या:

- स्वच्छता उद्यमी योजना सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में भुगतान और उपयोग सामुदायिक शौचालयों के निर्माण, संचालन

और रखरखाव और स्वच्छता संबंधी वाहनों की खरीद एवं संचालन के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अत: कथन 1 सही है।

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्वच्छता उद्यमी योजना (SUY) शुरू की है।
- स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन
  - क्षमता का दोहन करने के लिये उपयुक्त बुनियादी ढाँचा तैयार करना।
  - स्रोत से कचरा संग्रहण के लिये सुविधाओं का निर्माण करना।
  - सफाई कर्मचारियों/मैला ढोने वालों के लक्षित समूह के लिये रोज़गार के अवसर सृजित करना।
- मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिये स्वरोज़गार योजना (SRMS) के तहत 3.25 लाख रूपए की अधिकतम सब्सिडी तब देय होती है जब इकाई की स्थापना "हाथ से मैला ढोने वालों के रूप में रोज़गार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अनुसार पहचान की जाती है। अत: कथन 2 सही है।

69.

उत्तर C

व्याख्या:

- चालू खाता देश में और बाहर माल, सेवाओं और निवेश के प्रवाह को मापता है। यह देश के विदेशी लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता है और पूंजी खाते की तरह, देश के भुगतान संतुलन (BoP) का एक घटक है।
- चालू खाते में घाटा तब होता है जब आयातित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात किये गए मूल्य से अधिक हो जाता है
- बढ़ते CAD वाला देश दर्शाता है कि वह अब अप्रतिस्पर्धी हो गया है, और निवेशक वहाँ निवेश करने के इच्छुक नहीं हो सकता है न हों। अत: कथन 1 सही है।
- चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा (जिसे "बजट घाटा" के रूप में भी जाना जाता है यह एक ऐसी स्थिति है जब किसी देश का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है) को एक साथ जुड़वाँ घाटे के रूप में जाना जाता है और दोनों अक्सर एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, अर्थात, उच्च राजकोषीय घाटा उच्च CAD की ओर जाता है या इसके विपरीत। अत: कथन 2 सही है।

70.

उत्तर: D

व्याख्या:

- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register- NPR) एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- NPR के प्रयोजनों के लिये एक सामान्य निवासी वह व्यक्ति है जो किसी स्थान पर छह महीने या उससे अधिक समय से रह रहा है और वहाँ छह महीने या उससे अधिक समय तक रहने का इरादा रखता है।
- नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register of Citizens- NRC) सभी भारतीय नागरिकों का विवरण रखने वाला रजिस्टर है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- NRC वर्ष 1951 में केवल एक बार प्रकाशित किया गया था और तब से इसे हाल तक अद्यतन नहीं किया गया है।
- इसे अभी असम में ही अद्यतन किया गया है और सरकार की योजना इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपडेट करने की है।

71.

उत्तर: C

व्याख्या:

- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जारी किया है। अत: कथन 1 सही है।
- कामकाज़ी उम्र की आबादी 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को संदर्भित करती है।
- श्रम बल भागीदारी दर की गणना कुल कामकाज़ी उम्र की आबादी द्वारा श्रम बल को विभाजित करके की जाती है। अत: कथन 2 सही है।
- पुरुषों में LFPR 73.4% तथा महिलाओं में 21.7% (73.5% और 19.9%, जुलाई-सितंबर 2021 में) था।

72.

उत्तर: C

व्याख्या:

मार्ग (MAARG) पोर्टल का उद्देश्य:

- स्टार्ट-अप को उनके पूरे जीवनचक्र में क्षेत्र केंद्रित मार्गदर्शन, हैंडहोल्डिंग और समर्थन प्रदान करना। इसका उद्देश्य एक औपचारिक और संरचित मंच स्थापित करना है जो स्टार्ट-अप के लये कुशल और विशेषज्ञ सलाह की सुविधा हेतु सलाहकारों और उनके संबंधित मेंटर के बीच एक मंच की सुविधा प्रदान करता है तथा एक परिणाम-उन्मुख तंत्र का निर्माण करता है जो मेंटर-मेंटी व्यस्तताओं की समय पर ट्रैकिंग की अनुमति देता है। अत: कथन 1 सही है।
- MAARG पोर्टल है – मेंटरशिप, सलाहकार, सहायता, लचीलापन और विकास।
- MAARG पोर्टल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा संचालित किया जा रहा है। अत: कथन 2 सही है।

73.

उत्तर: D

व्याख्या:

- 2019 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग सेवाओं की शिकायत निवारण प्रक्रिया में ग्राहक अनुभव को बेहतर प्रदान के लिये शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS) शुरू की। अत: कथन 1 सही है।
- यह योजना शिकायत दर्ज करने के आधार के रूप में 'सेवा में कमी' को परिभाषित करती है, जिसमें बहिष्करण की एक निर्दिष्ट सूची होती है।
- अत: शिकायतों को अब केवल "योजना में सूचीबद्ध आधारों के तहत कवर नहीं किये जाने" के कारण खारिज नहीं किया जाएगा। अत: कथन 2 सही है।
- इस योजना का क्षेत्राधिकार तटस्थ है और किसी भी भाषा में शिकायतों के प्रारंभिक निपटान के लिये चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है। अत: कथन 3 सही है।

74.

उत्तर: A

व्याख्या:

- राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (NIIF) सरकार समर्थित संस्था है जो देश के बुनियादी ढाँचा क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिये स्थापित की गई है।
- NIIF में भारत सरकार की 49% हिस्सेदारी है, बाकी विदेशी और घरेलू निवेशकों के पास है।
- केंद्र की महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ NIIF को भारत का अर्द्ध-संप्रभु धन कोष माना जाता है।
- इसे दिसंबर 2015 में श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में स्थापित किया गया था।
- अपने तीन फंडों में यह 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक पूंजी का प्रबंधन करता है।
- इसका रजिस्टर्ड कार्यालय नई दिल्ली में है।

75.

उत्तर: A

व्याख्या:

- फ्रेंडशोरिंग एक रणनीति है जहाँ एक देश कच्चे माल, घटकों और यहाँ तक कि निर्मित वस्तुओं को उन देशों से प्राप्त करता है जो इसके मूल्यों को साझा करते हैं। इसमें आपूर्ति शृंखलाओं की स्थिरता के लिये "खतरा" माने जाने वाले देशों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो जाती है।
- इसे "एलीशोरिंग" भी कहा जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- फ्रेंडशोरिंग विश्व के देशों को व्यापार के लिये अलग-थलग कर सकता है और इससे वैश्वीकरण के लाभों की प्रकृति बिलकुल ही विपरीत हो जाएगी। यह "डीग्लोबलाइज़ेशन" प्रक्रिया का एक हिस्सा है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

76.

उत्तर: C

व्याख्या:

बॉण्ड बाज़ार:

- बॉण्ड बाज़ार प्रमुख तौर पर एक ऐसे बाज़ार है जहाँ निवेशक ऋण प्रतिभूतियाँ खरीदते हैं जो या तो सरकारी संस्थाओं या निगमों द्वारा बाज़ार में लाई जाती हैं।
  - राष्ट्रीय सरकारें आम तौर पर बॉण्ड से प्राप्त आय का उपयोग अवसंरचनात्मक सुधारों और ऋणों का भुगतान करने के लिये करती हैं। अत: कथन 3 सही है।
- बॉण्ड:
  - बॉण्ड कंपनियों द्वारा जारी कॉर्पोरेट ऋण की इकाइयाँ हैं और व्यापार योग्य संपत्ति के रूप में प्रतिभूतिकृत हैं। अत: कथन 1 सही है।
  - एक बॉण्ड को एक निश्चित आय साधन के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि बॉण्ड पारंपरिक रूप से देनदारों को एक निश्चित ब्याज दर (कूपन) का भुगतान करते हैं।
  - परिवर्तनीय या अस्थायी ब्याज दरें भी अब काफी आम हैं।
  - बॉण्ड की कीमतें ब्याज़ दरों के साथ विपरीत रूप से सहसंबद्ध होती हैं: जब दरें बढ़ती हैं, तो बॉण्ड की कीमतें गिरती हैं और जब दरें गिरती हैं, तो बॉण्ड की कीमतें बढ़ती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

77.

उत्तर: C

व्याख्या:

- बड़ी मात्रा में ड्रग्स विनिर्माण के लिये एक ठोस पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण को बढ़ावा देने के लिये PLI योजना की शुरुआत की गई है। अत: कथन 1 सही है।
- विभिन्न समूहों के विकास के माध्यम से एंड-टू-एंड विनिर्माण पारितंत्र बनाने के लिये सरकार ने कृषि रसायन क्षेत्र के लिये 10-20% आउटपुट प्रोत्साहन के साथ एक पीएलआई प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है।
- उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोज़गार सृजन के साथ घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिये उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना की कल्पना की गई थी। अत: कथन 2 सही है।

78.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने भारत का पहला तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया, अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह महिलाओं के लिये महिलाओं की विचारधारा पर आधारित है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अपने प्रश्नों को स्वयं एक महिला के साथ साझा करने में अधिक सहज़ महसूस करती हैं। अत: कथन 2 सही है।

79.

उत्तर: C

व्याख्या:

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) को वर्ष 2016 में शुरू किया गया तथा इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों या किसी भी तरह से फसल के खराब होने की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करना ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- PMFBY वर्तमान में किसान नामांकन के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी तथा औसतन 5.5 करोड़ आवेदन एवं प्राप्त प्रीमियम के मामले में यह तीसरी सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है।अत: कथन 3 सही है।

80.

उत्तर: A

व्याख्या:

- चुनावी बॉण्ड प्रॉमिसरी नोट्स के रुप में मुद्रा उपकरण होते हैं, जिन्हें भारत में कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से खरीदा जा सकता है तथा इसे किसी राजनीतिक दल को दान किया जा सकता है, जो बॉण्ड को भुना सकता है।
- केवल भारतीय स्टेट बैंक ही इन बॉण्डों को जारी करने और भुनाने के लिये अधिकृत है। अत: कथन 1 सही है।
- चुनावी बॉण्ड दाताओं द्वारा गुप्त रूप से खरीदे जाते हैं और जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिये वैध होते हैं।
- इन्हें केवल पात्र पार्टी द्वारा बैंक के साथ बनाए गए अपने निर्दिष्ट खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है।
- वर्ष 2018 में जब चुनावी बॉण्ड योजना पेश की गई थी, तो ये बॉण्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर में 10-10 दिनों की अवधि के लिये उपलब्ध कराए गए थे, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

81.

उत्तर: B

व्याख्या:

- ग्रीन बॉण्ड कंपनियों, देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से उन परियोजनाओं को कोष प्रदान करने के लिये जारी किये जाते हैं जिसके सकारात्मक पर्यावरणीय अथवा जलवायवीय लाभ होते हैं तथा निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इन परियोजनाओं के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और हरित इमारतें शामिल की जा सकती हैं। अत: कथन 2 सही है।

82.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भुगतान संतुलन (Balance Of Payment-BoP) का अभिप्राय ऐसे सांख्यिकी विवरण से होता है, जो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश के निवासियों के विश्व के साथ हुए मौद्रिक लेन-देनों के लेखांकन को रिकॉर्ड करता है।
- निर्यात में सुधार और आयात में गिरावट के कारण BoP मजबूत होता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- देश के BoP का उपयोग देश की मुद्रा के मूल्य में वृद्धि या मूल्यह्रास के संकेतक के रूप में किया जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- एक देश का BoP खाता तैयार करने के लिये विश्व के अन्य हिस्सों के बीच इसके आर्थिक लेन-देन को चालू खाते, पूंजी खाते और त्रुटियों तथा चूक के तहत वर्गीकृत किया जाता है।यह विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserve) में बदलाव को भी दर्शाता है।

83.

उत्तर: B

व्याख्या:

- पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक कार्यालय है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह 1898 में विस्फोटक, संपीड़ित गैसों और पेट्रोलियम जैसे पदार्थों की सुरक्षा को विनियमित करने के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। अत: कथन 2 सही है।
- इसका प्रधान कार्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में स्थित है।

84.

उत्तर: A

व्याख्या:

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs):

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वित्तीय संस्थान हैं जो कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिंहम वर्किंग ग्रुप (1975) की सिफारिशों के आधार पर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के विनियमन के बाद की गई थी। अत: कथन 1 सही है।
- पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक "प्रथम ग्रामीण बैंक" 2 अक्तूबर, 1975 को स्थापित किया गया था।
- RRBs को अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण के रूप में प्रदान करना आवश्यक है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की इक्विटी केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के पास 50:15:35 के अनुपात में होती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का उद्देश्य:
- ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों को ऋण और अन्य सुविधाएँ प्रदान करना।
- शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण जमा के बहिर्गमन की जाँच करना और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना तथा ग्रामीण रोज़गार सृजन में वृद्धि करना।

85.

उत्तर: C

व्याख्या:

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA):

- यह एक आपराधिक कानून है जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और इसे संबंधित मामलों से प्राप्त या इसमें शामिल संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिये बनाया गया है।
- यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।
- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- ED को अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति का पता लगाने, संपत्ति को अस्थायी रूप से संलग्न करने और अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चलाने और विशेष न्यायालय द्वारा संपत्ति की जब्ती सुनिश्चित करने के लिये ऐसे मामलों की जाँच करके PMLA के प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। अत: कथन 2 सही है।
- PMLA संशोधन अधिनियम 2012:
  - 'रिपोर्टिंग इकाई' की अवधारणा को सम्मिलित करता है जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि शामिल होंगे।
  - PMLA, 2002 ने 5 लाख रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया, लेकिन संशोधन अधिनियम ने इस ऊपरी सीमा को हटा दिया है।
  - इसने ऐसी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुर्की और जब्ती का प्रावधान किया है।

86.

उत्तर: C

व्याख्या:

- इनफिनिटी फोरम अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) का प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कार्यक्रम है, जो फिनटेक में महत्त्वपूर्ण विचारों का पता लगाने और आगे बढ़ाने के लिये नीति, व्यवसाय और प्रौद्योगिकी में दुनिया के अग्रणी विचारों को एकजुट करता है, तथा उन विचारों को वैश्विक समाधान एवं अवसरों में विकसित करता है। अत: कथन 1 सही है।
- बिग टेक के अंतर्गत अलीबाबा, अमेज़न, फेसबुक, गूगल और टेनसेंट जैसी कंपनियाँ शामिल हैं।
- गिफ्ट सिटी नियामक IFSCA और ब्लूमबर्ग वित्तीय प्रौद्योगिकी, नेतृत्व मंच की सह-मेज़बानी कर रहे हैं। अत: कथन 2 सही है।
- बिग टेक, फिनटेक क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिये एक समान अवसर प्रदान करने में एक बाधा हैं। अत: कथन 2 सही है।

87.

उत्तर: A

व्याख्या:

- यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है। इसके तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है जिसके तहत दोनों देशों के मध्य उत्पादन लागत बाकी देशों के मुकाबले सस्ता हो जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिये बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किये जाते हैं।
- मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

88.

उत्तर: A

व्याख्या:

भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र:

- हेलीकॉप्टरों की प्रमुख भूमिका शहरी संपर्क प्रदान करना है और साथ ही बचाव कार्यों आदि के दौरान आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ प्रदान करना तथा आपदा प्रबंधन में उपयोग इसके अन्य विविध कार्य हैं।
- भारत में नागरिक उड्डयन उद्योग पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सबसे तेज़ी से बढ़ते उद्योगों में से एक के रूप में उभरा है और इसे मोटे तौर पर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस, गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा शामिल है, जबकि चार्टर सेवा में ऑपरेटर, एयर टैक्सी, एयर कार्गो सेवा शामिल है। अत: कथन 1 सही है।

- महत्त्व:
  - वर्तमान में भारत दुनिया का 7वाँ सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाज़ार है और अगले 10 वर्षों में इसके तीसरा सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन बाज़ार बनने की उम्मीद है। अत: कथन 2 सही है।
  - इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के अनुसार, भारत अगले दस वर्षों में (2030 तक) दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हवाई यात्री बाज़ार के रूप में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकल सकता है।
  - भारत में हवाई यात्रा से संबंधित अनुमान के अनुसार, घरेलू यात्री यातायात वित्त वर्ष-2022 में 58.5% की वृद्धि के साथ 166.8 मिलियन तक पहुँच जाएगा और इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात प्रतिवर्ष 118% की वृद्धि के साथ 22.1 मिलियन तक पहुँच जाएगा।
- अवसर:
  - FDI: ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं के साथ-साथ रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहाल (MRO) सेवाओं तथा ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिये स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
  - विस्तार क्षेत्र: भारतीय नागरिक उड्डयन MRO बाज़ार, वर्तमान में लगभग 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है और वर्ष 2025 तक लगभग 14-15% की CAGR से बढ़कर 4.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है।
  - यह अनुमान है कि वर्ष 2038 तक देश के विमानों का बेड़ा चौगुना हो जाएगा जिसकी क्षमता लगभग 2500 विमान की होगी।
  - नए हवाई अड्डों को जोड़ना: सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक (उड़ान-UDAN-योजना के तहत) 100 हवाई अड्डों का विकास करना है और वैश्विक मानकों के अनुरूप विश्व स्तरीय नागरिक उड्डयन बुनियादी ढाँचा तैयार करना है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

89.

उत्तर: B

व्याख्या:

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध से तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये विश्व बैंक के साथ IMF की स्थापना की गई थी।
- दोनों संगठनों की स्थापना के लिये अमेरिका में ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन में सहमति बनी। इसलिये उन्हें ब्रेटन वुड्स के जुड़वाँ के रूप में जाना जाता है।
- IMF द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट:
  - वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
  - वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक
  - रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक
  - फिस्कल मॉनीटर
- चीफ इकोनोमिस्ट्स आउटलुक विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- अत: विकल्प B सही है।

90.

उत्तर: D

व्याख्या:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल:

- यह सार्वजनिक संपत्ति और/अथवा सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिये सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक व्यवस्था है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी बड़े पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं, जैसे सड़कों, पुलों, या अस्पतालों को निजी वित्त पोषण के साथ पूरा करने की अनुमति देती है।
- इस प्रकार की साझेदारी में निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के लिये निवेश किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- चूँकि PPP मॉडल में सेवाएँ प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा ज़िम्मेदारी का पूर्ण प्रतिधारण शामिल है, यह निजीकरण की प्रक्रिया नहीं है। अत: कथन 2 सही है।
- इसमें निजी और सार्वजनिक इकाई के मध्य जोखिम का एक सुव्यवस्थित तरीके से आवंटन होता है।

- निजी इकाई को खुली प्रतिस्पर्द्धी बोली के आधार पर चुना जाता है और वह प्रदर्शन आधारित भुगतान प्राप्त करती है। अत: कथन 3 सही है।
- PPP मार्ग उन विकासशील देशों में एक विकल्प हो सकता है, जहाँ सरकारों को महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये ऋण लेने में विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- यह बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाने या उन्हें क्रियान्वित करने में आवश्यक विशेषज्ञता भी प्रदान कर सकता है।

91.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारतीय संविधान ने करों के वितरण के साथ-साथ गैर-कर राजस्व और ऋण लेने की शक्ति से संबंधित विस्तृत प्रावधान किये हैं, जो राज्यों को संघ द्वारा सहायता अनुदान के प्रावधानों के पूरक हैं।
- अनुच्छेद 268 संघ द्वारा आरोपित कर के लिये प्रावधान करता है, लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है।
  - इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक आदि पर स्टांप शुल्क शामिल है। अत: कथन 1 सही है।
- अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाये गये और साथ ही एकत्र किये गये लेकिन राज्यों को सौंपे गये कर शामिल हैं।
  - इनमें अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं की बिक्री और खरीद पर कर या अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं के आवागमन पर कर शामिल हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।

92.

उत्तर: D

व्याख्या:

विदेशी मुद्रा भंडार:

- विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्ति है, जिसमें बाण्डॅ, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं। अत: कथन 1 सही है।
  - अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में रखे जाते हैं।
  - घटक:
  - विदेशी मुद्रा संपत्ति
  - स्वर्ण भंडार
  - विशेष आहरण अधिकार (SDR)
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ रिज़र्व स्थिति
  - अत: कथन 2 सही है।
  - महत्त्व:
  - मौद्रिक और विनिमय दर प्रबंधन के लिये नीतियों में समर्थन और विश्वास बनाये रखना। अत: कथन 3 सही है।
  - राष्ट्रीय या संघ मुद्रा के समर्थन में हस्तक्षेप करने की क्षमता प्रदान करता है।
  - संकट के समय या जब ऋण लेने की पहुँच में कटौती की जाती है, तो यह विदेशी मुद्रा तरलता को बनाये रखते हुये बाहरी कारकों को सीमित करता है।

93.

उत्तर: A

व्याख्या:

- स्थापना:
  - IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 के तहत की गई थी। अत: कथन 1 सही है।
  - इसका मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) की गिफ्ट सिटी (GIFT City) में स्थित है। अत: कथन 2 सही है।
- भूमिका:
  - यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास तथा विनियमन के लिये एक एकीकृत प्राधिकरण है।
  - वर्तमान में गुजरात के GIFT सिटी में स्थित IFSC भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
  - IFSCA की स्थापना से पूर्व घरेलू वित्तीय नियामक यथा RBI, SEBI, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) तथा पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) IFSC में व्यवसाय को विनियमित करने का कार्य करते थे।
- सदस्य:
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण में कुल नौ सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।
  - इनमें प्राधिकरण का अध्यक्ष, RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA का एक-एक सदस्य तथा वित्त मंत्रालय के दो सदस्य होते हैं। इसके अलावा चयन समिति की सिफारिश पर दो अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
  - कार्यकाल:
- IFSCA के सभी सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होता है, जो पुनर्नियुक्ति के अधीन होता है।

94.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल और इन-एप लेनदेन में उपयोग किये जाने वाले सभी क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड के लिये टोकनाइज़ेशन अनिवार्य कर दिया है।
- यह वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विवरण को "टोकन" नामक एक वैकल्पिक कोड में बदलने को संदर्भित करता है, जो कार्ड, टोकन अनुरोधकर्त्ता (वह इकाई जो कार्ड के टोकनाइज़ेशन के लिये ग्राहक का अनुरोध स्वीकार करता है और संबंधित टोकन जारी करने के लिये इसे कार्ड नेटवर्क पर भेजता है) तथा डिवाइस के संयोजन के लिये विशिष्ट होगा। अत: केवल कथन 3 सही है।

95.

उत्तर: B

व्याख्या:

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के तहत पंजीकृत हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- सेबी के तहत छह क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ क्रिसिल, इक्रा, केयर, एसएमईआरए, फिच इंडिया और ब्रिकवर्क रेटिंग्स पंजीकृत हैं।
- क्रेडिट रेटिंग के साथ, उधारदाताओं को किसी व्यक्ति या कंपनी (जो पैसा उधार ले रहा है) की क्रेडिट योग्यता और उनके साथ जुड़े जोखिम कारक के बारे में एक विचार मिलता है। इसका मूल्यांकन करके वे निवेश का बेहतर निर्णय ले सकते हैं। अत: कथन 2 सही है।

96.

उत्तर: A

व्याख्या:

डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA):

- डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA), एक ऐसा कानून जो ऑनलाइन सुरक्षा पर केंद्रित है और क्षेत्र के सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स नियमों को अद्यतन करता है, को यूरोपियन संघ (EU) का अंतिम अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
- जैसा कि यूरोपीय संघ आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है, DSA "एकल बाज़ार में बिचौलियों के दायित्वों और जवाबदेही पर सामान्य नियमों की एक सारणी" है तथा यूरोपीय संघ के सभी उपयोगकर्त्ताओं के लिये उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चाहे उनका देश कोई भी हो।
  - जब उपयोगकर्त्ता सामग्री को मॉडरेट करने की बात आती है तो DSA बिचौलियों, विशेष रूप से गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके को सख्ती से नियंत्रित करेगा।
- अत: विकल्प A सही है।

97.

उत्तर: A

व्याख्या:

- हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किये हैं।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) को वर्ष 1996 में प्रत्यायन के लिये एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। अत: कथन 2 सही है।
- तद्नुसार, QCI की स्थापना PPP मॉडल के माध्यम से स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार और तीन प्रमुख उद्योग संघों द्वारा प्रतिनिधित्व भारतीय उद्योग के समर्थन से की गई थी।
  - एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM)
  - भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)
  - फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI)
- QCI वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है। अत: कथन 1 सही है।
- QCI के संचालन हेतु नोडल एजेंसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है।
- यह सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के समान प्रतिनिधित्व के साथ 38 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित है।
- QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग जगत की ओर से की गई सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

98.

उतर: B

व्याख्या:

- हाल ही में एक राजनीतिक दल के प्रमुख ने देश में "समृद्धि" लाने के लिये केंद्र सरकार से नोटों (मुद्रा) पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश के चित्र छापने का अनुरोध किया।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और केंद्र सरकार बैंक नोटों तथा सिक्कों के डिज़ाइन एवं स्वरूप में बदलाव का फैसला करते हैं।
  - करेंसी नोट के डिज़ाइन में किसी भी बदलाव को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।
  - अत: कथन 1 सही नहीं है।

- सिक्का अधिनियम, 2011 केंद्र सरकार को विभिन्न मूल्यवर्ग के सिक्कों को डिज़ाइन करने और ढालने की शक्ति देता है।
  - आरबीआई की भूमिका केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सिक्कों के वितरण तक सीमित है।
  - अत: कथन 2 सही है।

99.

उत्तर: B

उत्तर:

- चुनावी बॉण्ड दाताओं द्वारा गुप्त रूप से खरीदे जाते हैं और ये बॉण्ड जारी करने की तारीख से पंद्रह दिनों तक वैध रहते हैं।.
  - ऋण साधनों के रूप में इन्हें दानदाताओं द्वारा बैंक से खरीदा जा सकता है और राजनीतिक दल उन्हें भुना सकते हैं।
- इन्हें केवल एक पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा बैंक के अपने खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है।
- चुनावी बॉण्ड SBI द्वारा बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किये जाते हैं।
- बॉण्ड किसी भी व्यक्ति (जो भारत का नागरिक है) द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्तूबर के महीनों में प्रत्येक दस दिनों की अवधि हेतु खरीद के लिये उपलब्ध होते हैं, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है।
- केवल भारतीय स्टेट बैंक इन बॉण्ड्स को जारी करने और भुनाने (Encash) के लिये अधिकृत बैंक है।
  - अत: कथन 1 सही नहीं है।
- केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम-से-कम 1% वोट प्राप्त किया है, वे चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।
  - अत: कथन 2 सही है।

100.

उत्तर: C

व्याख्या:

- सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):
  - CBDC कागज़ी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एवं समर्थित वैध मुद्रा है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ वन-टू-वन विनिमय योग्य है। अत: कथन 2 सही है।
  - फिएट मुद्रा एक राष्ट्रीय मुद्रा है, जो किसी वस्तु की कीमत जैसे सोने या चाँदी की कीमत पर नहीं आँकी जाती है।
  - ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या CBDC का लेन-देन किया जा सकता है।
  - हालाँकि CBDCs की अवधारणा बिटकॉइन से प्रेरित है, यह विकेंद्रीकृत आभासी मुद्राओं और क्रिप्टो परिसंपत्तियों से भिन्न है, जो राज्य द्वारा जारी नहीं की जाती हैं एवं न ही यह 'लीगल टेंडर' है।

101.

उत्तर: D

व्याख्या:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI):

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। अत: कथन 1 सही है।
  - FDI किसी निवेशक को एक बाहरी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- निवेशक कई तरह से FDI का लाभ उठा सकते हैं।
  - दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना करना, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का अधिग्रहण या विलय अथवा किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी इसके कुछ सामान्य तरीके हैं।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण चालक होने के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिये एक प्रमुख गैर-ऋण वित्तीय संसाधन भी रहा है। अत: कथन 2 सही है।
- यह विदेशी पोर्टफोलियो निवेश से अलग है जहाँ विदेशी संस्था केवल किसी कंपनी के स्टॉक और बॉण्ड खरीदती है।
  - FPI निवेशक को व्यवसाय पर नियंत्रण प्रदान नहीं करता है। अत: कथन 3 सही है।

102.

उत्तर: C

व्याख्या:

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के अध्यक्ष और अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बने रहेंगे। अत: कथन 1 सही है।
- बैठकों में निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिये जाते हैं।
- मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष (या बैठक की अध्यक्षता करने वाला सदस्य) दूसरा या निर्णायक मत देता है। अत: कथन 2 सही है।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करता है।

103.

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड की स्थापना वर्ष 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता नियम, 2016 द्वारा की गई थी।
- यह दिवाला पेशेवरों, दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला व्यावसायिक संस्थाओं और सूचना उपयोगिताओं का नियामक पर्यवेक्षण करता है।
  - अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह संहिता के तहत प्रक्रियाओं के लिये नियम बनाता और लागू करता है, अर्थात् कॉर्पोरेट दिवाला समाधान, कॉर्पोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवाला समाधान और व्यक्तिगत दिवालियापन।
- निम्नलिखित मामलों के संबंध में बोर्ड के पास वही शक्तियाँ हैं जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत एक दीवानी अदालत में निहित हैं, अर्थात्: -
  - ऐसे स्थान और ऐसे समय पर जो बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, खाते की पुस्तकों और अन्य दस्तावेज़ो की खोज़ और उत्पादन।
  - व्यक्तियों को बुलाना और उपस्थित कराना और शपथ पर उनका निरीक्षण।
  - किसी भी व्यक्ति की किसी भी स्थान पर किसी भी पुस्तक, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज़ो का निरीक्षण।
  - गवाहों या दस्तावेज़ो की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना।
  - अत: कथन 2 सही नहीं है।

104.

उत्तर: B

व्याख्या:

- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत कार्यरत एक सांविधिक प्राधिकरण है।
  - अत: कथन 1 सही है।
- बोर्ड के अधिकारी अपनी पदेन क्षमता में मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में भी कार्य करते हैं जो प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मामलों को देखता है।
- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:
  - केंद्रीय राजस्व बोर्ड, विभाग के सर्वोच्च निकाय के रूप में करों के प्रशासन के लिये ज़िम्मेदार, केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1924 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया।
  - प्रारंभ में बोर्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के करों का प्रभारी था। हालाँकि जब करों का प्रशासन एक बोर्ड को संभालने में सक्षम नहीं रहा तो बोर्ड को दो भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात् 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड।
  - अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - यह विभाजन केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 की धारा 3 के तहत दो बोर्डों के गठन द्वारा लाया गया था।
  - केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष और छह सदस्य होते हैं।
  - अत: कथन 3 सही है।
- अत: विकल्प B सही है।

105.

उत्तर: A

व्याख्या:

- सरकार द्वारा विशिष्ट उद्योगों पर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है जो आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप औसत से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- भू-राजनीतिक उथल-पुथल के कारण वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में उछाल के साथ कंपनियों को असामान्य लाभ कमाते हुए देखा जाने के बाद यह कर लगाया गया था।
- चूँकि अप्रत्याशित कर पूर्वव्यापी रूप में लगाए जाते हैं और प्राय: अप्रत्याशित घटनाओं से प्रभावित होते हैं, ये भविष्य के करों के बारे में बाज़ार में अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।

106.

उत्तर:B

व्याख्या:

- यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है:
- व्यापक क्षेत्र अर्थात् खनन, विनिर्माण और बिजली। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- उपयोग-आधारित क्षेत्र अर्थात् मूल सामान, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिये उपयोग किया जाने वाला आधार वर्ष 2011-2012 है।
- यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- IIP तिमाही और उन्नत सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिये बेहद प्रासंगिक है।

107.

उत्तर: D

व्याख्या:

भौगोलिक संकेतक (GI) टैग:

- परिचय:
- GI एक संकेतक है, जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिये किया जाता है।
  - 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं उन्हें बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
- वैधता:
  - भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।
- भौगोलिक संकेतक का महत्त्व:
  - एक बार भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान कर दिये जाने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिये इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी जानकारी की सुविधा प्रदान करता है। अत: कथन 1 सही है।
  - किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को रोकता है। अत: कथन 2 सही है।
  - यह कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतकों के निर्यात को बढ़ावा देता है और विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्य देशों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है।
  - GI टैग उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करता है। अत: कथन 3 सही है।
- अत: विकल्प D सही है।

108.

उत्तर: C

व्याख्या:

- रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें मूल्य भूमि, पूंजी और श्रम के पारंपरिक कारकों के बजाय रचनात्मक कल्पना के उपयोग पर आधारित होता है। यह अवधारणा जॉन हॉकिन्स द्वारा वर्ष 2001 में दी गई थी। अत: कथन 1 सही है।
- अर्थव्यवस्था का यह रूप केवल तभी संभव होता है जब व्यक्ति की रचनात्मकता, मूल्य का प्रमुख स्रोत और लेनदेन का मुख्य कारण बन जाती है।
- एक्ज़िम बैंक ऑफ़ इंडिया के एक दस्तावेज़ के अनुसार भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था जिसमें कला एवं शिल्प, ऑडियो और वीडियो कला तथा डिज़ाइन शामिल हैं, वर्ष 2019 में 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात किया गया।
  - रचनात्मक वस्तु और रचनात्मक सेवाएँ दोनों ही भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। अत: कथन 2 सही है।
- वर्ष 2019 तक भारत का रचनात्मक वस्तुओं और सेवाओं का कुल निर्यात 121 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब था, जिसमें से रचनात्मक सेवाओं का निर्यात लगभग 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

109.

उत्तर: A

व्याख्या:

- जब कोई देश IMF से उधार लेता है, तो उसकी सरकार उन समस्याओं को दूर करने के लिये अपनी आर्थिक नीतियों को समायोजित करने के लिये सहमत होती है। जिसके कारण उसे वित्तीय सहायता लेनी पड़ती है।
  - यह सशर्त देशों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हानिकारक उपकरणों का सहारा लिये बिना भुगतान संतुलन की समस्याओं को हल करने में मदद करता है। अत: कथन 1 सही है।
- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund-IMF) ने श्रीलंका के साथ चार वर्ष की अवधि के लिये 2.9 बिलियन अमेरीकी डॉलर के बेलआउट पैकेज़ पर एक प्रारंभिक समझौते को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य संकटग्रस्त दक्षिण एशियाई राष्ट्र के लिये आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता को बहाल करना है। अत: कथन 2 सही है।
- यह पैकेज़ को प्राप्त करने वाले देश की क्रेडिट रेटिंग को बढ़ा सकता है और अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों और निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा दे सकता है जो कि किश्तों के मध्य अंतराल को बंद करने के लिये ब्रिज़ वित्तपोषण प्रदान करने के लिये निवेदन कर सकते हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।

110.

उत्तर: A

व्याख्या:

- पेरेस्त्रोइका का अर्थ है "पुनर्गठन", विशेष रूप से साम्यवादी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था का सोवियत अर्थव्यवस्था में बाज़ार अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को शामिल करके। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण भी हुआ।

- ग्लासनोस्त का अर्थ है- "खुलापन", विशेष रूप से सूचनाओं के संदर्भ में पारदर्शिता, इसी क्रम में सोवियत संघ का लोकतंत्रीकरण शुरू हुआ। अत: विकल्प A सही है।

111.

उत्तर: C

व्याख्या:

- भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) एक गैर-सरकारी एवं गैर-लाभकारी संगठन है। अत: कथन 1 सही है।
- वर्ष 1927 में स्थापित, यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापार संगठन है। इसका इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अत: कथन 2 सही है।
- यह बहस को प्रोत्साहित करने के लिये नीति को प्रभावित करता है और नीति निर्माताओं तथा नागरिक समाज के साथ जुड़कर, फिक्की उद्योग के विचारों एवं चिंताओं को व्यक्त करता है। यह भारतीय निजी एवं सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्रों व बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अपने सदस्यों को सेवा एवं सुविधा प्रदान करता है।
- यह एक क्षेत्र के भीतर और सभी क्षेत्रों में नेटवर्किंग एवं आम सहमति बनाने के लिये एक मंच प्रदान करता है साथ ही भारतीय उद्योग, नीति निर्माताओं तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिये भी एक मंच का कार्य करता है।

112.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में एथेरियम ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पूरी तरह से "प्रूफ-ऑफ वर्क' से 'प्रूफ-ऑफ-स्टेक' सर्वसम्मति तंत्र में परिवर्तित हो गया है।
  - प्रूफ-ऑफ वर्क: एक विकेंद्रीकृत मंच के रूप में एथेरियम के पास बैंक जैसे संस्थान नहीं हैं जो अपने नेटवर्क पर होने वाले लेन-देन को मंज़ूरी देते हैं, अनुमोदन पहले प्रूफ-ऑफ वर्क (PoW) सर्वसम्मति तंत्र के तहत हो रहे थे जो अनिवार्य रूप से खनिकों (Miners) द्वारा किया जाता था
- इसके तहत खनिक अत्याधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर के विशाल बुनियादी ढाँचे का उपयोग करके जटिल गणितीय पहेली को हल करने के लिये प्रतिस्पर्द्धा करेंगे और पहेली को हल करने वाले पहले व्यक्ति को सत्यापनकर्त्ता के रूप में चुना जाएगा।
- यह विधि लगभग पूरी तरह से क्रिप्टो फार्मों पर निर्भर थी, जो कंप्यूटर के बड़े पैमाने पर उपयोग कर समस्याओं को हल करेंगे। अत: कथन 1 सही है।
- हिस्सेदारी का प्रमाण (Proof of Stake): यह उन क्रिप्टो खनिकों और विशाल माइनिंग फार्म की आवश्यकता को अलग कर देगा, जिन्होंने पहले ब्लॉकचेन को 'प्रूफ-ऑफ-वर्क' (PoW) नामक एक तंत्र के तहत संचालित किया था।
  - इसके बजाय यह अब 'प्रूफ-ऑफ-स्टेक' (PoS) तंत्र में स्थानांतरित हो गया है जो लेन-देन की मंज़ूरी देने के लिये यादृच्छिक रूप से 'सत्यापनकर्त्ता' प्रदान करता है।
  - सत्यापनकर्त्ता वे लोग होते हैं जो पहले ब्लॉक से आखिरी तक लिंकेज की लगातार गणना करके ब्लॉकचेन की अखंडता को बनाए रखने के लिये कंप्यूटर को स्वेच्छा से रखते हैं। अत: कथन 2 सही है।

113.

उत्तर: D

व्याख्या:

- उच्च आयात प्रतिस्थापन और रोज़गार सृजन के साथ घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिये PLI योजना की कल्पना की गई थी।
- सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों हेतु PLI योजनाओं के तहत 1.97 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया तथा वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में सौर PV मॉड्यूल के लिये PLI हेतु 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
- मार्च 2020 में शुरू की गई इस योजना ने शुरू में तीन उद्योगों को लक्षित किया था:
- मोबाइल और संबद्ध घटक निर्माण
- विद्युत घटक निर्माण
- चिकित्सा उपकरण, अत: कथन 1 सही है।
- सरकार ने चीन एवं अन्य देशों पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिये इस योजना की शुरुआत की है।
- यह श्रम प्रधान क्षेत्रों का समर्थन करती है और भारत में रोज़गार अनुपात को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।
- यह योजना आयात बिलों को कम करने एवं घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये भी काम करती है।
- हालाँकि PLI योजना विदेशी कंपनियों को भारत में अपनी इकाइयाँ स्थापित करने के लिये आमंत्रित करती है और घरेलू उद्यमों को अपनी उत्पादन इकाइयों का विस्तार करने हेतु प्रोत्साहित करती है। अत: कथन 2 सही है।
- संवर्द्धित बिक्री के आधार पर गणना की गई प्रोत्साहन राशि, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिये न्यूनतम 1% से लेकर औषधियों के संबंध में अधिकतम 20% तक है। अत: कथन 3 सही है।

114.

उत्तर: B

व्याख्या:

- वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) वित्त मंत्रालय के

तहत एक गैर-सांविधिक शीर्ष परिषद है तथा इसकी स्थापना वर्ष 2010 में एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गई थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।

- FSDC की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले वित्तीय क्षेत्र के सुधारों पर गठित रघुराम राजन समिति (2008) द्वारा किया गया था। अत: कथन 2 सही है।
- संरचना:
  - इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके सदस्यों में वित्तीय क्षेत्र के सभी नियामकों (RBI, SEBI, PFRDA और IRDA) के प्रमुख, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हैं।
  - वर्ष 2018 में सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के ज़िम्मेदार राज्य मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड (IBBI) के अध्यक्ष तथा राजस्व सचिव को शामिल करने के उद्देश्य से FSDC का पुनर्गठन किया।
  - FSDC उप-समिति की अध्यक्षता RBI के गवर्नर द्वारा की जाती है।
  - आवश्यकता पड़ने पर यह परिषद विशेषज्ञों को भी अपनी बैठक में आमंत्रित कर सकती है।

115.

उत्तर: C

व्याख्या:

- एक यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाज़ार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
  - यह अन्य उत्पादों/सेवाओं के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल पेश करने के लिये समर्पित नई संस्थाओं की उपस्थिति को दर्शाता है।अत: कथन 1 सही नहीं है।
- भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बन गया है।
- भारत में 75,000 स्टार्टअप हैं।
- 49% स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से हैं।
  - वर्तमान में 105 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 44 वर्ष 2021 में और 19 वर्ष 2022 में बना। अत: कथन 2 सही है।
- प्रारंभ (Prarambh): 'प्रारंभ' शिखर सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के स्टार्ट अप और युवांओं को नए विचारों, नवाचारों और आविष्कारो हेतु एक साथ आने के लिये मंच प्रदान करना है। अत: कथन 3 सही है।

116.

उत्तर: A

व्याख्या:

- एकीकृत लोकपाल योजना भारतीय रिज़र्व बैंक विनियमित संस्थाएँ जैसे बैंक, एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट प्लेयर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में कमी से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण प्रदान करेगी, अगर शिकायत का समाधान ग्राहकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है या विनियमित इकाई द्वारा 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों को त्वरित और लागत प्रभावी तरीके से हल करने के लिये शुरू की गई थी।
- यह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की तीन लोकपाल योजनाओं- वर्ष 2006 की बैंकिंग लोकपाल योजना, वर्ष 2018 की NBFCs के लिये लोकपाल योजना और वर्ष 2019 की डिजिटल लेन-देन की लोकपाल योजना को समाहित करता है। अत: कथन 2 सही है।

117.

उत्तर: A

व्याख्या:

- इसे आत्मनिर्भर अभियान (वर्ष 2020) के तहत शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है।
- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। अत: कथन 1 सही है।
- यह योजना आगत खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में लाभ उठाने के लिये एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

118.

उत्तर: D

व्याख्या:

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI):

- UIDAI, आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों का पालन करते हुए 12 जुलाई 2016 को भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।

- UIDAI की स्थापना भारत सरकार द्वारा जनवरी 2009 में योजना आयोग के तत्त्वावधान में एक संलग्न कार्यालय के रूप में की गई थी।
- आधार ने गरीबों को एक सत्यापन योग्य पहचान प्रदान करके बैंक खाते खोलने की सुविधा प्रदान की है, इसने 'फिक्स-ऑल' समाधान होने का दावा करके वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से आकर्षित किया है। अत: कथन 1 सही है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण:

- बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने शाखाओं के विस्तार में मदद की और इस तरह अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच बनाई। इसके अलावा, कृषि, लघु उद्योगों और संबद्ध क्षेत्रों के ऋण वितरण में भी वृद्धि हुई है। अत: कथन 2 सही है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी):

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सरकार द्वारा प्रायोजित क्षेत्र-आधारित ग्रामीण ऋण देने वाली संस्थाओं के रूप में स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थानीय अभिविन्यास और सहकारी समितियों की लघु-स्तरीय ऋण संस्कृति और वाणिज्यिक बैंकों की व्यावसायिक संस्कृति के संयोजन के रूप में हाइब्रिड माइक्रो बैंकिंग संस्थानों के रूप में चिह्नित किया गया था। अत: कथन 3 सही है।

119.

उत्तर: D

व्याख्या:

- बेनामी लेन-देन उन लेन-देन को संदर्भित करता है जिसमें लेन-देन के वास्तविक लाभार्थी और जिस व्यक्ति के नाम पर लेनदेन (विशेष रूप से संपत्तियों से संबंधित लेन-देन) किया जाता है, अलग-अलग होते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- धारा 5:
  - संपत्ति का स्वामित्व एक व्यक्ति के पास होता है, जबकि इसके लिये भुगतान करने वाला दूसरा व्यक्ति होता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - न्यायालय के अनुसार इस प्रावधान को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

120.

उत्तर: A

व्याख्या:

- व्यापक भागीदारी समझौता (CEPA) एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है जो सेवाओं और निवेश में व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर होने वाली वार्ता को शामिल करता है ।
- यह व्यापार सुविधा और सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे क्षेत्रों में पर भी विचार करता है।
- भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और जापान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किये हैं। अत: विकल्प A सही है।

121.

उत्तर: D

व्याख्या:

- CBDC कागज़ी मुद्रा का डिजिटल रूप है और किसी भी नियामक संस्था द्वारा संचालित नहीं होने वाली क्रिप्टोकरेंसी के विपरीत केंद्रीय बैंक द्वारा जारी और समर्थित वैध मुद्रा है।
- यह फिएट मुद्रा के समान है और फिएट मुद्रा के साथ वन टू वन विनिमय योग्य है।
  - ब्लॉकचेन द्वारा समर्थित वॉलेट का उपयोग करके डिजिटल फिएट मुद्रा या CBDC का लेन-देन किया जा सकता है।
  - अत: कथन 1 सही नहीं है।
- बहामा अपनी राष्ट्रव्यापी CBDC सैंड डॉलर लॉन्च करने वाली पहली अर्थव्यवस्था है।
  - नाइज़ीरिया एक और देश है जिसने वर्ष 2020 में ईनायरा (eNaira) शुरू किया है।
  - चीन अप्रैल 2020 में डिजिटल मुद्रा e-CNY का संचालन करने वाली दुनिया की पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया।
  - अत: कथन 2 सही नहीं है।

122.

उत्तर: C

व्याख्या:

- भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज:
  - यह भारत में विद्युत के भौतिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र के लिये एक राष्ट्रव्यापी, स्वचालित व्यापार मंच प्रदान करने वाला पहला और सबसे बड़ा ऊर्जा एक्सचेंज है।
  - यह एक्सचेंज उचित मूल्य निर्धारण में सक्षम बनाता है और व्यापार निष्पादन की गति और दक्षता को बढ़ाते हुए भारत में विद्युत बाज़ार तक पहुँच और पारदर्शिता को बढ़ाता है।
  - यह 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज' (NSE) और 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज' (BSE) के साथ सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) द्वारा अनुमोदित और विनियमित है तथा वर्ष 2008 से कार्यरत है। अत: कथन 2 सही है।

- उद्देश्य:
  - उपभोक्ताओं की वहनीय ऊर्जा तक पहुँच स्थापित करने के लिये पारदर्शी और कुशल ऊर्जा बाज़ार स्थापित करके प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना।

123.

उत्तर: B

व्याख्या:

- शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य (Air Quality and Health in Cities) शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें वर्ष 2010 और 2019 के बीच दुनिया भर के 7,000 से अधिक शहरों में प्रदूषण और वैश्विक स्वास्थ्य प्रभावों का विश्लेषण किया गया था।
- अध्ययन में पाए गए दो प्रमुख वायु प्रदूषकों- फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO_2) के आधार पर शहरों की रैंकिंग की गई।
- भारत के संदर्भ में विशिष्ट निष्कर्ष:
- PM 2.5 का स्तर:
  - PM 2.5 स्तर के मामले में शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली और कोलकाता क्रमश: पहले एवं दूसरे स्थान पर हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- NO_2 स्तर:
  - NO_2 स्तर के संबंध में कोई भी भारतीय शहर शीर्ष 10 या शीर्ष 20 प्रदूषित शहरों की सूची में शामिल नहीं है। अत: कथन 2 सही है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में NO_2 का औसत स्तर 20-30 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के बीच है।
- होने वाली मौतें:
  - दिल्ली को प्रति 100,000 में 106 मौतों के साथ छठे और कोलकाता को 99 मौतों के साथ आठवें स्थान पर रखा गया है ।

124.

उत्तर: D

व्याख्या:

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी उस संस्था को कहते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत है और जिसका मुख्य काम उधार देना तथा विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार तथा चिटफंड से संबंधित कार्यों में निवेश करना है।
  - अत: कथन 1 सही नहीं है।
- जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिये उपलब्ध नहीं है।.
- एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता।
  - अत: कथन 2 सही नहीं है।

125.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक, अधिनियम, 1934 (RBI अधिनियम, 1934) (2016 में संशोधित) के तहत, आरबीआई को भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुये मूल्य स्थिरता बनाए रखना है।
- RBI अधिनियम, 1934 केंद्र सरकार को छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) गठित करने का अधिकार देता है। अत: कथन 1 सही नहीं है और कथन 2 सही है।
- RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

126.

उत्तर: A

व्याख्या:

- स्वर्ण/गोल्ड ETF (जिसका उद्देश्य घरेलू भौतिक सोने की कीमत को ट्रैक करना है) निष्क्रिय निवेश साधन हैं जो सोने की कीमतों पर आधारित होते हैं तथा सोने को बुलियन में निवेश करते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- गोल्ड ETF भौतिक सोने का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयाँ हैं जो कागज या डीमैट रूप में हो सकती हैं
- एक गोल्ड ETF इकाई 1 ग्राम सोने के बराबर होती है और इसमें उच्च शुद्धता का भौतिक सोना होता है। यह असाधारण रूप से शुद्ध भौतिक सोने द्वारा समर्थित होती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

127.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित स्वायत्त वैधानिक निकाय है।
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार FSSAI का प्रशासनिक मंत्रालय है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- FSSAI में एक अध्यक्ष और 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएँ होती हैं। अत: कथन 2 सही है।

- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के रूप में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने वर्ष 2016 में अधिसूचनाओं के माध्यम से उत्पाद-दर-उत्पाद अनुमोदन से घटक तथा योज्य-आधारित अनुमोदन प्रक्रिया में स्थानांतरित कर लिया है।

128.

उत्तर: C

व्याख्या:

- वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार (GoI) ने एकीकृत बाल विकास योजनाओं (ICDS) और पोषण (प्रधान मंत्री की समग्र पोषण योजना) अभियान को सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 में पुनर्गठित किया।
- पुनर्गठित योजना में निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल हैं:
  - ICDS
  - पोषण अभियान
  - किशोरियों के लिये योजना (SAG)
  - राष्ट्रीय शिशु गृह योजना
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
  - आयुष मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह योजना कार्यान्वयन के लिये तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- मिशन इंद्रधनुष को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उन बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित करने के लिये शुरू किया गया था, जिनका या तो UIP के तहत टीकाकरण नहीं हुआ है या आंशिक रूप से टीकाकरण किया गया है।
  - यह 12 वैक्सीन-निवारक रोगों (VPD) यानी डिप्थीरिया, काली खाँसी, टेटनस, पोलियो, तपेदिक, हेपेटाइटिस बी, मेनिन्जाइटिस और निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी संक्रमण, जापानी एन्सेफलाइटिस (JE), रोटावायरस वैक्सीन, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV) और खसरा-रूबेला (MR) के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करता है।
  - हालाँकि देश के चुनिंदा ज़िलों में जापानी इंसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के खिलाफ टीकाकरण प्रदान किया जा रहा है। अत: विकल्प C सही है।

129.

3. उत्तर: B

व्याख्या:

- बिक्री के XXI चरण में, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉण्ड जारी करने और भुनाने की अनुमति दी गई है। ये बॉण्ड केवल भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किये जा सकते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए के तहत ऐसे पंजीकृत राजनीतिक दल जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम-से-कम 1% वोट प्राप्त किया है, वे चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।
- चुनावी बॉण्ड जारी होने के दिन से शुरू होने वाले पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिये वैध होते हैं। अत: कथन 2 सही है।
- यदि वैधता अवधि बीत जाने के बाद चुनावी बॉण्ड जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

130.

उत्तर: A

व्याख्या:

- पीरियड पॉवर्टी तब होती है जब कम आय वाले लोग आवश्यक पीरियड प्रोडक्ट/उत्पादों (जैसे टैम्पोन, सैनिटरी पैड आदि) को वहन नहीं कर सकते या उन तक पहुँच नहीं बना सकते। अत: कथन 1 सही है।
- स्कॉटलैंड फ्री पीरियड प्रोडक्ट तक पहुँच के अधिकार की कानूनी रूप से रक्षा करने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है और इसने पीरियड प्रोडक्ट एक्ट पारित करके पीरियड प्रोडक्ट को सभी के लिये नि:शुल्क कर दिया है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- शुचि योजना का उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करना है और यह फ्री पीरियड के उत्पाद प्रदान नहीं करती है।
- इसे वर्ष 2013-14 में केंद्र प्रायोजित के रूप में शुरू किया गया था। हालाँकि, केंद्र ने राज्यों को वर्ष 2015-16 से इस योजना को अपने नियंत्रण में लेने के लिये कहा। अत: कथन 3 सही नहीं है।

131.

उत्तर: B

व्याख्या:

- नाबार्ड (NABARD) विकास बैंक है जो मुख्य रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्र पर केंद्रित है। इसका मुख्यालय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है।
- यह वर्ष 1982 में संसदीय अधिनियम-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिये वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। अत: कथन 2 सही है।

132.

उत्तर: C

व्याख्या:

A. डिजिटल मुद्रा एक भुगतान विधि है जो केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मौजूद है और मूर्त नहीं है। डिजिटल मुद्रा को डिजिटल मनी और साइबर कैश के नाम से भी जाना जाता है।

a. डिजिटल मुद्राओं को केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत किया जा सकता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

- फिएट मुद्रा, यह भौतिक रूप में मौजूद होती है, जो एक केंद्रीय बैंक और सरकारी एजेंसियों द्वारा उत्पादन और वितरण की एक केंद्रीकृत प्रणाली है। प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी, जैसे कि- बिटकॉइन और एथेरियम, विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा प्रणाली के उदाहरण हैं। अत: कथन 2 सही है।
- केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएँ (CBDC) किसी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई विनियमित डिजिटल मुद्राएँ हैं। अत: कथन 3 सही है।
- CBDC पारंपरिक फिएट मुद्रा का पूरक या प्रतिस्थापन हो सकता है।
- फिएट मुद्रा के विपरीत (जो भौतिक और डिजिटल दोनों रूपों में मौजूद है) CBDC विशुद्ध रूप से डिजिटल रूप में मौजूद है।
- इंग्लैंड, स्वीडन और उरुग्वे कुछ ऐसे देश हैं जो अपनी मूल फिएट मुद्राओं का डिजिटल संस्करण लॉन्च करने की योजना पर विचार कर रहे हैं।

133.

उत्तर: C

व्याख्या:

- आठ कोर सेक्टर:
  - कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली।
- आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योग उनके भारांक के घटते क्रम में:
  - रिफाइनरी उत्पाद> बिजली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक। अत: विकल्प C सही है।

134.

उत्तर: D

व्याख्या:

- नीली अर्थव्यवस्था से तात्पर्य आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों र महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के लिये समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग से है।
  - यह उच्च उत्पादकता और समुद्र के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिये महासागर विकास रणनीतियों को मज़बूत करने की वकालत करता है।
- नीली अर्थव्यवस्था से संबंधित पहलें:
  - सागरमाला कार्यक्रम को वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ समग्र बंदरगाह बुनियादी ढाँचे का विकास करना है।
  - इस बंदरगाह के नेतृत्व वाले विकास ढाँचे के तहत सरकार को अपने कार्गो यातायात को तीन गुना बढ़ाने की उम्मीद है।
  - महासागर सेवाएँ, प्रौद्योगिकी, अवलोकन, संसाधन मॉडलिंग और विज्ञान (ओ-स्मार्ट) में सेवाओं, प्रौद्योगिकी, संसाधन, अवलोकन तथा विज्ञान जैसे महासागर विकास गतिविधियों को संबोधित करने वाली कुल 16 उप-परियोजनाएँ शामिल हैं।
  - राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति समुद्री मात्स्यिकी पर राष्ट्रीय नीति, 2017 (NPMF), मसौदा राष्ट्रीय अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि नीति (NIFAP). मसौदा राष्ट्रीय समुद्री कृषि नीति (NMP) को फसल के बाद के तत्त्वों के साथ एकीकृत करती है। अत: विकल्प D सही है।

135.

उत्तर: B

व्याख्या:

- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2017 में निर्यात योजना (TIES) के लिये व्यापार बुनियादी ढाँचा शुरू किया। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इसका उद्देश्य निर्यात की वृद्धि के लिये उपयुक्त बुनियादी ढाँचे के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता करना है।
- बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये केंद्र सरकार की सहायता अनुदान सहायता के रूप में होगी। अत: कथन 2 सही है।
- सहायता अनुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दी गई सहायता, दान या योगदान की प्रकृति का भुगतान है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और/या पंचायती राज संस्थाओं को सहायता अनुदान दिया जाता है।

136.

उत्तर: C

व्याख्या:

- बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) का लक्ष्य केंद्रीय बैंकों के लिये एक बैंक के रूप में कार्य करना और वैश्विक सहयोग के

माध्यम से मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने के लिये केंद्रीय बैंकों के प्रयासों में सहायता करना है। अत: कथन 1 सही है।

- BIS का मिशन:
  - BIS प्रदर्शन में उत्कृष्टता के माध्यम से मान्यता प्रदान करता है।
  - निरंतर सुधार और नवाचार के लिये प्रतिबद्ध है।
  - यह सत्यनिष्ठा के साथ काम करता है।
  - BIS विविधता, समावेशन, स्थिरता और सामाजिक ज़िम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
- बैंक पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (बीसीबीएस) अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के भीतर एक समिति है। अत: कथन 2 सही है।
- बीआईएस का स्वामित्व 63 केंद्रीय बैंकों के पास है, जो दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो एक साथ विश्व सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 95% हिस्सा हैं।
- इसका प्रधान कार्यालय बेसल, स्विटज़रलैंड में है।

137.

उत्तर: D

व्याख्या:

- मात्स्यिकी सब्सिडी पर समझौता गहरे समुद्री क्षेत्र जो कि तटीय देशों और क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों/व्यवस्थाओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, में मछली पकड़ने के मामले में भी सब्सिडी प्रदान करने पर रोक लगाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह समझौता वैश्विक मछली स्टॉक की बेहतर सुरक्षा के लिये अवैध, गैर-सूचित और अनियमित तरीके (IUU) से मछली पकड़ने के मामले में सब्सिडी पर रोक लगाएगा।
- यह गैर-सूचित और अनियमित तरीके से मछली पकड़ने में लगे जहांज़ों या ऑपरेटरों को दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर देगा।
- विशेष और विभेदक उपचार (S&DT) के तहत विकासशील देशों तथा अल्प विकसित देशों (LDC) को इस समझौते के लागू होने की तारीख से दो साल की संक्रमण अवधि की अनुमति दी गई है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

138.

उत्तर: B

व्याख्या:

- रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) की रणनीतिक भूमिका को ध्यान में रखते हुए 'फार्मास्युटिकल उद्योग को सुदृढ़ बनाने' (SPI) के लिये योजना शुरू की है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह योजना फार्मास्युटिकल क्षेत्र में MSME इकाइयों के प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिये क्रेडिट लिंक्ड पूंजी और ब्याज़ सब्सिडी प्रदान करती है।
- इसमें फार्मा क्लस्टर्स में रिसर्च सेंटर, टेस्टिंग लैब और ETP (इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) सहित सामान्य सुविधाओं के लिये 20 करोड़ रुपए तक की सहायता प्रदान करना शामिल है। अत: कथन 2 सही है।
- MSME इकाई के पास पूंजीगत सब्सिडी या इंटरेस्ट छूट में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।

139.

उत्तर: C

व्याख्या:

- विंडफॉल टैक्स किसी विशेष कंपनी या उद्योग को हुए अचानक बड़े मुनाफे पर लगाया गया उच्च कर दर है। अत: कथन 1 सही है।
- भारत सरकार ने हाल ही में डीज़ल और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर लगाए गए उपकरों एवं शुल्कों में कटौती की है तथा वैश्विक मंदी की आशंका के बीच पेट्रोल के निर्यात पर उपकर हटा दिया है। अत: कथन 2 सही है।
- पेट्रोल के निर्यात पर 6 रुपए प्रति लीटर के बराबर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटा दिया गया है।

140.

उत्तर: A

व्याख्या:

डिजिटल बैंक:

- इसे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में परिभाषित किया जाएगा और अपनी बैलेंस शीटों के साथ इसका कानूनी अस्तित्व होगा। अत: कथन 1 और 2 सही हैं।
- यह केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) से अलग होगा, जो कि कम सेवा वाले क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान, बैंकिंग और फिनटेक नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिये स्थापित किये जा रहे हैं।
- DBU विशेष निश्चित बिंदु व्यापार इकाई या डिजिटल बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं को वितरित करने के साथ-साथ मौजूदा वित्तीय उत्पादों एवं सेवाओं को किसी भी समय स्वयं सेवा मोड में डिजिटल रूप से सुविधा प्रदान करने के लिये कुछ न्यूनतम डिजिटल आधारभूत संरचनाओं का हब है।
- डिजिटल बैंक मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों के समान विवेकपूर्ण और तरलता मानदंडों के अधीन होंगे। अत: कथन 3 सही नहीं है।

141.

उत्तर: B

व्याख्या:

- स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि MSP में सरकार को उत्पादन की औसत लागत के कम-से-कम 50% की वृद्धि करनी चाहिये। इसे C2+50% सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- C2+50 सूत्र, MSP की गणना करती है जिसमें इनपुट की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है।
- इसमें A2 की गणना के लिये उपयोग किये जाने वाले कारकों के अलावा खेत पर काम करने वाले परिवार के सदस्यों के प्रयासों का आर्थिक मूल्य तथा किराए और अन्य संपत्ति (C2) सहित अन्य खर्चों का मूल्य शामिल है। अत: कथन 2 सही है।

142.

उत्तर: A

व्याख्या:

- किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिये एक लिखित समझौते के रूप में एक ज़मानती बॉण्ड को अपने सरल रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- बीमा कंपनी द्वारा ठेकेदार की ओर से उस संस्था को ज़मानती बॉण्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना शुरू कर रही है। अत: कथन 1 सही है।
- ज़मानत एक अद्वितीयक प्रकार का बीमा है क्योंकि इसमें तीन-पक्षीय समझौता शामिल है। एक ज़मानत समझौते में तीन पक्ष होते हैं:
  - मुख्य पक्ष- वह पक्ष जो बॉण्ड खरीदता है और वादे के अनुसार कार्य करने का दायित्व लेता है।
  - ज़मानत पक्ष- दायित्व की गारंटी देने वाली बीमा कंपनी या ज़मानत कंपनी का प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मुख्य पक्ष वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, तो ज़मानत पक्ष निरंतर नुकसान के लिये संविदात्मक रूप से उत्तरदायी है।
  - ओब्लिगी- जिस पार्टी की आवश्यकता होती है वह प्राय: ज़मानती बॉण्ड से लाभ प्राप्त करता है। अधिकांश ज़मानती बॉण्ड के लिये 'ओब्लिगी' एक स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारी संगठन होता है।
  - अत: कथन 2 सही नहीं है।

143.

उत्तर: B

व्याख्या:

रिवर्स करेंसी वॉर:

- अमेरिकी फेडरल रिज़र्व की आक्रामक रूप से ब्याज़ दरें बढ़ाने की कार्रवाई का एक दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका में निवेश करने के लिये अधिक-से-अधिक निवेशक आकर्षित हो रहे हैं।
  - इसने बदले में डॉलर को अन्य सभी मुद्राओं की तुलना में मज़बूत बना दिया है क्योंकि येन, यूरो, युआन आदि की तुलना में डॉलर की अधिक मांग है।
- डॉलर के मुकाबले अन्य देशों की स्थानीय मुद्रा की सापेक्ष कमज़ोरी उनके निर्यात को और अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाती है।
  - उदाहरण के लिये चीनी या भारतीय निर्यातक को अधिक बढ़ावा मिलता है।
  - अतीत में अमेरिका ने अन्य देशों पर अपनी मुद्रा में हेरफेर करने (डॉलर के मुकाबले इसे कमज़ोर रखने) का आरोप लगाया है ताकि वे अमेरिका के खिलाफ व्यापार अधिशेष का लाभ उठा सकें।
  - इसे करेंसी वॉर या मुद्रा युद्ध कहा जाता है। अत: विकल्प B सही है।

144.

उत्तर: D

व्याख्या:

- इसे एक ऐसे ग्राहक के रूप में चित्रित किया जाएगा जो उपभोक्ताओं के रूप में अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है और अपनी समस्याओं का जवाब मांग रहा है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह विभिन्न सरकारी पहलों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता का विस्तार करने में मदद करेगा जैसे:
  - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान
  - हॉलमार्किंग
  - राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915
  - वज़न और माप अधिनियम के प्रावधान
  - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय
  - शिकायत निवारण पर उपभोक्ताओं द्वारा प्रशंसापत्र
- उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जागृति शुभंकर पेश किया है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- कई मीडिया अभियानों में इसे "जागो ग्राहक जागो" के नारे के साथ प्रदर्शित किया जाएगा।

145.

उत्तर: C

व्याख्या:

इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ)

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) ने निर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव ज़ोन या पर्यावरण संवेदी क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिये।
  - हालाँकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में "इको-सेंसिटिव ज़ोन" शब्द का उल्लेख नहीं है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - अधिनियम की धारा 3(2)(v) में कहा गया है कि केंद्र सरकार उन क्षेत्रों को प्रतिबंधित कर सकती है जिनमें कोई उद्योग, संचालन या प्रक्रिया नहीं की जाएगी या कुछ सुरक्षा उपायों के अधीन किया जाएगा।
  - इस अधिनियम की धारा 5 (1) के अलावा केंद्र सरकार उद्योगों के स्थान को प्रतिबंधित कर सकती है और कुछ कार्यों या प्रक्रियाओं को किसी क्षेत्र की जैविक विविधता, प्रदूषकों की एकाग्रता की अधिकतम स्वीकार्य सीमा जैसे विचारों के आधार पर कर सकती है।
- सरकार द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों या पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्रों (EFA) को घोषित करने के लिये उपरोक्त दो खंडों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है।
- जबकि 10 किमी. के नियम को एक सामान्य सिद्धांत के रूप में लागू किया जाता है, इसके आवेदन की सीमा भिन्न हो सकती है।
- वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओ से 10 किमी. से अधिक के क्षेत्रों को भी केंद्र सरकार द्वारा ESZ के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है, यदि वे पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण "संवेदनशील गलियारे" हैं।
- ESZs को संरक्षित क्षेत्रों के लिये "शॉक एब्जॉर्बर" के रूप में बनाया गया है ताकि आस-पास होने वाली कुछ मानवीय गतिविधियों के "कमज़ोर पारिस्थितिक तंत्र" पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र चारों ओर एक समान नहीं हो सकते हैं।

146.

उत्तर: D

व्याख्या:

DIGI यात्रा:

- 'डिजी यात्रा' नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समन्वित एक पहल है। अत: कथन 1 सही है।
- डिजी यात्रा हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिये डिजिटल प्रक्रिया है। चेक प्वाइंट पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों को स्वचालित रूप से संसाधित किया जाएगा जैसे; एंट्री पॉइंट चेक, एंट्री इन टू सिक्योरिटी चेक, एयरक्राफ्ट बोर्डिंग, इसके अतिरिक्त पैक्स और डेटा रिकॉल की पहचान के लिये चेहरे की पहचान का उपयोग करके सेल्फ-बैग ड्रॉप, चेक-इन की भी सुविधा होगी। डिजी यात्रा कागज़ रहित यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी और कई बिंदुओं पर पहचान जाँच से बचेगी।
- डिजी यात्रा प्लेटफॉर्म 4 प्रमुख स्तंभों पर बनाया जाएगा, जैसे कनेक्टेड पैसेंजर्स, कनेक्टेड एयरपोर्ट्स, कनेक्टेड फ्लाइंग और कनेक्टेड सिस्टम जिन्हें यात्रियों के लिये समय के साथ संभव बनाया जा सकता हैं: अत: कथन 2 सही है।
- टिकट बुकिंग के समय, मूल्य प्रवृत्तियों की पहचान करके और भविष्य के हवाई किराए का अनुमान लगाकर उनकी यात्राओं की कुशलता से योजना बनाना।
- उन्नत बॉयोमीट्रिक सुरक्षा समाधानों के कारण वॉक-थ्रू सुरक्षा स्कैनर।
- यह एक विकेंद्रीकृत मोबाइल वॉलेट-आधारित पहचान प्रबंधन मंच प्रदान करता है जो कि लागत प्रभावी है और डिजी यात्रा के कार्यान्वयन में गोपनीयता/डेटा सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करता है।
- डिजी यात्रा फाउंडेशन:
- इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 2019 में एक संयुक्त उद्यम (JV) कंपनी के रूप में स्थापित किया गया है।
- फाउंडेशन का गठन डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम (DYCE) बनाने के उद्देश्य से किया गया था।
- डिजी यात्रा फाउंडेशन एक अखिल भारतीय इकाई और यात्री आईडी सत्यापन प्रक्रिया का संरक्षक होगा।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) उन हवाई अड्डों की पहचान करेगा जहाँ डिजी यात्रा चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

147.

उत्तर:C

व्याख्या:

- विदेशी मुद्रा भंडार का आशय केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा में आरक्षित संपत्ति से है, जिसमें बॉण्ड, ट्रेज़री बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल होती हैं। गौरतलब है कि अधिकांश विदेशी मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर में आरक्षित किये जाते हैं।
- घटक:
  - विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति (FCA): FCA में ऐसी परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जिनका मूल्य देश की अपनी मुद्रा के अलावा किसी अन्य मुद्रा के आधार पर किया जाता है। FCA विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है। इसे डॉलर के रूप में व्यक्त किया

जाता है। FCA में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी मुद्राओं की वृद्धि या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है।

- स्वर्ण भंडार: स्वर्ण भंडार एक सरकार या बैंक द्वारा रखे गए स्वर्ण, बुलियन या सिक्कों का एक कोष है।
- विशेष आहरण अधिकार (SDR): SDR एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, जिसे IMF द्वारा वर्ष 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिये बनाया गया था। SDR न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा बल्कि यह IMF सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के लिये SDR का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित निधि (IMF): एक आरक्षित निधि का तात्पर्य मुद्रा के आवश्यक कोटा के एक हिस्से से है जिसे प्रत्येक सदस्य देश को IMF को प्रदान करना होता है, जिसका उपयोग सदस्य देशों द्वारा अपने स्वयं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किया जा सकता है। आरक्षित निधि मूल रूप से एक आपातकालीन खाता है जिसे IMF सदस्य किसी भी समय शर्तों से सहमत हुए या सेवा शुल्क का भुगतान किये बिना प्राप्त कर सकते हैं।

- अत: विकल्प C सही है।

148.

उत्तर: B

व्याख्या:

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बीड मॉडल:

- हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के 'बीड मॉडल' के राज्यव्यापी कार्यान्वयन के लिये कहा। अत: विकल्प B सही है।

बीड मॉडल:

- बीड महाराष्ट्र का एक ज़िला है जो सूखाग्रस्त मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित है।
- 80-110 फॉर्मूला: इस मॉडल को 80-110 फॉर्मूला भी कहा जाता है।
- बीमा फर्म को सकल प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक के दावों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बीमाकर्त्ता को नुकसान (पूल राशि) से बचाने के लिये एकत्र किये गए प्रीमियम के 110 प्रतिशत से अधिक मुआवज़े की लागत राज्य सरकार को वहन करनी होगी।
  - हालाँकि यदि मुआवज़ा एकत्र किये गए प्रीमियम से कम है तो बीमा कंपनी राशि का 20% हैंडलिंग शुल्क के रूप में रखेगी और शेष राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार (प्रीमियम अधिशेष) करेगी।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2016:

- यह योजना किसानों को फसल की विफलता (खराब होने) की स्थिति में एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करती है।
- दायरा (Scope): वे सभी खाद्य और तिलहनी फसलें तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलें, जिनके लिये पिछली उपज के आँकड़े उपलब्ध हैं।
- बीमा किस्त: इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त/प्रीमियम-खरीफ की सभी फसलों के लिये 2% और सभी रबी फसलों के लिये 1.5% है। वार्षिक वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में बीमा किस्त 5% है।

149.

उत्तर: C

व्याख्या:

सार्वजनिक-निजी भागीदारी:

- PPP सार्वजनिक संपत्ति और/या सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान के लिये सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बीच एक व्यवस्था है।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी बड़े पैमाने पर सरकारी परियोजनाओं, जैसे- सड़कों, पुलो अस्पतालों को निजी वित्तपोषण के साथ पूरा करने की अनुमति देती है।
- इस प्रकार की साझेदारी में निजी क्षेत्र की संस्था द्वारा एक निर्दिष्ट अवधि के लिये निवेश किया जाता है।
- समय पर एवं बजट के भीतर काम पूरा करने के लिये निजी क्षेत्र की प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन के संयोजन से इस साझेदारी को सुनिश्चित किया जा सकता है।

निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण (BOT) मॉडल:

BOT मॉडल के तहत निजी साझेदार को निर्दिष्ट अवधि (20 या 30 वर्ष की रियायत अवधि) के लिये एक परियोजना के वित्तीयन, निर्माण और संचालन के लिये रियायत दी जाती है, जिसमें निजी साझेदार उपयोगकर्त्ता शुल्क या सुविधा का उपयोग करने वाले ग्राहकों से टोल के माध्यम से निवेश की भरपाई करता है और इस प्रकार एक निश्चित मात्रा में वित्तीय जोखिम उठाता है।

- BOT एक निजी-सार्वजनिक भागीदारी (Public Private Partnership) मॉडल है जिसके अंतर्गत निजी साझेदार पर अनुबंधित अवधि के दौरान ढाँचागत परियोजना के डिज़ाइन, निर्माण एवं परिचालन की पूरी ज़िम्मेदारी होती है।
- निजी क्षेत्र के भागीदार को परियोजना के लिये वित्तीयन के साथ ही इसके निर्माण और रखखाव की ज़िम्मेदारी लेनी होती है।

बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOOT):

- इसमें निर्माण, परिचालक, परिचालन और हस्तांतरण जैसे चार प्रावधान हैं।
- BOT के इस प्रकार में समय की बातचीत के बाद परियोजना को सरकार या निजी परिचालक को स्थानांतरित कर दिया जाता है।
- राज्य की ओर से दी जाने वाली रियायत, रियायतग्राही को उन संपत्तियों का स्वामित्व या कम से कम अधिकार प्रदान करती है, जिन्हें निर्मित किया जाना है और उन्हें कुछ समय के लिये संचालित करना है: रियायत की समयसीमा। राज्य और रियायतग्राही के बीच रियायत समझौता यह परिभाषित करेगा कि किस हद तक स्वामित्व, और संपत्ति के कब्जे और नियंत्रण के संबंधित गुण, रियायतग्राही के पास हैं।अत: कथन 1 सही है।

स्विस चैलेंज:

- स्विस चैलेंज पद्धति बोली लगाने का एक तरीका है, जिसे अक्सर सार्वजनिक परियोजनाओं में उपयोग किया जाता है, जिसमें इच्छुक पार्टी अनुबंध के लिये प्रस्ताव या परियोजना हेतु बोली शुरू करती है।
- सरकार तब परियोजना का विवरण जनता के सामने रखती है और इसे क्रियान्वित करने में रुचि रखने वाले अन्य लोगों से प्रस्ताव आमंत्रित करती है।
- इन बोलियों की प्राप्ति पर मूल प्रस्तावक को सर्वोत्तम बोली के मिलान का अवसर मिलता है। यदि मूल प्रस्तावक बोली से मेल नहीं खाता है, तो परियोजना सर्वोत्तम बोली लगाने वाले प्रस्तावक को प्रदान की जाती है। अत: कथन 2 सही है।

150.

64 उत्तर: A

व्याख्या:

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA):

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) को एक वैधानिक निकाय (संवैधानिक निकाय नहीं) के रूप में स्थापित किया। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - यह उपभोक्ता अधिकारों के दुरुपयोग, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विपणन, जो कि जनता के हित में हानिकारक हैं, को नियंत्रित करने का अधिकार रखता है।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिये त्रि-स्तरीय अर्द्ध-न्यायिक तंत्र की घोषणा करता है, जैसे ज़िला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग।
- अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन नया आर्थिक क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होगा:
  - ज़िला आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहाँ प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है।
  - राज्य आयोगों के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहाँ प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक है, लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।
  - राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहाँ प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 2 करोड़ रुपए से अधिक है। अत: कथन 2 सही है।
- उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने में सुविधा के लिये केंद्र सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल की स्थापना की है।
- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के प्रावधानों को अधिसूचित और प्रभावी किया है। अत: कथन 3 सही है।
- ऑनलाइन खरीदारी करते समय उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के लिये CCPA ने सभी मार्केटप्लेस ई-कॉमर्स संस्थाओं को दिशा-निर्देश भी जारी किये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 6 के उप-नियम (5) के तहत अनिवार्य रूप से विक्रेताओं का विवरण, 2020 शिकायत अधिकारी के नाम और संपर्क नंबर सहित स्पष्ट और सुलभ तरीके से प्रदान किया जाए।

151.

उत्तर: A

व्याख्या:

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC):

- ONDC स्वतंत्र रूप से सुलभ सरकार-समर्थित प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य ई-कॉमर्स को प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद तथा बिक्री हेतु एक ओपन नेटवर्क में स्थानांतरित करके सार्वभौमिक बनाना है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो उद्योगों में स्थानीय डिजिटल कॉमर्स स्टोर को किसी भी नेटवर्क-सक्षम एप्लीकेशन द्वारा खोजने और संलग्न करने में सक्षम बनाने के लिये एक नेटवर्क की पेशकश करेगा।
  - ONDC के तहत यह परिकल्पना की गई है कि एक प्रतिभाग करने वाली ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये अमेज़ॅन) पर पंजीकृत खरीदार किसी अन्य प्रतिभागी ई-कॉमर्स साइट (उदाहरण के लिये फ्लिपकार्ट) पर विक्रेता से सामान खरीद सकता है।
  - प्रदाता और उपभोक्ता ONDC पर सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं लेन-देन करने के लिये अपनी पसंद के किसी भी संगत

एप्लीकेशन का उपयोग करने में सक्षम होंगे। अत: कथन 2 सही है।

- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

152.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी।
  - वर्ष 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिज़र्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। अत: कथन 1 सही है।
- मौद्रिक नीति समिति: यह विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत संस्थागत एक सांविधिक बहु-सदस्यीय निकाय है।
  - RBI के गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
  - MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य (4%) को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीतिगत ब्याज़ दर (रेपो दर) निर्धारित करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 22 के तहत एक रुपये के नोट को छोड़कर विभिन्न मूल्यवर्ग के करेंसी नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार भारतीय रिज़र्व बैंक के पास है। एक रुपये के नोट और सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये जाते हैं और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।

153.

उत्तर: C

व्याख्या:

औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2020:

- स्थायी आदेश का नया प्रावधान हर उस औद्योगिक प्रतिष्ठान पर लागू होगा जिसमें पिछले बारह महीनों के किसी भी दिन 300 या 300 से अधिक कर्मचारी कार्यरत रहे या कार्यरत थे। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- कानून बनने के बाद आदेश राज्य सरकारों के अधिकारियों की मर्जी और पसंद पर निर्भर नहीं होंगे।
- हड़ताल:
- यह वैध हड़ताल करने के लिये नई शर्तें भी पेश करता है। वैध हड़ताल पर जाने से पहले श्रमिकों के लिये शर्तों में मध्यस्थता की कार्यवाही अवधि को शामिल किया गया है, जबकि वर्तमान में केवल समझौते का समय शामिल है। अत: कथन 2 सही है।
- इसने छंटनी किये गए कामगारों के प्रशिक्षण के लिये नियोक्ता के योगदान के साथ पुन: कौशल निधि स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है, जो श्रमिक द्वारा प्राप्त अंतिम वेतन के 15 दिनों की राशि के बराबर होगी। अत: कथन 3 सही है।

154.

उत्तर: D

व्याख्या:

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय:

- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में नियामक निकाय है, जो मुख्य रूप से सुरक्षा मुद्दों से निपटता है। यह भारत में/से/के भीतर हवाई परिवहन सेवाओं के नियमन और नागरिक हवाई नियमों, हवाई सुरक्षा तथा उड़ान योग्यता मानकों को लागू करने के लिये जिम्मेदार है।
- DGCA अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के साथ सभी नियामक कार्यों का समन्वय भी करता है। अत: कथन 1 सही है।

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण:

- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण (AERA) की स्थापना वर्ष 2009 में "भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008" के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
- AERA की स्थापना वैमानिकी सेवाओं के लिये शुल्कों को विनियमित करने, प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु अन्य हवाईअड्डा शुल्क निर्धारित करने और हवाई अड्डों के प्रदर्शन मानकों की निगरानी के लिये की गई थी। अत: कथन 2 सही है।

155.

उत्तर: B

व्याख्या:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत ग्रामीण आबादी की 75 प्रतिशत और शहरी आबादी की 50 प्रतिशत आबादी को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म से 6 माह बाद तक भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अत: कथन 2 सही है।

156.

उत्तर: A

व्याख्या:

- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना को वर्ष 1998 में किसानों को उनकी खेती और बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों आदि जैसे कृषि आदानों की खरीद और उनकी उत्पादन आवश्यकताओं के लिये नकदी निकालने जैसी अन्य आवश्यकताओं के लिये लचीली एवं सरलीकृत प्रक्रिया के साथ एक एकल खिड़की के तहत बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त तथा समय पर ऋण सहायता प्रदान करने हेतु शुरू किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- इसे वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB), लघु वित्त बैंकों और सहकारी बैंकों जैसी एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

157.

उत्तर: B

व्याख्या:

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने हाल ही में झूठे या भ्रामक विज्ञापनों को रोकने के लिये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
- CCPA उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के आधार पर 2020 में स्थापित नियामक संस्था है।
- CCPA उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

अत: विकल्प B सही है।

158.

उत्तर: D

व्याख्या:

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक वे होते हैं जो अपनी घरेलू सीमा के बाहर के बाज़ारों में निवेश करते हैं। अत: कथन 3 सही है।
  - FPI के उदाहरणों में स्टॉक, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (ADR), और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (GDR) शामिल हैं।
- FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और इसे भुगतान संतुलन (BOP) पर दर्शाया जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- FPI को अक्सर "हॉट मनी" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में सबसे पहले भागने वाले संकेतों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एफपीआई अधिक तरल और अस्थिर होता है, इसलिये यह FDI की तुलना में अधिक जोखिम भरा है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

159.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा सभी राज्य / केंद्रशासित प्रदेशों में टेक होम राशन-गुड प्रैक्टिस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई थी।
  - WFP दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है।
- वर्ष 2020 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में खाद्य और कृषि संगठन (FAO) तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा की गई थी, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अत: कथन 2 सही है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समूह (UNSDG) का सदस्य भी है, जो संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संगठनों का एक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को पूरा करना है। अत: कथन 3 सही है।

160.

उत्तर: D

व्याख्या:

वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB):

- कैबिनेट नियुक्ति समिति (ACC) ने बैंक बोर्ड ब्यूरो (BBB) के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की स्थापना के लिये एक सरकारी प्रस्ताव पारित किया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - नए ढाँचे का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया गया था।
  - वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगा।
- FSIB के पास दिशा-निर्देश जारी करने और राज्य द्वारा संचालित गैर-जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमाकर्त्ताओं और वित्तीय संस्थानों के महाप्रबंधकों तथा निदेशकों का चयन करने का स्पष्ट अधिदेश होगा।
  - FSIB सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और वित्तीय संस्थानों में पूर्णकालिक निदेशक और गैर-कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये सिफारिशें करने वाली एकल इकाई होगी।
  - FSIB का क्षेत्राधिकार BBB से व्यापक होगा। अत: कथन 2 सही नहीं है। अत: विकल्प D सही है।

161.

उत्तर: D

व्याख्या:

- ग्लोलिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका प्रारंभिक वित्तपोषण नॉर्वे सरकार द्वारा किया गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इसका उद्देश्य शिपिंग व मत्स्य पालन उद्योग से उत्पन्न होने वाले समुद्री प्लास्टिक कचरे को कम करना है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

162.

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या में केवल अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। अत: कथन 1 सही है।
- 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स के निगमन के बाद से 10 वर्षों में से लगातार 3 वर्षों की अवधि के लिये आयकर से छूट दी गई है। अत: कथन 2 सही है।
- अटल नवाचार मिशन के तहत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप को इनक्यूबेट करने के लिये अटल इनक्यूबेशन सेंटर (AIC) की स्थापना की है।
  - इसने राष्ट्रीय महत्त्व और सामाजिक प्रासंगिकता की क्षेत्रीय चुनौतियों को हल करने वाले प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचारों के साथ स्टार्टअप्स को सीधे सहायता देने के लिये अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) कार्यक्रम भी शुरू किया है। अत: कथन 3 सही है।

163.

उत्तर: D

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) की स्थापना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल, 1935 को हुई थी। अत: कथन 1 सही है।
- बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपनी मांग और मीयादी देयताओं का एक भाग नकदी आरक्षित निधि के रूप में रिज़र्व बैंक के पास रखें। इस प्रयोजन के लिये उन्हें रिज़र्व बैंक में चालू खाता रखने की आवश्यकता होती है। बैंकों के चालू खाते भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग विभागों द्वारा खोले जाते हैं। अत: कथन 2 सही है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (वर्ष 2016 में संशोधित) के तहत RBI को विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। अत: कथन 3 सही है।
- अत: विकल्प D सही है।

164.

उत्तर: C

व्याख्या:

- क्रिप्टोकरेंसी, जिसे कभी-कभी क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का एक ऐसा रूप है जो डिजिटल रूप में या वस्तुत: मौजूद है और लेन-देन को सुरक्षित करने के लिये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। क्रिप्टोकरेंसी में मुद्रा जारी करने या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। यह लेन-देन को रिकॉर्ड करने तथा नई इकाइयों को जारी करने के लिये विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करती है।
- इसका संचालन एक विकेंद्रीकृत पीयर-टू-पीयर नेटवर्क द्वारा होता है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिये 'अस्थिर प्रभावों' का हवाला देते हुए क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। अत: कथन 2 सही है।

165.

उत्तर: D

व्याख्या:

- सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिये गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
- यह विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिये वन-स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। अत: कथन 1 सही है।
- GeM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिये मंत्रालयों व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है। अत: कथन 2 सही है।
- अत: विकल्प D सही है।

166.

उत्तर: C

व्याख्या:

GI टैग:

- GI एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न विशेष विशेषताओं वाले उत्पादों को पहचान प्रदान करने के लिये किया जाता है।
- 'वस्तुओं का भौगोलिक सूचक' (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है।
  - अधिनियम का संचालन महानियंत्रक पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क द्वारा किया जाता है जो भौगोलिक संकेतकों का रजिस्ट्रार होता है।
  - भौगोलिक संकेत पंजीकरण कार्यालय चेन्नई में स्थित है।
  - भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिये वैध होता है। इसे समय-समय पर 10-10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिये नवीनीकृत किया जा सकता है।
- GI टैग वाले कुछ उत्पादों में शामिल हैं:

उत्पाद	वर्ग	राज्य/क्षेत्र
लाहौली बुने हुए जुराब और दस्ताने	हस्तशिल्प	हिमाचल प्रदेश
हाथी मिर्च	कृषि	मणिपुर
महोबा देसावरी पान	कृषि	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश

अत: सभी युग्म सही सुमेलित हैं।

167.

उत्तर: A

व्याख्या :

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 की थीम है- सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। यह अवसर संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख मुद्दों से निपटने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी आंदोलन और अन्य कारकों के बीच गठबंधन को बढ़ाने एवं विस्तारित करने के लिये सहकारी आंदोलन के योगदान पर प्रकाश डालता है। अत: कथन 1 सही है।
- आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड (AMUL), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED), कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (KRIBHCO) और भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) सभी भारतीय सहकारी समितियों के उदाहरण हैं। अत: कथन 2 सही है।

168.

उत्तर: C

व्याख्या:

- अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। विश्व बैंक समूह में पाँच विकास संस्थान IDA, IFC, IBRD, MIGA और ICSID शामिल हैं। अत: कथन 1 सही है।
- बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA) युद्ध जैसे राजनीतिक जोखिमों के खिलाफ उधारदाताओं और निवेशकों को बीमा प्रदान करती है। अत: कथन 2 सही है।

169.

उत्तर: C

व्याख्या:

उपभोक्ता कल्याण कोष (CWF):

- इसे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित किया गया था। वर्ष 1992 के उपभोक्ता कल्याण कोष नियमों को CGST नियम, 2017 के तहत शामिल कर लिया गया है। अत: कथन 1 सही है।
  - इस कोष की स्थापना राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) द्वारा की गई है और इसका संचालन उपभोक्ता मामलों के विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) द्वारा किया जा रहा है। अत: कथन 2 सही है।
- उपभोक्ताओं के कल्याण को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना। इसके कुछ उदाहरण हैं:
  - अनुसंधान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिये प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता कानून से संबंधित पीठों/उत्कृष्टता केंद्रों का गठन करना।
  - उपभोक्ताओं को साक्षर करने और जागरूक बनाने के लिये परियोजनाएँ लागू करना।

अत: विकल्प C सही है।

170.

उत्तर: A

व्याख्या:

केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत भुगतान प्रणाली

- भारत में केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) प्रणाली और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (NEFT) प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली के रूप में शामिल होंगे

जिस पर समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

- RTGS: यह लाभार्थियों के खाते में वास्तविक समय पर धनराशि के हस्तांतरण की सुविधा को सक्षम बनाता है और इसका प्रयोग मुख्य तौर पर बड़े लेन-देनों के लिये किया जाता है।
  - यहाँ 'रियल टाइम' अथवा वास्तविक समय का अभिप्राय निर्देश प्राप्त करने के साथ ही उनके प्रसंस्करण (Processing) से है, जबकि 'ग्रॉस सेटलमेंट' या सकल निपटान का तात्पर्य है कि धन हस्तांतरण निर्देशों का निपटान व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।
- NEFT: यह एक देशव्यापी भुगतान प्रणाली है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है।
  - इसका उपयोग आमतौर पर 2 लाख रुपए तक के फंड ट्रांसफर के लिये किया जाता है।
- विकेंद्रीकरण भुगतान प्रणाली में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समाशोधन व्यवस्था [चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS)] के साथ-साथ अन्य बैंक [एक्सप्रेस चेक क्लियरिंग सिस्टम (ECCS) केंद्रों की जाँच] और किसी अन्य प्रणाली के रूप शामिल होंगे जिसमें समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
  - चेक ट्रंकेशन: यह भुगतानकर्त्ता बैंक द्वारा भुगतानकर्त्ता बैंक शाखा के रास्ते में किसी बिंदु पर ड्रॉअर द्वारा जारी किये गए भौतिक चेक के प्रवाह को रोकने की प्रक्रिया है।
- अत: विकल्प A सही है।

171.

उत्तर: D

व्याख्या:

WTO सामान्य परिषद:

- सामान्य परिषद जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च-स्तरीय निर्णय लेने वाला निकाय है।
- इसमें सभी सदस्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और उसे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की ओर से कार्य करने का अधिकार है जो प्रत्येक दो वर्ष में बैठक का आयोजन करता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- सामान्य परिषद विभिन्न नियमों के तहत विवाद निपटान निकाय और व्यापार नीति समीक्षा निकाय के रूप में भी बैठक करती है।

विवाद निपटान निकाय:

- सामान्य परिषद WTO सदस्यों के बीच विवादों को हल करने के लिये विवाद निपटान निकाय (DSB) के रूप में स्थापित किया गया है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- इस तरह के विवाद उरुग्वे दौर के अंतिम अधिनियम में निहित किसी भी समझौते के संबंध में उत्पन्न हो सकते हैं जो विवादों के निपटारे (DSU) को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं के अधीन है।
- DSB के पास विवाद निपटान पैनल स्थापित करने का अधिकार है।

अपीलीय निकाय:

- अपीलीय निकाय की स्थापना 1995 में विवादों के निपटारे को नियंत्रित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं की समझ (DSU) के अनुच्छेद 17 के तहत की गई थी।
- यह सात सदस्यों का एक स्थायी निकाय है, यह विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के बीच विवादों का समाधान करता है।
- अपीलीय निकाय पैनल के कानूनी निष्कर्षों को बनाए रख सकता है, संशोधित कर सकता है या उलट सकता है और अपीलीय निकाय रिपोर्ट को विवाद निपटान निकाय (DSB) द्वारा अपनाया जाता है जब तक कि सभी सदस्य ऐसा न करने का निर्णय नहीं लेते हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।

172.

उत्तर: D

व्याख्या:

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई प्रतिभूतियाँ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं।
  - यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता तथा ये बाज़ार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होती हैं। अत: कथन 1 सही है।
- FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और इसके भुगतान संतुलन (BOP) पर दर्शाया जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- BOP एक मौद्रिक वर्ष में एक देश से दूसरे देशों में धारा प्रवाह वाले धन की मात्रा को मापता है।
- FPI को अक्सर "हॉट मनी" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में सबसे पहले भागने वाले संकेतों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। FPI अधिक तरल और अस्थिर होता है, इसलिये यह FDI की तुलना में अधिक जोखिम भरा है। अत: कथन 3 सही है।

173.

उत्तर: D

व्याख्या:

चालू खाता घाटा (CAD):

- चालू खाता देश में और बाहर माल, सेवाओं और निवेश के प्रवाह

को मापता है। यह एक देश के विदेशी लेनदेन का प्रतिनिधित्त्व करता है और, पूंजी खाते की तरह, देश के भुगतान संतुलन (BoP) का एक घटक है। अत: कथन 1 सही है।

- चालू खाता घाटा जब आयातित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात किये गए मूल्य से अधिक हो जाता है
- एक देश का चालू खाता अन्य देशों के साथ देश के लेन-देन का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें ब्याज़ और लाभांश सहित शुद्ध आय और विदेशी सहायता जैसे स्थानान्तरण शामिल हैं। इसमें निम्नलिखित घटक होते हैं:
- वस्तुओं का व्यापार,
- सेवाएँ, और
- विदेशी निवेश पर शुद्ध आय और समय की अवधि में भुगतान का शुद्ध हस्तांतरण, जैसे प्रेषण।
- बढ़ते CAD वाले देश से पता चलता है कि यह अप्रतिस्पर्धी हो गया है, और निवेशक वहाँ निवेश करने के लिये तैयार नहीं होते हैं। अत: कथन 2 सही है।
- CAD और राजकोषीय घाटा (जिसे "बजट घाटा" के रूप में भी जाना जाता है, एक ऐसी स्थिति है जब किसी देश का व्यय उसके राजस्व से अधिक होता है) को एक साथ दोहरे घाटे के रूप में जाना जाता है और दोनों अक्सर एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं, अर्थात् उच्च राजकोषीय घाटा उच्च CAD को बढ़ाता है और इसके विपरीत कम होने पर CAD भी कम होता है। अत: कथन 3 सही है।

174.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्त्ता को सुरक्षित, तीव्र, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से "भुगतान विज़न 2025" (Payment Vision 2025) प्रस्तुत किया गया है। अत: कथन 1 सही नहीं है
  - इसका मुख्य ध्यान भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में सभी महत्वपूर्ण बिचौलियों को विनियमित करना है, न कि क्रेडिट कार्ड के उपयोग को बढ़ाना। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- उद्देश्य:
  - किसी भी समय और कहीं भी सुविधा के साथ सुलभ भुगतान विकल्पों के साथ उपयोगकर्त्ताओं को सशक्त बनाने के क्षेत्र में भुगतान प्रणाली को उन्नत करने में सहायक।
  - क्लोज्ड सिस्टम PPIs सहित प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (Prepaid Payment Instruments- PPIs) के लिये डिजिटल भुगतान अवसंरचना तथा लेन-देन और पुनरीक्षण दिशा-निर्देशों की जियोटैगिंग को सक्षम करने के लिये। अत: कथन 3 सही है।

175.

उत्तर: B

व्याख्या:

- विश्व व्यापार संगठन का मंत्रिस्तरीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।
  - इसके सभी सदस्यों को कम-से-कम हर दो वर्ष में मिलना आवश्यक है। मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के सदस्य बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत सभी मामलों पर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- वैश्विक वैक्सीन इक्विटी हासिल करने के लिये पेटेंट विनियमों में ढील देने पर सहमति; खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, मत्स्य पालन क्षेत्र को सब्सिडी देना तथा ई-कॉमर्स के लिये प्रासंगिक स्थगन जारी रखना सम्मेलन के कुछ फोकस बिंदु थे। अत: कथन 2 सही है।
- सदस्य देश इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन (ET) पर सीमा शुल्क नहीं लगाने के मौजूदा स्थगन को दिसंबर 2023 में होने वाले MC13 तक विस्तार करने पर सहमत हुए। यूएस, यूके ऑस्ट्रेलिया चीन और जापान सहित 105 देशों ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के विरोध में होने के बावजूद स्थगन का विस्तार करने की मांग की थी। अत: कथन 3 सही है।

176.

उत्तर: D

व्याख्या:

ज़मानती बॉण्ड:

- किसी अधिनियम के अनुपालन, भुगतान या प्रदर्शन की गारंटी के लिये एक लिखित समझौते के रूप में एक ज़मानती बॉण्ड को अपने सरल रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- यह एक अद्वितीयक प्रकार का बीमा है क्योंकि इसमें तीन-पक्षीय समझौता शामिल है। एक ज़मानत समझौते में तीन पक्ष होते हैं। अत: कथन 1 सही है।
  - एक ज़मानत समझौते में तीन पक्ष हैं:
  - मुख्य पक्ष- वह पक्ष जो बॉण्ड खरीदता है और वादे के अनुसार कार्य करने का दायित्व लेता है।
  - ज़मानत पक्ष- दायित्त्व की गारंटी देने वाली बीमा कंपनी या ज़मानत कंपनी का प्रदर्शन किया जाएगा। यदि मुख्य पक्ष वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहता है, तो ज़मानत पक्ष निरंतर नुकसान के लिये संविदात्मक रूप से उत्तरदायी है।

- ओब्लिगी- जिस पार्टी की आवश्यकता होती है वह प्राय: ज़मानती बॉण्ड से लाभ प्राप्त करता है। अधिकांश ज़मानती बॉण्ड के लिये 'ओब्लिगी' एक स्थानीय, राज्य या संघीय सरकारी संगठन होता है।

- बीमा कंपनी द्वारा इकाई की ओर से उस संस्था को ज़मानती बॉण्ड प्रदान किया जाता है जो परियोजना शुरू कर रही है। अत: कथन 2 सही है।
- ज़मानती बॉण्ड मुख्य रूप से बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित है, यह आपूर्तिकर्त्ताओं और कार्य-ठेकेदारों के लिये अप्रत्यक्ष लागत को कम करने हेतु उनके विकल्पों में विविधता लाने व बैंक गारंटी के विकल्प के रूप में कार्य करता है। अत: कथन 3 सही है।

177.

उत्तर: C

व्याख्या:

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):

- यह एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसे 1989 में पेरिस में 1989 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
  - यह देश के धन शोधन रोधी और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण ढाँचे की ताकत का आकलन करता है।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिये मानक निर्धारित करना और कानूनी, नियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।
- इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) मुख्यालय में स्थित है।
- FATF की सूचियाँ:
  - ग्रे लिस्ट:
  - जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिये सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है।
  - इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि उसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया सकता है।
  - ब्लैक लिस्ट:
  - असहयोगी देशों या क्षेत्रों (Non-Cooperative Countries or Territories- NCCTs) के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जाता है। ये देश आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
  - इस सूची में देशों को शामिल करने अथवा हटाने के लिये FATF इसे नियमित रूप से संशोधित करता है।
  - वर्तमान में ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या ब्लैक लिस्ट में हैं। अत: कथन 2 सही है।

178.

उत्तर: C

व्याख्या:

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI):

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI), भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसे 'भारतीय रिज़र्व बैंक' (RBI) और 'भारतीय बैंक संघ' (IBA) द्वारा 'भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007' के तहत शुरू किया गया है। अत: कथन 1 सही है।
- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस वर्तमान में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, तत्काल भुगतान सेवा, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली, भारत बिल भुगतान प्रणाली, रुपे आदि सहित एनपीसीआई संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है। अत: कथन 2 सही है।

179.

उत्तर: D

व्याख्या:

- मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों से डिजिटल माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिये एक बैंक को भुगतान की गई लागत है। अत: कथन 1 सही है।
  - व्यापारी छूट दर लेन-देन राशि के प्रतिशत में व्यक्त की जाती है। अत: कथन 2 सही है।
  - वर्तमान में यह ऑनलाइन लेन-देन और क्यूआर-आधारित लेन-देन के लिये लागू है। अत: कथन 3 सही है।
- व्यापारी द्वारा हर लेन-देन के लिये भुगतान की जाने वाली राशि तीन हितधारकों के बीच वितरित की जाती है- बैंक जो लेन-देन को सक्षम बनाता है, विक्रेता जो बिक्री बिंदु (POS) मशीन स्थापित करता है और कार्ड नेटवर्क प्रदाता जैसे वीज़ा, मास्टरकार्ड, रूपे।

180.

उत्तर: C

व्याख्या:

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 'एक ज़िला एक उत्पाद' (ODOP) शुरू किया गया था, ताकि ज़िलों को उनकी पूरी क्षमता उपभोग, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सके। अत: कथन 1 सही नहीं है।

- यह पहल विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य विभाग द्वारा 'निर्यात हब के रूप में ज़िले (Districts as Exports Hub)' पहल के साथ की जाती है। 'निर्यात हब के रूप में ज़िले' पहल ज़िला स्तर के उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है ताकि लघु उद्योगों की मदद की जा सके और वे स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान कर सकें। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- राज्य मौजूदा क्लस्टरों और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ज़िलों के लिये खाद्य उत्पादों की पहचान करेंगे। ODOP एक खराब होने वाली उपज-आधारित या अनाज-आधारित या एक क्षेत्र में व्यापक रूप से उत्पादित खाद्य पदार्थ हो सकता है। अत: कथन 3 सही है।
- एक ज़िला एक उत्पाद, ज़िला स्तर के उद्योगों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है ताकि लघु उद्योगों की मदद की जा सके और वे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर सकें। अत: कथन 4 सही है।

181.

उत्तर: B

व्याख्या:

भारत में बेरोजगारी के प्रकार:

- प्रच्छन्न बेरोज़गारी: यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोज़गार दिया जाता है।
  - यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में व्याप्त है।
- मौसमी बेरोज़गारी: यह एक प्रकार की बेरोज़गारी है, जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है।
  - भारत में खेतिहर मज़दूरों के पास वर्ष भर काफी कम कार्य होता है।
- संरचनात्मक बेरोज़गारी: यह बाज़ार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोज़गारी की एक श्रेणी है।
  - भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती है तथा शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है।
- चक्रीय बेरोज़गारी: यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है।
- अत: विकल्प B सही है ।

182.

उत्तर: C

व्याख्या:

नियोबैंक:

- नियोबैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई भौतिक शाखा नहीं है। किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय, नियोबैंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है। अत: कथन 1 सही है।
  - नियोबैंक वित्तीय संस्थान हैं जो ग्राहकों को पारंपरिक बैंकों का एक सस्ता विकल्प देते हैं।
  - वे परिचालन लागत को कम करते हुए ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हैं।
- नियोबैंक ने 'चैलेंजर बैंक' के टैग के साथ वित्तीय प्रणाली में प्रवेश किया क्योंकि उन्होंने पारंपरिक बैंकों के जटिल बुनियादी ढाँचे और 'क्लाइंट ऑनबोर्डिंग' प्रक्रिया को चुनौती दी थी।
- भारत में इन फर्मों के पास स्वयं का कोई बैंक लाइसेंस नहीं है, ये लाइसेंस प्राप्त सेवाएँ प्रदान करने के लिये बैंक भागीदारों पर निर्भर हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि RBI ने अभी तक बैंकों को 100% डिजिटल करने की अनुमति नहीं दी है।
  - RBI बैंकों की भौतिक उपस्थिति को प्राथमिकता देने के प्रति दृढ़ है और उसने डिजिटल बैंकिंग सेवा प्रदाताओं के लिये कुछ भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में भी बात की है।
- नियोबैंक आमतौर पर पारंपरिक बैंकों की तुलना में कम सेवाएँ प्रदान करते हैं। अत: कथन 3 सही नहीं है।

183.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए 2.0) की स्थापना की है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह नियामक निर्देशों को सुव्यवस्थित करने, जहाँ भी संभव हो रिपोर्टिंग की प्रक्रियाओं तथा आवश्यकताओं को कम करने और विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने आदि विषयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। अत: कथन 2 सही है।
- विनियमित इकाई विद्युत कंपनियों, सार्वजनिक उपयोगिताओं या सार्वजनिक उपयोगिता होल्डिंग कंपनियों के वित्तीय, संगठनात्मक या दर विनियमन से संबंधित किसी भी कानून, नियमों या विनियमों के अधीन है। वाणिज्यिक बैंक, शहरी सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग

वित्तीय कंपनियाँ विनियमित संस्थाओं के अंतर्गत शामिल हैं। अत: कथन 3 सही है।

- आरआरए, आरबीआई परिपत्रों/निर्देशों के प्रसार प्रक्रिया में आवश्यक परिवर्तनों की जाँच करता है और सुझाव देता है (इसमें परिपत्र जारी करने, अद्यतन करने और वेबसाइट लिंकेज के तरीके आदि पर सुझाव शामिल होंगे)। अत: कथन 4 सही है।
- अत: विकल्प- (B) सही है।

184.

उत्तर: B

व्याख्या:

- स्लो फैशन कपड़ों के उत्पादन के लिये एक दृष्टिकोण है जो आपूर्ति श्रृंखला के सभी पहलुओं को ध्यान में रखता है और ऐसा करने का उद्देश्य लोगों, पर्यावरण एवं जानवरों का सम्मान करना है। अत: कथन 2 सही है।
- स्लो फैशन फास्ट फैशन के ठीक विपरीत है। यह नई फैशन अवधारणाओं को अपनाने की धीमी प्रक्रिया से संबंधित नहीं बल्कि गुणवत्तापूर्ण कार्य के आधार पर विचारशील, क्यूरेटेड फैशन का संग्रह है।
  - पहला कथन 'स्लो फैशन मूवमेंट' की सही व्याख्या नहीं करता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।

185.

उत्तर: B

व्याख्या:

जन समर्थ पोर्टल:

- यह पोर्टल वित्त मंत्रालय की एक पहल है , जो सरकार की एक दर्जन से अधिक क्रेडिट-लिंक्ड योजनाओं के लिये वन-स्टॉप गेटवे है और लाभार्थियों को सीधे उधारदाताओं से जोड़ती है।
- यह पोर्टल क्रेडिट-लिंक्ड सरकारी योजनाओं के तहत ऋण आवेदन और प्रसंस्करण के लिये एकल मंच के रूप में कार्य करेगा।
- इस पोर्टल से छात्रों, किसानों, व्यापारियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के साथ-साथ उद्यमियों के जीवन में सुधार होगा तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भी मदद मिलेगी।
  - इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य कई क्षेत्रों में समावेशी वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना है।
  - अत: विकल्प B सही है।

186.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (NARCL), भारतीय ऋण समाधान कंपनी (IDRCL) के साथ मिलकर बैंकों के बैड लोन के पहले सेट का समाधान करने का प्रयास करेगी। अत: कथन 1 सही है।
  - बैड बैंक स्थापित करने का उद्देश्य बैंकों को उनकी बैलेंसशीट से बैड लोन को समाप्त कर बोझ को कम करना है ताकि वे बिना किसी बाधा के ग्राहकों को फिर से उधार दे सकें।
- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है, जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है।
- अधिकतर मामलों में ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि तक न किया गया हो। अत: कथन 2 सही है।

187.

उत्तर: D

व्याख्या :

- GeM विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिये वन-स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- GeM पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिये मंत्रालयों व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद करना अनिवार्य है। अत: कथन 2 सही है।
- यह सरकारी उपयोगकर्त्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिये ई-बोली और रिवर्स ई-नीलामी जैसे उपकरण भी प्रदान करता है।
- इसे वर्ष 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिये लॉन्च किया गया था।
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय GeM पोर्टल का नोडल मंत्रालय है। अत: कथन 3 सही है। अत: विकल्प D सही है।

188.

उत्तर: C

व्याख्या:

- सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF) को वर्ष 2002 में दूरसंचार विभाग के तहत बनाया गया था। अत: कथन 1 सही है।

- USOF यह सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में लोगों के लिये आर्थिक रूप से उपयुक्त कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण आईसीटी सेवाओं तक सार्वभौमिक गैर-भेदभावपूर्ण पहुँच हो। अत: कथन 3 सही है।
- वर्तमान में इस पर 5% की दर से चार्ज किया जाता है, जबकि टीएसपी द्वारा इसे घटाकर 3% करने की मांग की जा रही है।
- यह एक गैर-व्यपगत निधि है, अर्थात् लक्षित वित्तीय वर्ष के तहत खर्च नहीं की गई राशि व्यपगत नहीं होती है और अगले वर्षों के खर्च के लिये व्यय की जाती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- इस फंड के सभी प्रकार के क्रेडिट के लिये संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम, 2003 के तहत वैधानिक समर्थन प्राप्त है।

189.

उत्तर: D

व्याख्या:

- स्टैगफ्लेशन का अर्थ है कीमतों में एक साथ वृद्धि और आर्थिक विकास की स्थिरता की विशेषता वाली स्थिति।
- स्टैगफ्लेशन शब्द नवंबर 1965 में यूनाइटेड किंगडम में कंज़र्वेटिव पार्टी के सांसद इयान मैकलेओड द्वारा गढ़ा गया था।
- इसे अर्थव्यवस्था में एक ऐसी स्थिति के रूप में वर्णित किया जाता है जहाँ विकास दर धीमी हो जाती है, बेरोज़गारी का स्तर लगातार ऊँचा रहता है, फिर भी मुद्रास्फीति या मूल्य वृद्धि एक ही समय में उच्च रहती है।.अत: कथन 1 सही नहीं है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक मुद्रास्फीति के निर्दिष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपने नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग के संदर्भ में मौद्रिक नीत को संदर्भित करता है।
  - आरबीआई की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य विकास को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

190.

उत्तर: B

व्याख्या:

- विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश वर्ष 1998 से इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण पर सीमा अधिस्थगन पर सहमत हुए थे और स्थगन की अवधि को समय-समय पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में बढ़ाया जाता रहा है, जो कि 164 सदस्यीय संगठन (WTO) का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह स्थगन फोटोग्राफिक फिल्मों, सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों, प्रिंटेड विषय-वस्तु, संगीत, मीडिया, सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम जैसे डिजिटल उत्पादों पर लागू है।
- भारत जून 2022 से शुरू होने वाले विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन (ई-ट्रांसमिशन) पर सीमा शुल्क को लेकर अधिस्थगन का विरोध करेगा क्योंकि इसके प्रावधान केवल विकसित देशों के पक्ष में हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - भारत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के आयात में तेज़ी से वृद्धि देखी जा रही है, मुख्य रूप से फिल्में, संगीत, वीडियो गेम और मुद्रित पदार्थ आदि, इनमें से कुछ स्थगन के दायरे में आ सकते हैं।
  - विकासशील देशों के लिये अपनी डिजिटल उन्नति हेतु नीतिगत स्थान को संरक्षित करने, आयात को विनियमित करने और सीमा शुल्क के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिये अधिस्थगन की अनुमति देना महत्त्वपूर्ण है।

191.

उत्तर: A

व्याख्या:

- FTA दो या दो से अधिक देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच एक व्यवस्था है जो मुख्य रूप से उनके बीच पर्याप्त व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करती है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- FTA आमतौर पर माल (जैसे- कृषि या औद्योगिक उत्पाद) या सेवाओं में व्यापार (जैसे- बैंकिंग, निर्माण, व्यापार आदि) पर लागू होता है।
  - FTA अन्य क्षेत्रों जैसे- बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), निवेश, सरकारी खरीद और प्रतिस्पर्द्धा नीति आदि को भी कवर कर सकता है। अत: कथन 2 सही है।
  - उदाहरण: भारत ने कई देशों के साथ FTA पर बातचीत की है, उदाहरण- श्रीलंका और आसियान जैसे विभिन्न व्यापारिक ब्लॉकों के साथ।
  - FTA को तरजीही व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

192.

उत्तर: C

व्याख्या:

- शहरी स्थिरता मूल्यांकन फ्रेमवर्क (USAF) को सतत् शहर एकीकृत दृष्टिकोण पायलट (SCIAP) परियोजना के तहत विकसित किया गया है, जिसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और यूएन-हैबिटेट द्वारा कार्यान्वित किया गया है। अत: कथन 1 सही है।

- इस परियोजना को भारतीय शहरों की कार्बन पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाने के लिये वैश्विक पर्यावरण सुविधा (GEF-6) से धन प्राप्त हुआ है। अत: कथन 2 सही है।

193.

उत्तर: C

व्याख्या:

एंटी-डंपिंग ड्यूटी:

- डंपिंग की स्थिति में किसी देश द्वारा दूसरे देश में माल का निर्यात उस कीमत से कम कीमत पर किया जाता है जो वह आमतौर पर अपने घरेलू बाज़ार में वसूलता है।
- काउंटरवेलिंग ड्यूटी से अलग:
  - एडीडी आयात पर एक सीमा शुल्क है जो सामान्य मूल्य से काफी कम कीमत पर माल की डंपिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि काउंटरवेलिंग ड्यूटी उन सामानों पर सीमा शुल्क है जिन्हें मूल या निर्यात करने वाले देश में सरकारी सब्सिडी प्राप्त हुई है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- डंपिंग रोधी शुल्क से संबंधित विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान: एक एंटी-डंपिंग शुल्क लागू होने की तारीख से पाँच साल की अवधि के लिये वैध होता है।
  - वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत व्यापार उपचार महानिदेशालय, डंपिंग रोधी, प्रतिकारी शुल्क और सुरक्षा उपायों सहित सभी व्यापार उपचारात्मक उपायों को प्रशासित करने के लिये। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - यह एक संरक्षणवादी टैरिफ है जो एक घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर लगाती है, जिसका मानना है कि इनकी कीमत उचित बाज़ार मूल्य से कम है।
  - विश्व व्यापार संगठन द्वारा उचित प्रतिस्पर्द्धा के साधन के रूप में डंपिंग रोधी उपायों के उपयोग की अनुमति है।

194.

उत्तर: D

व्याख्या:

- जीएसटी परिषद, केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है। यह संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279ए (1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया गया था। अत: कथन 1 सही है।
- परिषद के सदस्यों में केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्र से केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं। अत: कथन 2 सही है।
- प्रत्येक राज्य, वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है। अत: कथन 3 सही है।
- कार्य:
  - परिषद अनुच्छेद 279 के अनुसार, "GST से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करने के लिये है, जैसे- वस्तुओं व सेवाओं पर GST, मॉडल GST कानूनों के अधीन है या छूट दी जा सकती है"।
  - यह GST के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है।
  - उदाहरण के लिये मंत्रियों के एक पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ पर 28% कर लगाने का सुझाव दिया गया है।

195.

उत्तर: C

व्याख्या:

विश्व व्यापार संगठन (WTO):

- यह वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया विश्व व्यापार संगठन द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर स्थापित टैरिफ और व्यापार (GATT) पर सामान्य समझौते का उत्तराधिकारी है। अत: कथन 1 सही हैं।
  - इसका उद्देश्य व्यापार प्रवाह को सुचारू, स्वतंत्र और अनुमानित रूप से मदद करना है।
  - इसके 164 सदस्य हैं, जो विश्व व्यापार का 98% हिस्सा है।
- भारत वर्ष 1947 के GATT का संस्थापक सदस्य है और इसका उत्तराधिकारी WTO है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- इसे GATT के तहत आयोजित व्यापार वार्ताओं, या दौरों की एक श्रृंखला के माध्यम से विकसित किया गया था।
- विश्व व्यापार संगठन का सचिवालय जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है। अत: कथन 3 सही है।

196.

उत्तर: A

व्याख्या:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013:

- इसका उद्देश्य गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।
- इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% तक शामिल है।
  - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है। अत: कथन 1 सही है।
  - लाभार्थी:
  - राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत आने वाले प्राथमिकता वाले घर।

- अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किये गए घर।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में केंद्रीय पूल से जारी खाद्यान्नों के केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) में संशोधन की सिफारिश की गई थी, जो बीते कई वर्षों से अपरिवर्तित है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
  - केन्द्रीय निर्गम मूल्य: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत रियायती दरों पर लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।
  - केंद्र सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर अनाज खरीदती है और इसे केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) पर राज्यों को बेचती है।
  - केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर केंद्रीय निर्गम मूल्य (CIP) का निर्धारण किया जाता है, किंतु यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से अधिक नहीं होता है।

197.

उत्तर: D

व्याख्या:

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) में विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई प्रतिभूतियाँ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल हैं।
  - यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता है और बाज़ार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होती है। अत: कथन 1 सही है।
- FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और इसके भुगतान संतुलन (BOP) पर दर्शाया जाता है। अत: कथन 2 सही है।
- BOP एक मौद्रिक वर्ष में एक देश से दूसरे देशों में होने वाले धन के प्रवाह की मात्रा को मापता है।
- FPI को अक्सर "हॉट मनी" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में सबसे पहले भागने वाले संकेतों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एफपीआई अधिक तरल और अस्थिर होता है, इसलिये यह FDI की तुलना में अधिक जोखिम भरा है। अत: कथन 3 सही है।

198.

उत्तर: D

व्याख्या:

- नियोबैंक एक तरह का डिजिटल बैंक है जिसकी कोई शाखा नहीं है। किसी विशिष्ट स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय, नियोबैंकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन है।
- नियोबैंक वित्तीय संस्थान हैं जो ग्राहकों को पारंपरिक बैंकों का एक सस्ता विकल्प प्रदान करते हैं।
- वे परिचालन लागत को कम करते हुए ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाते हैं।
- नियोबैंक स्वतंत्र रूप से या पारंपरिक बैंकों के साथ साझेदारी में काम करते हैं। नियोबैंक विनियमित बैंकों/एनबीएफसी के साथ साझेदारी करते हैं और बिना किसी भौतिक शाखा के वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- पेपैल एक नियोबैंक नहीं है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंपनी है जो ऑनलाइन स्थानांतरण के माध्यम से पार्टियों के बीच भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

199.

उत्तर: B

व्याख्या:

हस्तशिल्प क्षेत्र से संबंधित पहल:

- अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना:
  - कारीगरों को उनके बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन विकास की ज़रूरतों के साथ समर्थन देना। अत: युग्म 1 सुमेलित नहीं है।
  - इस योजना का उद्देश्य थोक उत्पादन और अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लक्ष्य के साथ कारीगरों को स्वयं सहायता समूहों एवं समाजों में संगठित करना है।
- मेगा क्लस्टर योजना:
  - इस योजना का उद्देश्य रोज़गार सृजन और कारीगरों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। अत: युग्म 2 सही सुमेलित है।
  - यह कार्यक्रम विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों के हस्तशिल्प केंद्रों में बुनियादी ढाँचे और उत्पादन श्रृंखलाओं को बढ़ाने में क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है।
- व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना:
  - इस योजना का दृष्टिकोण हस्तशिल्प समूहों में बुनियादी ढाँचे और उत्पादन श्रृंखला को बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त इस योजना का उद्देश्य उत्पादन, मूल्यवर्द्धन एवं गुणवत्ता आश्वासन के लिये पर्याप्त बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है। अत: युग्म 3 सुमेलित नहीं है।

यहाँ युग्म 1 और युग्म 3 सही सुमेलित नहीं हैं, लेकिन युग्म 2 सही सुमेलित है। अत: विकल्प A सही है।

200.

उत्तर: C

उत्तर:

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई), भारत में खुदरा

भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिये एक संगठन है। अत: कथन 2 सही है।

- यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) की एक पहल है।
- यह कंपनी अधिनियम 1956 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) की धारा 25 के प्रावधानों के तहत "बिना लाभ" की कंपनी है, जिसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली और निपटान प्रणाल को भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिये बुनियादी ढाँचा प्रदान करना है। अत: कथन 1 सही है।

201.

उत्तर: B

व्याख्या:

- GeM विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों/संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिये वन-स्टॉप राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह सरकारी उपयोगकर्त्ताओं को उनके पैसे का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने की सुविधा के लिये ई-बोली और रिवर्स ई-नीलामी जैसे उपकरण भी प्रदान करता है।
- GeM पोर्टल योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित है। अत: कथन 2 सही है।
- इसे वर्ष 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिये लॉन्च किया गया था। अत: विकल्प B सही है।

202.

उत्तर: A

व्याख्या:

- केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिये धन जारी करने, वितरित करने और निगरानी करने के तरीके के संबंध में वर्ष 2021 में वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह इस क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है। अत: कथन 1 सही है।
- यह राज्यों के वित्त को नियंत्रित नहीं करेगा, यह विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किये गए धन के वितरण की दक्षता बढ़ाने के लिये एक डैशबोर्ड है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

203.

उत्तर: B

व्याख्या:

- यूनिकॉर्न किसी भी निजी स्वामित्व वाली फर्म है जिसका बाज़ार पूंजीकरण 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह अन्य उत्पादों/सेवाओं के अलावा रचनात्मक समाधान और नए व्यापार मॉडल पेश करने के लिये समर्पित नई संस्थाओं की उपस्थिति को दर्शाता है।
- हाल ही में भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 100 के आँकड़े तक पहुँच गई है।
- यूनिकॉर्न का अर्थ कम-से-कम 7,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाले स्टार्टअप से है। इन यूनिकॉर्न का कुल मूल्यांकन 330 अरब अमेरिकी डॉलर है, जो 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।
- भारतीय यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों की तुलना में अधिक है। अत: कथन 2 सही है।

204.

उत्तर: D

व्याख्या:

- अलग-अलग समितियों की सिफारिशें:
  - कई समितियों ने सार्वजनिक बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को 51% तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है:
  - नरसिम्हन समिति ने हिस्सेदारी को 33% तक सीमित करने की बात कही थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - पी.जे. नायक समिति ने हिस्सेदारी को 50% से कम करने का सुझाव दिया था।
- RBI के कार्यकारी समूह ने हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रवेश का सुझाव दिया है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

205.

उत्तर: D

व्याख्या:

- IPPB की स्थापना भारत की आम जनता के लिये सुलभ, सस्ते और भरोसेमंद बैंक का निर्माण करने के दृष्टिकोण के साथ की गई है।
- इस बैंक की स्थापना संचार मंत्रालय के डाक विभाग (DOP) के अंतर्गत की गई है जिसकी 100 फीसदी हिस्सेदारी पर भारत सरकार का स्वामित्व है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- IPPB का लक्ष्य भारत में हर घर तक कुशल बैंकिंग सेवाओं की पहुँच प्रदान करना है और उन्हें सरल, विविध तथा विकासोन्मुख पेशकश के माध्यम से वित्तीय रूप से सुरक्षित एवं सशक्त बनाना है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

अत: विकल्प D सही है।

206.

उत्तर: C

व्याख्या

- स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉज़िटरी और समाशोधन निगम को सामूहिक रूप से बाज़ार अवसंरचना संस्थान (Market Infrastructure Institutions) प्रतिभूति के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अध्यक्षता में स्थापित (2010 में) एक पैनल के अनुसार, 'मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर' शब्द इस पूंजी बाज़ार की सेवा क्षेत्रक मूलभूत सुविधाओं और प्रणालियों को दर्शाता है।
  - प्रतिभूतियों/पूंजी बाज़ार का प्राथमिक उद्देश्य पूंजी/वित्तीय संसाधनों के आवंटन/पुनर्आवंटन को सक्षम बनाना है।
- MIIs अर्थव्यवस्था में धन के इष्टतम उपयोग में मदद करने के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। अत: कथन 1 सही है।
- यह पूंजी आवंटन प्रणाली का केंद्र हैं तथा आर्थिक विकास हेतु अपरिहार्य हैं और किसी भी अन्य बुनियादी ढाँचा संस्थान की तरह समाज पर शुद्ध सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
- हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के निष्कर्षों के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE), देश का सबसे बड़ा इक्विटी और डेरिवेटिव एक्सचेंज तथा एक व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण बाज़ार अवसंरचना संस्थान (Market Infrastructure Institution- MII) है। अत: कथन 2 सही है।

207.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों को शिक्षित करने वाला एक मोबाइल एप सारथी लॉन्च किया है। 'R' को "₹' द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाज़ार की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
- यह एप केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड (एमएफ), हालिया बाज़ार के विकास, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र आदि के बारे में भी बताएगा।
- अत: विकल्प C सही है।

208.

उत्तर: D

व्याख्या:

मौद्रिक नीति के विभिन्न साधन

- तरलता समायोजन सुविधा (LAF):
  - LAF में रातों-रात और साथ ही सावधि रेपो नीलामियाँ शामिल हैं।
  - सावधि रेपो का उद्देश्य इंटरबैंक सावधिक मनी मार्केट को विकसित करने में मदद करना है, जो बदले में ऋण और जमा के मूल्य निर्धारण के लिये बाज़ार आधारित बेंचमार्क निर्धारित कर सकता है और इसलिये मौद्रिक नीति के हस्तांतरण में सुधार करता है।
  - RBI परिवर्तनीय ब्याज दर रिवर्स रेपो नीलामी भी आयोजित करता है, जैसा कि बाज़ार की स्थितियों के तहत आवश्यक है।
  - रेपो रेट:
  - वह ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों को रातों-रात चलनिधि प्रदान करता है।
  - रिवर्स रेपो रेट:
  - वह ब्याज दर जिस पर रिज़र्व बैंक LAF के तहत पर बैंकों से रातों-रात आधार पर तरलता प्राप्त करता है।
- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF):
  - एक सुविधा जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिज़र्व बैंक से ओवरनाईट मुद्रा की अतिरिक्त राशि को एक सीमा तक अपने सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) पोर्टफोलियो में गिरावट कर ब्याज की दंडात्मक दर ले सकते हैं।
  - यह बैंकिंग प्रणाली को अप्रत्याशित चलनिधि झटकों के खिलाफ सुरक्षा वाल्व प्रदान करती है।
- खुला बाज़ार परिचालन (OMOs):
  - इनमें सरकारी प्रतिभूतियों की एकमुश्त खरीद/बिक्री, टिकाऊ चलनिधि डालना/अवशोषित करना क्रमश: दोनों शामिल हैं।
- बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS):
  - मौद्रिक प्रबंधन के लिये इस लिखत को वर्ष 2004 में आरंभ किया गया।
  - बड़े पूंजी प्रवाह से उत्पन्न अधिक स्थायी प्रकृति के अधिशेष चलनिधि को अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों और खजाना बिलों की बिक्री के ज़रिये अवशोषित की जाती है।
  - जुटाए जाने वाली नकदी को रिज़र्व बैंक के पास एक अलग सरकारी खाते में रखा जाता है।
- अत: विकल्प D सही है।

209.

उत्तर: A

व्याख्या:

एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज (NSE IFSC):

- NSE IFSC (NSE International Exchange) 29 नवंबर, 2016 को निगमित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया

लिमिटेड (NSE) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अत: कथन 1 सही है।

- गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट) शहर में कार्यरत स्टॉक एक्सचेंजों को भारतीय रुपए के अलावा किसी भी मुद्रा में प्रतिभूतियों में व्यापार की पेशकश करने की अनुमति है।
- तदनुसार एनएसई आईएफएससी जिसने 5 जून, 2017 को व्यापार शुरू किया, विभिन्न उत्पादों में अमेरिकी डॉलर में व्यापार की पेशकश करता है।
- एनएसई आईएफएससी इंडेक्स डेरिवेटिव्स, स्टॉक डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स और डेट सिक्योरिटीज़ सहित विभिन्न उत्पादों में व्यापार की पेशकश करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

210.

उत्तर: C

व्याख्या:

- NLMC एक एजेंसी के रूप में अधिशेष भूमि संपत्ति मुद्रीकरण का कार्य करेगा और इस संबंध में केंद्र को सहायता व तकनीकी सलाह प्रदान करेगा।
  - NLMC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि व भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा। अत: कथन 2 सही है।
  - यह निजी क्षेत्र के निवेश, नई आर्थिक गतिविधियों, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने तथा आर्थिक एवं सामाजिक बुनियादी ढाँचे हेतु वित्तीय संसाधन जुटाने के लिये कम उपयोग की गई संपत्तियों के उत्पादक उपयोग को सक्षम करेगा।
  - NLMC की घोषणा 5000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपए की चुकता शेयर पूंजी के साथ की गई है।
- NLMC के निदेशक मंडल में कंपनी के पेशेवर संचालन और प्रबंधन को सक्षम करने के लिये केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल होंगे।
  - NLMC के अध्यक्ष, गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति योग्यता-आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।
- नई कंपनी को वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। अत: कथन 1 सही है।

211.

उत्तर: B

व्याख्या

तरलता प्रबंधन पहल:

- केंद्रीय बैंक की 'तरलता प्रबंधन' पहल को कुछ विशिष्ट फ्रेमवर्क, उपकरणों के समूह और विशेष रूप से उन नियमों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा बैंक रिज़र्व की मात्रा को नियंत्रित कर कीमतों (यानी अल्पकालिक ब्याज दरों) को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है, जिसका अल्पकालिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना होता है।
  - बैंक रिज़र्व का आशय उस न्यूनतम राशि से हैं, जो वित्तीय संस्थानों के पास होनी अनिवार्य है।
- 'तरलता प्रबंधन' पहल रिज़र्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौतों (रेपो) के माध्यम से ऋण लेने या बैंकों को रिवर्स रेपो समझौतों के माध्यम से रिज़र्व बैंक को ऋण देने की अनुमति देता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - इस फ्रेमवर्क के तहत विभिन्न उपकरण हैं:
  - रेपो/रिवर्स रेपो नीलामी
  - सीमांत स्थायी सुविधा (MSF)
  - विदेशी मुद्रा स्वैप। अत: कथन 2 सही है

212.

उत्तर: B

व्याख्या

- राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (e-NAM) एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।
- इसे अप्रैल 2016 में भारत में कृषि वस्तुओं के लिये मौजूदा मंडियों को 'एक राष्ट्र एक बाज़ार' में एकीकृत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह कृषि उत्पादों के लिये एक एकीकृत राष्ट्रीय बाज़ार बनाने हेतु मौजूदा APMC (कृषि उपज बाज़ार कमोडिटीज़) मंडियों को एक नेटवर्क में एक साथ लाता है।
  - एकीकृत बाज़ारों में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके कृषि विपणन में एकरूपता को बढ़ावा देना।
  - खरीदारों एवं विक्रेताओं के बीच सूचना विषमता को दूर करना और वास्तविक मांग वआपूर्ति के आधार पर वास्तविक समय मूल्य की खोज को बढ़ावा देना।
  - अत: कथन 2 सही है।
- लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) इसे लागू करने वाली प्रमुख एजेंसी है। अत: कथन 3 सही है।
  - यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्त्वावधान में कार्य करता है।

213.

उत्तर: C

व्याख्या

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार करने के लिये प्रतिबद्ध हैं ताकि वे वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाने के मामले में सभी एक-दूसरे से कम टैरिफ, उच्चतम आयात तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये सबसे कम व्यापार बाधाओं से लाभान्वित हो सकें।
  - गैर-भेदभावपूर्ण के इस सिद्धांत को मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) के रूप में जाना जाता है।
  - यह उन उपायों में से एक है जो बिना किसी भेदभाव के व्यापार सुनिश्चित करता है तथा दूसरा 'राष्ट्रीय उपचार' है।
- टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT), 1994 के अनुच्छेद 1 के तहत विश्व व्यापार संगठन के प्रत्येक सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों को एमएफएन का दर्जा देने की आवश्यकता है।
- इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे- जब सदस्य द्विपक्षीय व्यापार समझौते करते हैं या जब सदस्य विकासशील देशों को अपने बाज़ारों में विशेष पहुँच प्रदान करते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- विश्व व्यापार संगठन से बाहर के देशों जैसे- ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया या बेलारूस के लिये विश्व व्यापार संगठन के सदस्य वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन किये बिना अपनी इच्छानुसार कोई भी व्यापार उपाय लागू कर सकते हैं।
- इसके अनुसार एमएफएन का दर्जा प्राप्त राष्ट्रों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और न ही किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में बुरा व्यवहार किया जाएगा। अत: कथन 2 सही है।
  - इसके तहत किसी उत्पाद पर विशेष सहायता प्रदान करनी होगी (जैसे कि उनके उत्पादों में से एक के लिये कम सीमा शुल्क दर) तथा अन्य सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को भी ऐसा ही करना होगा।

214.

उत्तर: D

व्याख्या:

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है, जो डिफॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज़ का अनुसूचित भुगतान बकाया होता है।
- अधिकतर मामलों में ऋण को गैर-निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिये न किया गया हो। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ वह राशि है जो सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से 'प्रोविज़न अमाउंट' की कटौती के बाद प्राप्त होती है।
  - अत: कथन 2 सही नहीं है।

215.

उत्तर: C

व्याख्या:

- पारा पर मिनामाता कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पारे तथा इसके यौगिकों के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने के लिये एक वैश्विक संधि है।
  - वर्ष 2013 में जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में अंतर-सरकारी वार्ता समिति के पाँचवें सत्र में इस पर सहमति प्रदान की गई थी।
- अपने पूरे जीवनचक्र में पारे के दुष्प्रभावो को नियंत्रित करना कन्वेंशन के प्रमुख दायित्वों में से एक है।
  - कन्वेंशन पारा के अंतरिम भंडारण तथा इसके अपशिष्ट के निपटान व दूषित स्थलों के साथ-साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को भी संबोधित करता है।
- कन्वेंशन में पारा के जीवन चक्र के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, जो उत्पादों, प्रक्रियाओं और उद्योगों की शृंखला में पारा को नियंत्रित व इसमें कमी करता है। इसमें निम्नलिखित पर नियंत्रण शामिल है:
  - पारा खनन।
  - पारा और पारा से संबंधित उत्पादों का निर्माण और व्यापार।
  - पारायुक्त कचरे का निपटान।
  - उद्योगो में पारे का उत्सर्जन।
- जिन देशों ने कन्वेंशन की पुष्टि की है, उन्हें इन नियंत्रणों को लागू करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत बाध्यकरी है।
  - भारत ने भी कन्वेंशन की पुष्टि की है।
- अत: विकल्प C सही है।

216.

उत्तर: D

व्याख्या:

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा है कि एक राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों द्वारा आयोजित लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। अत: कथन 1 सही है।
- न्यायालय ने पाया कि 'लॉटरी' एक 'जुआ गतिविधि' है।
  - 'सट्टेबाज़ी और जुआ' संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है।

- ऐसे में राज्य सरकार को उन सभी गतिविधियों पर कर अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त है, जो लॉटरी सहित 'सट्टेबाज़ी और जुए' की प्रकृति की हैं।
- सट्टेबाज़ी और जुआ एक प्रकार की व्यापक श्रेणी है जिसमें घुड़दौड़, व्हीलिंग व अन्य स्थानीय सट्टेबाज़ी एवं जुआ से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं।

- अदालत ने कहा कि चूँकि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि लॉटरी भारत सरकार या राज्य सरकार या राज्य द्वारा अधिकृत है या राज्य सरकार या केंद्र सरकार की किसी एजेंसी या संस्था या किसी निजी अभिकर्त्ता द्वारा संचालित व आयोजित 'सट्टा और जुआ' है तथा राज्य विधानसभाओं के पास राज्य सूची की प्रविष्टि 62 के तहत लॉटरी पर कर लगाने का अधिकार है। अत: कथन 2 सही है।
  - उक्त प्रविष्टि के तहत कराधान में सट्टेबाज़ी और जुआ जैसी गतिविधियों को शामिल किया जाता है जिसमें लॉटरी भी शामिल है, भले ही इनका संचालन किसी भी संस्था द्वारा किया जाता हो।
- वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लॉटरी, जुआ और सट्टेबाज़ी 'वस्तु एवं सेवा कर' (GST) अधिनियम, 2017 के तहत कर योग्य है। अत: कथन 3 सही है।

217.

उत्तर: A

व्याख्या:

- इस प्रकार के समझौते में दो या दो से अधिक भागीदार कुछ उत्पादों के संबंध में प्रवेश का अधिमान्य या तरजीही अधिकार देते हैं। यह टैरिफ लाइन्स की एक सहमत संख्या पर शुल्क को कम करके किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- यहाँ तक कि PTA में भी कुछ उत्पादों के लिये शुल्क को घटाकर शून्य किया जा सकता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक PTA पर हस्ताक्षर किये हैं।

218.

उत्तर: A

व्याख्या:

श्रृंकफ्लेशन:

- श्रृंकफ्लेशन किसी उत्पाद के स्टिकर मूल्य को बनाए रखते हुए उसके आकार को कम करने की पद्धति है।
  - यह छिपी हुई मुद्रास्फीति का एक रूप है।
- लाभांश को चुपके से बढ़ाने या इनपुट लागत में वृद्धि के सापेक्ष लाभ को बनाए रखने के लिये प्रति दी गई मात्रा के अनुसार कीमतों में वृद्धि करना (मुख्य रूप से खाद्य और पेय उद्योग में) कंपनियों द्वारा नियोजित एक रणनीति है।
- व्यवसाय एवं शैक्षणिक अनुसंधान में श्रृंकफ्लेशन को पैकेज डाउनसाइज़िंग (पैकेज के आकार को छोटा करना) के रूप में भी जाना जाता है।
- सामान्य रूप से बहुत कम प्रचलित यह शब्द समष्टि अर्थशास्त्र की उस स्थिति को संदर्भित कर सकता है जहाँ कीमत स्तर में वृद्धि का अनुभव करने के बावजूद अर्थव्यवस्था में संकुचन हो रहा है।
  - मैक्रोइकॉनॉमिक्स/समष्टि अर्थशास्त्र समग्र रूप से एक राष्ट्रीय या क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के व्यवहार का अध्ययन है।
  - यह अर्थव्यवस्था में व्याप्त घटनाओं जैसे- उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा, बेरोज़गारी के स्तर तथा कीमतों के सामान्य व्यवहार को समझने से संबंधित है।
- आजकल श्रृंकफ्लेशन उत्पादकों के बीच लोकप्रिय एक सामान्य अभ्यास है। डाउनसाइज़िंग से गुज़रने वाले उत्पादों की संख्या में प्रत्येक वर्ष वृद्धि होती है।
  - यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाज़ारों में बड़े उत्पादक मुनाफे को कम किये बिना अपने उत्पादों की प्रतिस्पर्द्धी कीमतों को बनाए रखने के लिये इस रणनीति पर भरोसा करते हैं।
- ऐसे समय में श्रृंकफ्लेशन के चलते ग्राहकों में निर्माता के ब्रांड के संबंध में प्राय: निराशा होती है और उपभोक्ता की भावना भी प्रभावित हो सकती है।
- अत: विकल्प A सही है।

219.

उत्तर: D

व्याख्या

एशियाई विकास बैंक:

- एशियाई विकास बैंक (ADB) एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर, 1966 को हुई थी। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- ADB में कुल 68 सदस्य शामिल हैंI भारत ADB का एक संस्थापक सदस्य है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया-प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से हैं।
- इसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
- 31 दिसंबर, 2019 तक ADB के पाँच सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका (प्रत्येक कुल शेयरों के 15.6% के साथ), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (6.4%), भारत (6.3%) एवं ऑस्ट्रेलिया (5.8%) शामिल हैं।
- ADB का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। अत: कथन 3 सही है।

220.

उत्तर: A

व्याख्या:

- भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (IFSC), एक अद्वितीय 11-अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड है जिसका उपयोग NEFT, RTGS और IMPS के माध्यम से किये गए ऑनलाइन फंड ट्रांसफर, लेन-देन हेतु किया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) विभिन्न बैंकों को IFSC कोड प्रदान करता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- यदि आप पैसे ट्रांसफर करने के लिये नेट बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं, तो ट्रांसफर शुरू करने के लिये IFSC दर्ज करना अनिवार्य है।
- प्रत्येक बैंक शाखा का एक विशिष्ट कोड होता है और कोई भी दो शाखाओं (एक ही बैंक की भी) का कोड समान नहीं होता है।
- जब तक विलय नहीं होता है, बैंक IFSC कोड को संशोधित या परिवर्तित नहीं कर सकते हैं।
- IFSC कोड प्रारूप: IFSC के पहले 4 अंक बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम 6 वर्ण शाखा का प्रतिनिधित्व करते हैं। पाँचवाँ वर्ण शून्य है।

221.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान करने हेतु गैर इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के फोन के लिये नई UPI सेवाएँ UPI123Pay शुरू की हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी पर उपयोगकर्ताओं को स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा 'डिजिसाथी' भी स्थापित किया गया है। अत: कथन 2 सही है।
  - वर्तमान में यह अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है।

222.

उत्तर C

व्याख्या

- एक देश का BoP खाता तैयार करने के लिये विश्व के अन्य हिस्सों के बीच इसके आर्थिक लेन-देन को चालू खाते, पूंजी खाते, वित्तीय खाते और त्रुटियों तथा चूक के तहत वर्गीकृत किया जाता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Exchange Reserve) में परिवर्तन को भी दर्शाता है।
- चालू खाता: यह दृश्यमान (जिसे व्यापारिक माल भी कहा जाता है- व्यापार संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है) और अदृश्यमान वस्तुओं (गैर-व्यापारिक माल भी कहा जाता है) के निर्यात तथा आयात को दर्शाता है।
  - अदृश्यमान में सेवाएँ, विप्रेषण और आय शामिल हैं।
  - अत: कथन 1 और 3 सही हैं।
- पूंजी खाता: यह किसी देश के पूंजीगत व्यय और आय को दर्शाता है।
  - यह एक अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों निवेश के शुद्ध प्रवाह का सार प्रदान करता है।
  - बाहरी वाणिज्यिक उधार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश आदि पूंजी खाते के हिस्से हैं।
- अत: कथन 2 सही नहीं है।
- त्रुटियाँ और चूक: कभी-कभी भुगतान संतुलन की स्थिति न होने के कारण इस असंतुलन को BoP में त्रुटियों और चूक (Errors and Omissions) के रूप में दिखाया जाता है। यह सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने में देश की अक्षमता को दर्शाता है।
- विदेशी मुद्रा भंडार में बदलाव: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा आस्तियों में बदलाव और विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights-SDR) बैलेंस में बदलाव के कारण भी होते हैं। अत: कथन 4 सही नहीं है।

223.

उत्तर: C

व्याख्या:

- स्विफ्ट विश्वसनीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की सुविधा प्रदान करता है जो वित्तीय संस्थानों को धन हस्तांतरण जैसे वैश्विक मौद्रिक लेन-देन के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अत: कथन 2 सही है।
- स्विफ्ट वास्तविक रूप से रुपए का लेन-देन नहीं करता है, यह 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवाएँ प्रदान करके लेन-देन की जानकारी को सत्यापित करने के लिये एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
  - अधिकांश विश्व व्यापार स्विफ्ट के माध्यम से वित्तीय संदेश भेजने के साथ होता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1973 में हुई थी तथा यह बेल्जियम में स्थित है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- यह बेल्जियम के अलावा कनाडा, फ्राँस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 11 औद्योगिक देशों के केंद्रीय बैंकों की देखरेख करता है।

- भारत की वित्तीय प्रणाली की पहुँच स्विफ्ट तक है। अत: कथन 3 सही है।
- स्विफ्ट से पहले अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिये संदेश पुष्टिकरण का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम टेलेक्स (Telex) था।
  - कम गति, सुरक्षा चिंताओं और एक मुफ्त संदेश प्रारूप जैसे कई मुद्दों के कारण इसे बंद कर दिया गया था।

224.

उत्तर: (a)

व्याख्या:

- मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दो या दो से अधिक देशों के बीच एक समझौता है। इसके तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात हेतु उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी आदि को सरल बनाया जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA), साझेदारी समझौता या सहयोग समझौता एफटीए की तुलना में अधिक व्यापक है।
  - CEPA के अंतर्गत सेवाओं और निवेश तथा आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में व्यापार संबंधी बातचीत शामिल है। अत: युग्म 2 सही सुमेलित नहीं है।
- एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) में आमतौर पर केवल व्यापार शुल्क और TRQ (टैरिफ दर कोटा) दरों पर बातचीत शामिल है। यह CEPA जितना व्यापक नहीं है। अत: युग्म 3 सुमेलित नहीं है।
- अत: विकल्प (a) सही है।

225.

उत्तर: D

व्याख्या:

'फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स' (FATF):

- FATF का गठन वर्ष 1989 में जी-7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक में हुआ था।
- FATF मनी लांड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिये आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करने का काम करता है। यह व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है।
- उद्देश्य:
  - FATF का उद्देश्य मनी लॉड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण जैसे खतरों से निपटना और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिये अन्य कानूनी, विनियामक एवं परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। अत: कथन 1 सही है।
- मुख्यालय:
  - इसका सचिवालय पेरिस स्थित आर्थिक सहयोग विकास संगठन (OECD) के मुख्यालय में स्थित है। अत: कथन 2 सही है।
- सदस्य देश:
  - वर्तमान में FATF में भारत समेत 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं। भारत वर्ष 2010 से FATF का सदस्य है। अत: कथन 3 सही है।

226.

उत्तर: B

व्याख्या:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने डिजिटल भुगतान करने हेतु गैर इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं के फोन के लिये नई UPI सेवाएँ UPI123Pay शुरू की हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं से संबंधित जानकारी पर उपयोगकर्ताओं को स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा 'डिजिसाथी' भी स्थापित किया गया है। अत: कथन 2 सही है।
  - वर्तमान में यह अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा में उपलब्ध है।

227.

उत्तर: D

व्याख्या:

- इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ETPBS) के तहत डाक मतपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत सेवा मतदाताओं को भेजा जाता है। अत: कथन 1 सही है।
- सेवा मतदाताओं को ETPBS का उपयोग करने की अनुमति देने हेतु चुनाव आचरण नियम, 1961 में वर्ष 2016 में संशोधन किया गया था। अत: कथन 2 सही है।
- सेवा मतदाता तब ETPB (घोषणा पत्र एवं कवर के साथ) डाउनलोड कर सकते हैं, मतपत्र पर अपना जनादेश दर्ज कर सकते हैं और इसे सामान्य मेल के माध्यम से निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को भेज सकते हैं।
- इस पोस्ट में एक सत्यापित घोषणा पत्र शामिल होता है (मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद एक नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में जो इसे सत्यापित करेगा)।

228.

उत्तर: C

व्याख्या:

- InTranSE का पूरा नाम इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर है।

- इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (ITS) एक क्रांतिकारी अत्याधुनिक तकनीक है।
- यह कुशल बुनियादी ढाँचे के उपयोग को बढ़ावा देकर यातायात की समस्याओं को कम कर यातायात में दक्षता को बढ़ाएगा, ताकि यात्रा में लगने वाले समय को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा एवं यात्रा को आरामदायक बनाने के लिये यातायात के पूर्व उपयोगकर्त्ताओं को जानकारी से समृद्ध किया जा सकेगा।
- यह प्रणाली किसी भी दुर्घटना का पता लगा सकती है, साथ ही अलर्ट कर सकती है ताकि एक एम्बुलेंस 10-15 मिनट के भीतर दुर्घटना स्थल पर पहुँच सके।
- अत: विकल्प C सही है।

229.

उत्तर: C

व्याख्या:

कॉयर जियो टेक्सटाइल:

- कॉयर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेशेदार पदार्थ है जो नारियल के खोल के बाहर पाया जाता है जिसे प्राकृतिक रूप से उपयोग के लिये संसाधित किया जाता है।
- कॉयर जियो टेक्सटाइल प्राकृतिक रूप से सड़न, गलन और नमी के लिये प्रतिरोधी हैं और किसी भी माइक्रोबियल हमले से मुक्त होते हैं। अत: कथन 1 सही है।
- ये उच्च स्थायित्व के साथ पारगम्य, प्राकृतिक और मज़बूत कपड़े हैं। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- यह पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है और मिट्टी को स्थिर करने में मदद करता है। अत: कथन 3 सही है।

230.

उत्तर:B

व्याख्या:

- 'अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ सम्मेलन 2022' का आयोजन संयुक्त रूप से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (FICCI) द्वारा किया गया है।अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इस सम्मेलन का लक्ष्य भारत को एक क्रूज़ केंद्र के रूप में बढ़ावा देना है, साथ ही नीतिगत पहलों को बढ़ावा देकर बंदरगाहों को सुविधाओं से सक्षम करना एवं नदी क्रूज़ पर्यटन की क्षमता का विकास करना है। अत: कथन 2 सही है।

अत: विकल्प B सही है।

231.

उत्तर: C

व्याख्या

'इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन' (IOSCO) के विषय में:

- स्थापना: अप्रैल, 1983
- मुख्यालय: मेड्रिड, स्पेन
  - IOSCO एशिया प्रशांत हब मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है।
- परिचय:
  - यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के प्रतिभूति नियामकों को एकीकृत करने के साथ ही दुनिया के 95% से अधिक प्रतिभूति बाज़ारों को कवर करता है और प्रतिभूति क्षेत्र के लिये वैश्विक मानक सेंटर है। अत: कथन 1 सही है।
  - यह प्रतिभूति बाज़ारों की मज़बूती के लिये मानकों को स्थापित करने में G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (FSB) के साथ मिलकर काम करता है।
  - IOSCO बोर्ड 32 प्रतिभूति नियामकों से बना है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) इसके बोर्ड के सदस्यों में से एक है। अत: कथन 2 सही है।

232.

उत्तर: B

व्याख्या:

- EPCG योजना वर्ष 1990 के दशक में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा हेतु शुरू की गई थी, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि हुई है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- इस योजना के तहत निर्माता बिना किसी सीमा शुल्क को आकर्षित किये, उत्पादन से पहले, उत्पादन के समय तथा उत्पादन के बाद वस्तुओं के लिये पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। अत: कथन 2 सही है।
  - EPCG योजना के तहत बिना किसी प्रतिबंध के पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का भी आयात किया जा सकता है।
- पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क के दायित्व का भुगतान करने में छूट प्रदान करने वाली यह योजना प्राधिकरण जारी होने की तारीख से 6 वर्षों के भीतर ऐसे पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर बचाए गए शुल्क के 6 गुना के निर्यात मूल्य के बराबर होता है।

233.

उत्तर: A

व्याख्या:

- इसे वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक (IBRD) के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में IBRD को ही विश्व बैंक के रूप में जाना गया।
  - विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले स्थायी समाधानों के लिये काम कर रहे पाँच संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है।
- सदस्य: इसके 189 सदस्य देश हैं। भारत भी एक सदस्य देश है।
  - प्रमुख रिपोर्ट
  - ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस। (हाल ही में प्रकाशित करना बंद कर दिया)।
  - ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स।
  - वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट।
  - पाँच विकास संस्थान:
  - अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD)
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA)
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC)
  - बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA)
  - निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)
  - भारत इसका सदस्य नहीं है।
- अत: विकल्प A सही है।

234.

उत्तर: B

व्याख्या:

- हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (India Post Payments Bank- IPPB) द्वारा फिनक्लुवेशन प्लेटफॉर्म (Fincluvation Platform) को लॉन्च किया गया है, ताकि फिनटेक स्टार्टअप्स के सहयोग से अभिनव उपायों को बढ़ावा दिया जा सके और वंचित तथा सेवाओं तक पहुँच वाली आबादी के बीच वित्तीय समावेशन में तेज़ी लाई जा सके।
- फिनक्लुवेशन, भाग लेने वाले स्टार्टअप के साथ समावेशी वित्तीय समाधान उपलब्ध कराने हेतु IPPB का एक स्थायी मंच होगा। अत: कथन 1 और कथन 2 सही हैं।
- वित्तीय समावेशन के लिये लक्षित सार्थक वित्तीय उत्पादों के निर्माण की दिशा में स्टार्टअप्स समुदाय को प्रोत्साहित करने हेतु एक शक्तिशाली मंच की स्थापना करने की यह उद्योग की प्रथम पहल है।
- स्टार्टअप्स को निम्नलिखित ट्रैक्स के साथ संरेखित समाधान विकसित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है:
  - क्रेडिटाइज़ेशन- लक्षित ग्राहकों के साथ संयोजित नवोन्मेषी तथा समावेशी क्रेडिट उत्पादों का विकास करना एवं उन्हें डाक नेटवर्क के माध्यम से उनके द्वार तक पहुँचाना।
  - डिजिटाइज़ेशन- डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकियों के साथ पारंपरिक सेवाओं के समन्वयन के माध्यम से सुविधा प्रदान करना, उदाहरण के लिये अंत: पारस्परिक बैंकिंग सेवा के रूप में पारंपरिक मनीऑर्डर सेवा उपलब्ध कराना।
  - बाज़ार आधारित समाधान- बाज़ार आधारित कोई भी समाधान जो लक्षित ग्राहकों की सेवा करने में आईपीपीबी (IPPB) और/या डाक विभाग से संबंधित किसी अन्य समस्या का समाधान करने में सहायता कर सकती है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

235.

उत्तर: A

व्याख्या:

- एक विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी (SPAC) इनिशियल पब्लिक ऑफ के माध्यम से निवेश हेतु पूंजी जुटाने के एकमात्र उद्देश्य के लिये बनाया गया एक निगम है। अत: कथन 1 सही है।
- उनके आईपीओ के समय SPAC के पास कोई मौजूदा व्यवसाय संचालन या अधिग्रहण के लिये कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- इस तरह की व्यावसायिक संरचना निवेशकों को फंड हेतु धन का उपयोग करने की अनुमति देती है जिसका उपयोग आईपीओ के बाद पहचाने जाने वाले एक या अधिक अनिर्दिष्ट व्यवसायों हेतु किया जाता है।
  - इसलिये इस प्रकार की शेल फर्म संरचना को लोकप्रिय मीडिया में अक्सर "ब्लैंक-चेक कंपनी" कहा जाता है।
  - एक बार जब जनता से पैसा जुटा लिया जाता है तो इसे एस्क्रो खाते में रखा जाता है जिसे अधिग्रहण करते समय एक्सेस किया जा सकता है।
  - यदि आईपीओ के दो साल के भीतर अधिग्रहण नहीं किया जाता है, तो SPAC को हटा दिया जाता है और पैसा निवेशकों को वापस कर दिया जाता है।

236.

उत्तर: D

व्याख्या:

बेरोज़गारी के प्रकार:

- प्रच्छन्न बेरोजगारी: यह एक ऐसी घटना है जिसमें वास्तव में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोज़गार दिया जाता है।
  - यह मुख्य रूप से भारत के कृषि और असंगठित क्षेत्रों में पाई जाती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- मौसमी बेरोज़गारी: यह एक प्रकार की बेरोज़गारी है, जो वर्ष के कुछ निश्चित मौसमों के दौरान देखी जाती है।
  - भारत में खेतिहर मज़दूरों के पास वर्ष भर काफी कम काम होता है।
- संरचनात्मक बेरोज़गारी: यह बाज़ार में उपलब्ध नौकरियों और श्रमिकों के कौशल के बीच असंतुलन होने से उत्पन्न बेरोज़गारी की एक श्रेणी है।
  - भारत में बहुत से लोगों को आवश्यक कौशल की कमी के कारण नौकरी नहीं मिलती है और शिक्षा के खराब स्तर के कारण उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल हो जाता है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- चक्रीय बेरोज़गारी: यह व्यापार चक्र का परिणाम है, जहाँ मंदी के दौरान बेरोज़गारी बढ़ती है और आर्थिक विकास के साथ घटती है।
  - भारत में चक्रीय बेरोज़गारी के आँकड़े नगण्य हैं। यह एक ऐसी घटना है जो अधिकतर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पाई जाती है।
- तकनीकी बेरोज़गारी: यह प्रौद्योगिकी में बदलाव के कारण नौकरियों का नुकसान है।
  - वर्ष 2016 में विश्व बैंक के आँकड़ों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत में ऑटोमेशन से खतरे में पड़ी नौकरियों का अनुपात साल-दर-साल 69% है।
- घर्षण बेरोज़गारी: घर्षण बेरोज़गारी का आशय ऐसी स्थिति से है, जब कोई व्यक्ति नई नौकरी की तलाश कर रहा होता है या नौकरियों के बीच स्विच कर रहा होता है, तो यह नौकरियों के बीच समय अंतराल को संदर्भित करता है।
- सुभेद्य रोज़गार: इसका मतलब है कि लोग बिना उचित नौकरी अनुबंध के अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं और इस प्रकार इनके लिये कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है।
- इन व्यक्तियों को 'बेरोज़गार' माना जाता है क्योंकि उनके कार्य का रिकॉर्ड कभी भी बनाया नहीं जाता हैं।
- यह भारत में बेरोज़गारी के मुख्य प्रकारों में से एक है।

237.

उत्तर: D

व्याख्या:

- पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा कीमतें मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बनी होती हैं:
  - आधार मूल्य (अंतर्राष्ट्रीय तेल की लागत को दर्शाता है)
  - केंद्रीय उत्पाद शुल्क
  - राज्य कर (वैट)
- भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमत का एक बड़ा हिस्सा केंद्रीय और राज्य कर है।
- उत्पाद शुल्क पूरे भारत में एक समान है, राज्य कर (बिक्री कर और मूल्यवर्द्धित कर) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए दरों के आधार पर भिन्न होते हैं।
  - ये कर उपभोक्ताओं के लिये ईंधन को और भी महंगा बनाते हैं।
- अत: विकल्प D सही है।

238.

उत्तर: C

व्याख्या:

- हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने मुद्रा और वित्त (RCF) पर रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से हुए नुकसान से उबरने में एक दशक से अधिक समय लग सकता है।
- रिपोर्ट का विषय "रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट" है, जो कोविड से मज़बूती से उबरने और मध्यम अवधि में वृद्धि को बढ़ाने के संदर्भ में है।
- अत: विकल्प B सही है।

239.

उत्तर: D

व्याख्या:

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है जिनमें से प्रत्येक देश का इसके वित्तीय महत्त्व के अनुपात में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी बोर्ड में प्रतिनिधित्व हैं। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था में जो देश अधिक शक्तिशाली है उस देश के पास अधिक मताधिकार है।
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के 'न्यू हैम्पशायर' में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी।

- उक्त सम्मेलन में 44 देशों नें एक साथ मिलकर आर्थिक-सहयोग हेतु एक फ्रेमवर्क के निर्माण की बात की ताकि प्रतिस्पर्द्धा अवमूल्यन की पुनरावृत्ति से बचा जा सके जिसके कारण वर्ष 1930 के दशक में आए विश्वव्यापी महामंदी जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी।
- जब तक कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं बनता, तब तक उसे विश्व बैंक की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (International Bank for Reconstruction and Development-IBRD) में सदस्यता नहीं मिलती है। अत: कथन 1 सही है।
  - अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) और बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (MIGA) में सदस्यता आईबीआरडी में सदस्यता पर सशर्त है।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रेटन वुड्स समझौते के अनुसार, आईएमएफ ने निश्चित विनिमय दरों पर परिवर्तनीय मुद्राओं की एक प्रणाली शुरू की, और आधिकारिक रिजर्व के लिए अमेरिकी डॉलर (सोना $35 प्रति औंस पर) के साथ सोने को बदल दिया। अत: कथन 2 सही है।
  - वर्ष 1971 में ब्रेटन वुड्स प्रणाली (स्थिर विनिमय दरों की प्रणाली) के समाप्त होने के बाद, आईएमएफ ने अस्थायी विनिमय दरों की प्रणाली को बढ़ावा दिया।

240.

उत्तर: A

व्याख्या:

मौद्रिक नीति समिति:

- यह विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत एक सांविधिक और संस्थागत ढाँचा है।
- RBI का गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।अत: कथन 1 सही है।
- MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य (4%) को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीतिगत ब्याज दर (रेपो दर) निर्धारित करती है।
- वर्ष 2014 में तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में RBI द्वारा गठित समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी। अत: कथन 2 सही नहीं है।

241.

उत्तर: D

व्याख्या:

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI):

- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment- FPI) में विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी गई प्रतिभूतियाँ और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं। यह निवेशक को वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष स्वामित्व प्रदान नहीं करता तथा बाज़ार की अस्थिरता के आधार पर अपेक्षाकृत तरल होती हैं। अत: कथन 1 सही है।
  - FPI के उदाहरणों में स्टॉक, बॉण्ड, म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स , अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (ADRs) और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स (GDRs) शामिल हैं।
- FPI किसी देश के पूंजी खाते का हिस्सा होता है और इसके भुगतान संतुलन (Balance of Payments- BOP) में दर्शाया जाता है।
  - BOP एक मौद्रिक वर्ष में एक देश से दूसरे देशों में होने वाले धन के प्रवाह की मात्रा को मापता है।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा वर्ष 2014 के पूर्ववर्ती FPI विनियमों के स्थान पर नया एफपीआई विनियम, 2019 लागू किया गया।
- FPI को अक्सर "हॉट मनी" के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि यह अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति में सबसे पहले भागने वाले संकेतों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एफपीआई अधिक तरल और अस्थिर होता है, इसलिये यह FDI की तुलना में अधिक जोखिमभरा है। अत: कथन 2 सही है।

242.

उत्तर: A

व्याख्या:

- क्रिप्टोकरेंसी जिसे कभी-कभी क्रिप्टो-मुद्रा या क्रिप्टो कहा जाता है, मुद्रा का एक रूप है जो डिजिटल या आभासी रूप में पाई जाती है तथा लेन-देन को सुरक्षित करने के लिये क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है। अत: कथन 1 सही है।
- क्रिप्टोकरेंसी में मुद्रा जारी करने या विनियमित करने वाला कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है। यह लेन-देन को रिकॉर्ड करने और नई इकाइयों को जारी करने के लिये विकेंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग करती है।
  - यह एक विकेंद्रीकृत पीयर-टू-पीयर नेटवर्क द्वारा संचालित होता है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

243.

उत्तर: B

व्याख्या:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के लिये अधिकांश वित्तपोषण अतिरिक्त बजटीय योगदान से आता है, जो स्वैच्छिक प्रकृति के होते हैं और इन्हें सामान्य रूप से निर्धारित किया

जाता है। WHO को इन फंडों के उपयोग में बहुत कम लचीलापन प्राप्त है। अत: कथन 1 सही है।

- अंतर्राष्ट्रीय चिंता संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (Public Health Emergency of International Concern- PHEIC) घोषणा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना:
  - PHEIC की घोषणा करने के लिये स्पष्ट मापदंडों के साथ वस्तुनिष्ठ मानदंड तैयार करने की आवश्यता है।
  - घोषणा प्रक्रिया में पारदर्शिता और तत्परता पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।
  - PHEIC का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जो:
  - गंभीर, अचानक, असामान्य या अप्रत्याशित हो।
  - प्रभावित राज्य की राष्ट्रीय सीमा से परे सार्वजनिक स्वास्थ्य के निहितार्थ हो।
  - जिसमें तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता हो। अत: कथन 2 सही है।

244.

उत्तर: C

व्याख्या:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF):

- परिचय:
- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व बैंक के साथ IMF की स्थापना युद्ध से तबाह देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिये की गई थी।
- अमेरिका में ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन के दौरान इन दोनों संगठनों की स्थापना पर सहमति बनी। इसलिये,इन्हें ब्रेटन वुड्स जुड़वां के रूप में जाना जाता है।
- IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, यह उन 190 देशों द्वारा शासित और उनके प्रति जवाबदेह है जो इसके वैश्विक सदस्य हैं। भारत ने 27 दिसंबर, 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की। अत:कथन 2 सही नहीं है।
- IMF का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है, यह विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की प्रणाली है जो देशों (तथा उनके नागरिकों) को एक-दूसरे के साथ लेन-देन करने में सक्षम बनाती है।अत: कथन 1 सही है।
- वर्ष 2012 में एक कोष के जनादेश के अंतर्गत वैश्विक स्थिरता से संबंधित सभी व्यापक आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों को शामिल करने के लिये इसको अद्यतित किया गया।
- IMF द्वारा प्रकाशित की जाने वाली रिपोर्ट:
  - वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
  - विश्व आर्थिक आउटलुक । अत: कथन 3 सही है। अत: विकल्प C सही है।

245.

उत्तर: D

व्याख्या:

- SDR न तो मुद्रा है और न ही IMF पर दावा बल्कि यह आईएमएफ के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। इन मुद्राओं के एवज में एसडीआर का आदान-प्रदान किया जा सकता है।
- मुद्राओं की SDR बास्केट में यूएस डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग एवं चीनी रॅन्मिन्बी (वर्ष 2016 में) शामिल हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- SDR मुद्रा के मूल्यों का दैनिक मूल्यांकन (अवकाश को छोड़कर या जिस दिन IMF व्यावसायिक गतिविधियों के लिये बंद हो) होता है एवं मूल्यांकन बास्केट की समीक्षा तथा इसका समायोजन प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। कोटा (Quotas) को SDRs में इंगित किया गया है। अत: कथन 2 सही नहीं है।

246.

उत्तर: B

व्याख्या:

विश्व आर्थिक मंच:

  - विश्व आर्थिक मंच (WEF) एक गैर-लाभकारी स्विस संस्थान है जिसकी स्थापना वर्ष 1971 में जिनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में हुई थी।
  - स्विस सरकार द्वारा इसे सार्वजनिक-निजी सहयोग के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।
  - WEF वैश्विक, क्षेत्रीय और उद्योग जगत की परियोजनाओं को आकार देने हेतु व्यापार, राजनीतिक, शिक्षा क्षेत्र और समाज के अन्य प्रतिनिधियों को शामिल करके विश्व की स्थिति में सुधार के लिये प्रतिबद्ध है।
- संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष: क्लॉस श्वाब (Klaus Schwab)।
- WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
  - ऊर्जा संक्रमण सूचकांक (Energy Transition Index- ETI)
  - वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (Global Competitiveness Report)
  - वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट (Global IT Report)
  - WEF द्वारा INSEAD और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है।

- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट (Global Gender Gap Report)
- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट (Global Risk Report)
- वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट (Global Travel and Tourism Report)

- विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है और विश्व आर्थिक आउटलुक को आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है।

अत: विकल्प B सही है।

247.

उत्तर:B

व्याख्या:

- वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) पर कानून बनाने के लिये संघ और राज्य विधानसभाओं के पास "एक समान और अद्वितीय शक्तियाँ" हैं। अत: कथन 1 सही है।
- GST परिषद की सिफारिशें संघ और राज्यों को शामिल करते हुए एक सहयोगी संवाद का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ये सिफारिशें प्रकृति में अनुशंसात्मक होती हैं। ये सिफारिशें केवल प्रेरक मूल्य की होती हैं अर्थात् संघ और राज्यों दोनों को GST पर कानून बनाने की समान शक्ति प्रदान की जाती है, अत: इन कानूनों को बाध्यकारी मानने से राजकोषीय संघवाद बाधित होगा। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि माल आयात के मामले में भुगतान किये गए समुद्री माल पर GST असंवैधानिक है। अत: कथन 3 सही नहीं है।

248.

उत्तर: B

व्याख्या:

- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने उत्तर प्रदेश के एक गाँव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की थी। अत: कथन 1 सही है।
- खाद्य और कृषि संगठन के डेटाबेस के अनुसार, वर्ष 2017-18 में भारत शहद उत्पादन (64.9 हज़ार टन) के मामले में दुनिया में आठवें स्थान पर था।
- KVIC सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक संबद्ध संस्था है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
- हनी मिशन पहल KVIC से जुड़ी हुई है।

249.

उत्तर: C

व्याख्या:

- अक्तूबर 2021 तक भारत 9.8 मीट्रिक टन के उत्पादन के साथ कच्चे इस्पात का दुनिया में "दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक" था। अत: कथन 2 सही है।
  - वित्तीय वर्ष 2022 (जनवरी तक) में कच्चे इस्पात और तैयार इस्पात का उत्पादन क्रमश: 98.39 मीट्रिक टन एवं 92.82 मीट्रिक टन था।
- भारत में खनन में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- अप्रैल 2021 के दौरान भारत के आयात में प्रमुख देशों की हिस्सेदारी - दक्षिण कोरिया- 39%, जापान-19%, चीन- 17%, ताइवान- 4%, वियतनाम- 3% आदि। अत: कथन 3 सही है।

अत: विकल्प C सही है।

250.

उत्तर: C

व्याख्या:

- प्रेषण से आशय प्रवासी कामगारों द्वारा धन अथवा वस्तु के रूप में अपने मूल समुदाय/परिवार को भेजी जाने वाली आय से है। अत: कथन 1 सही है।
- यह मूल रूप से दो मुख्य घटकों का योग है- निवासी और अनिवासी परिवारों के मध्य नकद या वस्तु के रूप में व्यक्तिगत स्थानांतरण तथा कर्मचारियों का मुआवज़ा, यह उन श्रमिकों की आय को संदर्भित करता है जो सीमित समय के लिये दूसरे देश में काम करते हैं। अत: कथन 2 सही है।
- प्रेषण प्राप्तकर्त्ता देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में सहायता करते हैं, लेकिन यह ऐसे देशों को प्रेषण अर्थव्यवस्था पर अधिक निर्भर भी बना सकता है।

अत: विकल्प C सही है।

251.

उत्तर: C

व्याख्या:

अवमूल्यन:

- अवमूल्यन के बारे में:
  - मुद्रा का मूल्यह्रास/अवमूल्यन का आशय अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा के मूल्य में गिरावट से है। अत: कथन 1 सही नहीं है।
  - रुपए के मूल्यह्रास का मतलब है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का कमज़ोर होना।
  - इसका मतलब है कि रुपया अब पहले की तुलना में कमज़ोर है।

- उदाहरण के लिये पहले एक अमेरिकी डॉलर 70 रुपए के बराबर हुआ करता था। अब एक अमेरिकी डॉलर 77 रुपए के बराबर है जिसका अर्थ है कि डॉलर के मुकाबले रुपए का अवमूल्यन हुआ है यानी एक डॉलर को खरीदने में अधिक रुपए लगते हैं।

- भारतीय रुपए के अवमूल्यन का प्रभाव:
  - रुपए में गिरावट भारतीय रिज़र्व बैंक के लिये एक दोधारी तलवार (नकारात्मक एवं सकारात्मक) की भाँति होती है।
  - सकारात्मक प्रभाव:
  - सैद्धांतिक रूप से कमज़ोर रुपए को भारत के निर्यात को बढ़ावा देना चाहिये, लेकिन अनिश्चितता और कमज़ोर वैश्विक मांग के माहौल में रुपए के बाहरी मूल्य में गिरावट उच्च निर्यात में परिवर्तित नहीं हो सकती है। अत: कथन 2 सही है।
  - नकारात्मक प्रभाव:
  - यह आयातित मुद्रास्फीति का जोखिम उत्पन्न करता है और केंद्रीय बैंक के लिये ब्याज दरों को रिकॉर्ड स्तर पर लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल बना सकता है। अत: कथन 3 सही है।
  - भारत अपनी घरेलू तेल आवश्यकता के दो-तिहाई से अधिक की पूर्ति आयात के माध्यम से करता है।
  - भारत खाद्य तेलों के शीर्ष आयातक देशों में से एक है। एक कमज़ोर मुद्रा आयातित खाद्य तेल की कीमतों को और अधिक बढ़ाएगी तथा उच्च खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ावा देगी।

252.

उत्तर: B

व्याख्या:

पीएम फॉर्मलाइज़ेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज़ेज़:

- इसे आत्मनिर्भर अभियान (वर्ष 2020) के तहत शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना तथा किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों एवं उत्पादक सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करना है।
  - यह योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं और उत्पादों के विपणन के संबंध में पैमाने का लाभ उठाने के लिये एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) दृष्टिकोण अपनाती है।.
- इसे पाँच वर्ष (2020-21 से 2024-25) की अवधि के लिये लागू किया जाएगा।
  - यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है।
- इस योजना के तहत परिव्यय को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा किया जाएगा। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के साथ 90:10 के अनुपात में, विधायिका वाले केंद्रशासित प्रदेशों के साथ 60:40 के अनुपात में और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिये केंद्र द्वारा शतप्रतिशत व्यय किया जाएगा। अत: कथन 1 सही नहीं है।
- प्रारंभिक वित्तपोषण के तहत कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद के लिये 40,000 रुपए प्रति स्वयं सहायता समूह (SHG) सदस्य को प्रदान किये जाएंगे। अत: कथन 2 सही है।